हिंडनबर्ग रिपोर्टः
अदाणी की अग्नि परीक्षा

जीविका दीदियों की आमदनी
इकन्नी, जिम्मेदारी सोलह आना

पूर्वोत्तर में चुनावः
भाजपा की बड़ी चुनौती

15 फरवरी, 2023 50 रुपए

इंडिया टुडे

"दुआ में याद रखना"

बजट 2023

रोजगार को जबरदस्त बढ़ावा

मोदी सरकार वित्तीय सूझबूझ बरकरार रखते हुए बेरोजगारी कम करने के लिए प्रमुख सेक्टरों में झोंकेगी मोटा पैसा.
अब योजनाओं को अमली जामा पहनाने का इंतजार

RNI NO. 45823/86 REGISTRATION NO. DL(DS)-02/MP/2022-23-24, DL(ND)-11/6042/2021-22-2023; LICENSED TO POST WPP NO U(C)-31/2021-23; FARIDABAD/46/2023-25 www.indiatodayhindi.in

अग्रिम सप्ताह के लिए प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित; एलपीसी दिल्ली-आरएमएस-दिल्ली-110006 से प्रत्येक शनिवार और सोमवार को प्रेषित; कुल पन्नों की संख्या 54 (आवरण सहित) वर्ष 37; अंक: 11

असीमित अवसर

बेहतर परिवेश

उत्तर प्रदेश में करें निवेश

'एक्सप्रेस प्रदेश'
6 एक्सप्रेसवे
5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट

ग्लोबल डेटा सेंटर,
एजुकेशन व मेडिकल हब
बनने की ओर अग्रसर

5 शहरों में
मेट्रो संचालित एवं
5 शहरों में निर्माणाधीन/प्रस्तावित

25
निवेश फ्रेंडली
नीतियां

सर्वाधिक
उपभोक्ताओं वाला
प्रदेश

इंडस्ट्रियल
लैण्ड बैंक

सर्वाधिक
एम.एस.एम.ई.
इकाइयां

'ईज ऑफ डूइंग
बिजनेस'
रैंकिंग में अग्रणी

निर्बाध
विद्युत आपूर्ति

सिंगल विंडो
पोर्टल
'निवेश मित्र'

खाद्यान्न, दुग्ध, चीनी,
आलू व एथनॉल
उत्पादन में देश में प्रथम

प्रचुर
जल संसाधन

दुआ में याद रखना

UP GLOBAL INVESTORS SUMMIT
10-12 FEBRUARY, 2023 | LUCKNOW

समिट में प्रतिभाग करने के लिए
https://invest.up.gov.in/investorcrm/event/event_registration
पर रजिस्टर करें या कार्यक्रम स्थल यूपीजीआईएस ग्राउंड, सेक्टर-15, वृन्दावन योजना, लखनऊ पर पूर्वाह्न 11:00 से सायं 06:00 बजे तक रजिस्ट्रेशन कराएं.

File your Investment here

हेल्पडेस्क नंबर
70809 99210, 70809 99259
80902 54483, 80902 54484

upgis2023@investup.org.in

सहभागी देश

यूनाइटेड किंगडम | जापान | दक्षिण कोरिया | नीदरलैंड | सिंगापुर | मॉरीशस | डेनमार्क | ऑस्ट्रेलिया | संयुक्त अरब अमीरात | इटली

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

नए भारत का

"दुआ में याद रखना"

ग्रोथ इंजन

आपके बिजनेस को देगा नयी रफ़्तार

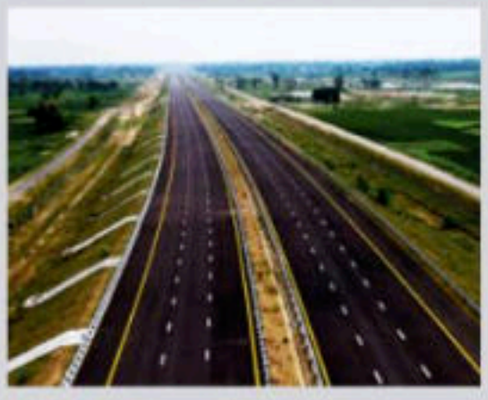

एक्सप्रेस प्रदेश

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट

डेटा सेंटर हब

डिफेंस कॉरिडोर

फिल्म सिटी

इन्वेस्ट यूपी

इंडिया टुडे

देश की भाषा में देश की धड़कन

INDIA TODAY GROUP

सबसे भरोसेमंद स्रोतों से, सबसे सटीक जानकारी

सब्सक्राइब करें और पाएं 21% तक की छूट

"हमें याद रखना"

हां! मैं इंडिया टुडे को सब्सक्राइब करना चाहता/चाहती हूँ

अपनी पसंद के सब्सक्रिप्शन को टिक करें और फॉर्म को इस पते पर भेज दें– वी केअर, लिविंग मीडिया इंडिया लि. सी–9, सेक्टर–10, नोएडा 201302 (भारत)

टिक करें	अवधि	कुल अंक	कवर प्राइस (₹)	ऑफर प्राइस (₹)	डिस्काउंट
☐	2 वर्ष	104	~~5200~~	4099	21%
☐	1 वर्ष	52	~~2600~~	2199	15%

कृपया फॉर्म को ब्लॉक लेटर में भरें

मैं चेक/डीडी जमा कर रहा/रही हूँ जिसकी संख्या.....है और इसे दिनांक..... को लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड के पक्ष में ..... (बैंक का नाम).....रुपये की धनराशि (दिल्ली से बाहर के चेक के लिए ₹ 50 रुपये अतिरिक्त जोड़ें, समान मूल्य के चेक मान्य नहीं होंगे) के लिए बनवाया गया है.

नाम..... पता.....

..... शहर..... राज्य..... पिन.....

मोबाइल..... ईमेल.....

सब्सक्राइब करने के लिए यहां स्कैन करें.

ऑफर के विषय में विशेष जानकारी के लिए निम्न माध्यमों से संपर्क भी कर सकते हैं

हमारे टॉल फ्री नंबर पर कॉल करें 18001800100

ईमेल भेजें wecare@intoday.com

लॉग ऑन करें subscriptions.intoday.in/indiatoday-hindi

Whatsapp"Hi" to +91 8597778778

लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड इस ऑफर या इसके अंश को कभी भी समाप्त करने या आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है. अन्य नियम व शर्तों की जानकारी के लिए कृपया देखें-www.indiatoday.in

प्रधान संपादक की कलम से

हर अर्थव्यवस्था में रोजगार और महंगाई दो अहम कारक होते हैं. भारत में महंगाई का मामला भारतीय रिजर्व बैंक देखता है. फिर भी सरकार मुफ्त खाद्यान्न बांटने सरीखे कल्याणकारी उपायों के जरिए महंगाई के असर को हल्का कर सकती है. जहां तक रोजगार तथा नौकरियों की बात है, सरकार पूंजीगत खर्च के जरिए रोजगार सृजन को बढ़ावा दे सकती है. इससे सुखद घटनाओं का चक्र बन सकता है. बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं पर सरकारी खर्च से उनके निर्माण के दौरान रोजगार सृजन होता है और उनके लिए आपूर्ति करने वाले तमाम उद्योगों में नौकरियों पर बहुगुणक प्रभाव पड़ता है. इन उद्योगों की क्षमता ज्यों-ज्यों बढ़ती है, वे अपना विस्तार करते हैं और निजी निवेश आने लगता है. इससे और नौकरियों का सृजन होता है. नौकरियों का मतलब है आमदनी, जिसका नतीजा समूची अर्थव्यवस्था में खपत की शक्ल में सामने आता है.

मोदी सरकार लगातार अपने बजटों में इसी पर दांव लगाती रही है. संसद में 2023 का बजट पेश करने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे ''खूबसूरत संतुलन'' कहा. जो यह सचमुच था. झटका और चौंकाने के अपने शुरुआती रुझान से मोदी सरकार दूरदर्शी नीति निर्माण को तरजीह देने लगी है. 2022 के बजट में बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत खर्च पिछले साल के 5.5 लाख करोड़ रु. से 35.4 फीसद बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रु. कर दिया गया था. इस साल वित्त मंत्री ने इसे 33 फीसद बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रु. या जीडीपी का 3.3 फीसद कर दिया. यह अच्छा आंकड़ा है, जिससे जरूरी नौकरियों का सृजन होना चाहिए.

रोजगार पैदा करने वाले दूसरे प्रमुख क्षेत्रों को भी कई प्रोत्साहन दिए गए हैं. एमएसएमई को दी गई 2 लाख करोड़ रु. की कर्ज गारंटी योजना और दूसरे फुटकर लाभों से इस क्षेत्र में जान पड़नी चाहिए, जो नोटबंदी के बाद से ही काफी-कुछ निढाल पड़ा है. यह 11 करोड़ से ज्यादा रोजगार देता है, जो कुल रोजगार का 20 फीसद से ज्यादा है. नई कृषि उत्प्रेरक निधि ग्रामीण भारत में एग्रीटेक स्टार्ट-अप के लिए मददगार साबित होगी. रोजगार वाले एक अन्य क्षेत्र पर्यटन को उदार प्रोत्साहन मिला है—50 जगहों को चुनकर उन्हें चमकाया जाएगा, तकि वहां हवाई अड्डे वगैरह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बनें.

16 फरवरी, 2022

बुनियादी ढांचे पर खर्च भी नौकरियों के सृजन का परोक्ष तरीका है. जहां तक प्रत्यक्ष रोजगार की बात है, केंद्र ने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का बजट घटाने के अपने रुझान का पालन किया. लिहाजा 2023-24 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) के तहत महज 60,000 करोड़ रु. रखे गए. यह वित्त वर्ष 2022-23 के 89,000 करोड़ रु. के संशोधित अनुमान से 33 फीसद कम है. साफ है कि केंद्र बड़ी तादाद में निजी निवेश लाने और अपने पूंजीगत खर्च के साथ नौकरियों के सृजन पर दांव लगा रहा है, ताकि मनरेगा के जरिए काम न देना पड़े. पिछले वित्त वर्ष में 5.7 करोड़ लोगों ने मनरेगा के तहत काम किए थे, यह दुनिया की सबसे बड़ी गरीबी उन्मूलन योजना के लक्ष्यों में बहुत साफ फेरबदल है.

इस हफ्ते हमारी आवरण कथा के लिए एक्जीक्यूटिव एडिटर एम.जी. अरुण दोहरी नजर डाल रहे हैं. एक तरफ हम विश्लेषण कर रहे हैं कि आम चुनाव से एक साल पहले नौकरियों के सृजन पर मोदी सरकार का इतना जोर क्यों है. हर साल 1.2 करोड़ भारतीय कार्यबल में शामिल होते हैं. दुखद यह है कि सीएमआइई के दिसंबर के आंकड़ों के मुताबिक 20-24 वर्ष आयु वर्ग के 7.7 करोड़ युवा भारतीयों में से 48 फीसद बेरोजगार थे. यह 2017-18 के 20 फीसद से दोगुने से भी ज्यादा और महामारी से ठीक पहले के 30 फीसद से भी ज्यादा है. 25-29 वर्ष आयु वर्ग में भी यह 14 फीसद था. यही हमारी विशाल आबादी से मिलने वाला वह लाभांश है जिसके बहुत गुण गाए जाते हैं और जो बर्बाद हो रहा है.

भारत में 44.3 करोड़ कामगारों की फौज है, पर एक चौथाई के पास ही 'नियमित नौकरी' है, यानी ऐसी नौकरी जिसमें हर महीने तनख्वाह और कुछ सुरक्षा मिलती है. 75 फीसद से ज्यादा लोग अल्पकालिक काम में लगे हैं या अपने धंधे करते हैं. उन्हें न नियमित आमदनी की गारंटी है और न काम की. हमारे ब्यूरो ने बेजान आंकड़ों को मानवीय चेहरा भी दिया. हमारा सामना उन मुरझाए लाखों युवाओं में कुछ से हुआ—मसलन, 24 वर्षीय बीकॉम ग्रेजुएट कुलदीप नारायण त्रिपाठी, जो भोपाल पार्क की बेंच पर मोबाइल एसेसरीज बेचते हैं.

भारत में रोजगार पेचीदा मुद्दा है. यह ढांचागत समस्या भी है. कृषि में कार्यबल के 46 फीसद लोग लगे हैं, पर यह जीडीपी में महज 20 फीसद का योगदान देती है. सेवाएं 54 फीसद का योगदान देती हैं, जिनमें 32 फीसद लोग लगे हैं, और उद्योगों में करीब 21 फीसद लोग लगे हैं, जो 26 फीसद का योगदान देते हैं. भारत में परेशानी बेरोजगारी की उतनी नहीं बल्कि छिपी हुई अल्परोजगारी की है. लोग अनुत्पादक काम-धंधों में लगे हैं. कई सरकारों ने इस असंतुलन को बदलने की कोशिश की, पर कम ही कामयाबी मिली. खुद बेरोजगारी के आंकड़े ही गुमराह करने वाले हैं. परिभाषा से बेरोजगार वह व्यक्ति है जो रोजगार की तलाश कर रहा है, पर भारत में ज्यादातर लोग बेरोजगार रहना गवारा नहीं कर सकते क्योंकि वे हाशिए पर जिंदगी गुजारते हैं.

बजट 2023 इस मुद्दे से निपटने की कोशिश करता है., सिर्फ पूंजीगत खर्च बढ़ाकर नहीं. कारीगरों और दस्तकारों के लिए नई प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान (पीएम-विकास) योजना उन्हें अपने उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने, पैमाना बढ़ाने और बेहतर बाजारों तक पहुंच हासिल करने, उसे एमएसएमई मूल्य श्रृंखला से जोड़ने में मदद करती है. लोगों को हुनर मुहैया कराने पर भी ज्यादा जोर है. विदेश में नौकरियों का लक्ष्य साधने में युवाओं की मदद के लिए तमाम राज्यों में करीब 30 स्किल इंडिया अंतरराष्ट्रीय केंद्र खोले जाएंगे.

शायद कई राज्यों के चुनावों और अगले साल आम चुनाव को ध्यान में रखकर वित्त मंत्री निजीकरण के एजेंडे पर खामोश रहीं, जिसमें 2021 के बजट में घोषित बैंकों के निजीकरण की योजना भी शामिल है. केंद्र ने विनिवेश का लक्ष्य भी घटाकर 51,000 करोड़ रु. कर दिया. पिछले बजट में विनिवेश से 65,000 करोड़ रु. उगाहने का मंसूबा था, जिसे बाद में बदलकर 50,000 करोड़ रु. कर दिया. 18 जनवरी तक महज 31,106 करोड़ रु. इकट्ठा हुए थे. 2021 में संपत्तियों के मौद्रीकरण की बजट घोषणा के बाद उस साल अगस्त में केंद्र ने राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन के तहत 6 लाख करोड़ रु. उगाहने की योजना का ऐलान किया था. इस बजट में उसकी प्रगति का कोई जिक्र नहीं है.

अंततः सार्वजनिक निवेश के लिहाज से सरकार बस इतना ही कर सकती है. आखिरकार यह जीडीपी का 7 फीसद है, जबकि निजी निवेश, सरकारी निवेश के तिगुने से भी ज्यादा, करीब 20-23 फीसद है. बजट तो बस उत्प्रेरक हो सकता है. चुनावी प्रलोभनों के बावजूद राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने और देश को लगातार वृद्धि की राह पर ले जाने के लिए सरकार की तारीफ करनी होगी.

अरुण पुरी

(अरुण पुरी)

इंडिया टुडे

www.indiatodayhindi.in

चेयरमैन और प्रधान संपादक: अरुण पुरी
वाइस चेयरपर्सन: कली पुरी
ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर: दिनेश भाटिया
ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर: राज चेंगप्पा
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर: मनोज शर्मा
एडिटर: सौरभ द्विवेदी
डिप्टी एडिटर: मोहम्मद वक़ास
एसोसिएट एडिटर: शिवकेश मिश्र, आशीष मिश्र (लखनऊ)
सीनियर असिस्टेंट एडिटर: पवन वर्मा
असिस्टेंट एडिटर: मनीष दीक्षित, प्रदीपिका सारस्वत
वरिष्ठ विशेष संवाददाता: हिमांशु शेखर
विशेष संवाददाता: विनय सुल्तान
राज्य ब्यूरो: पुष्यमित्र (पटना), आनंद चौधरी (जयपुर), एम.जी. अरुण (मुंबई), राहुल नरोन्हा (भोपाल), अमरनाथ के. मेनन (हैदराबाद)
ग्रुप क्रिएटिव एडिटर: नीलांजन दास
एसोसिएट आर्ट डायरेक्टर: चंद्रमोहन ज्योति
असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर: असित रॉय
ग्रुप फोटो एडिटर: बंदीप सिंह
फोटो डिपार्टमेंट: राजवंत रावत, चंद्रदीप कुमार, मंदार सुरेश देवघर (मुंबई)
चीफ फोटो रिसर्चर: प्रभाकर तिवारी
प्रिंसिपल फोटो रिसर्चर: सलोनी वैद
प्रोडक्शन चीफ: अभिनव पुगला
एसोसिएट पब्लिशर (इंपैक्ट): विद्या मेनन, सुपर्णा कुमार
इंपैक्ट टीम
सीनियर जनरल मैनेजर: मयूर रस्तोगी (नॉर्थ), जीतेंद्र लाड (वेस्ट)
जनरल मैनेजर: सैयद नवीद (चेन्नै)
ग्रुप चीफ मार्केटिंग ऑफिसर: विवेक मल्होत्रा
सेल्स एवं ऑपरेशन
सीनियर जनरल मैनेजर: दीपक भट्ट (नेशनल सेल्स)
जनरल मैनेजर: विपिन बग्गा (ऑपरेशंस)
डिप्टी जनरल मैनेजर: राजीव गांधी (नॉर्थ)
डिप्टी रीजनल सेल्स मैनेजर: योगेश गोधनलाल गौतम (वेस्ट)
डिप्टी रीजनल सेल्स मैनेजर: एस. परमशिवम (साउथ)
सीनियर सेल्स मैनेजर: पीयूष रंजन दास (ईस्ट)

वर्ष: 37; अंक: 11; 9-15 फरवरी 2023; प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित

- **संपादकीय कॉर्पोरेट कार्यालय:** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, इंडिया टुडे ग्रुप मीडियाप्लेक्स, एफसी-8, सेक्टर 16-ए, फिल्म सिटी, नोएडा-201301, फोन: 0120-4807100;
- **ग्राहकी चंदा भेजें:** इंडिया टुडे (हिंदी), पो. बॉक्स 114, नई दिल्ली-110001
- **ग्राहक सेवा:** कस्टमर केयर, इंडिया टुडे ग्रुप, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301, टोल फ्री फोन नं. 1800 1800 100 (बीएसएनएल/एमटीएनएल लाइनों से) फोन: दिल्ली, फरीदाबाद से (95120) 2479900; शेष भारत से (0120) 2479900. (सोम से शुक्र-सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक), फैक्स: (0120) 4078080. ई-मेल: wecare@intoday.com
- **सर्कुलेशन कार्यालय:** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301
- **इंपैक्ट कार्यालय:** 1201, 12वां तल, टावर 2ए, वन इंडियाबुल्स सेंटर, (जुपिटर मिल्स) एस.बी. मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम)-मुंबई-400013. फोन: 022-66063355 फैक्स: 022-66063226
- **क्षेत्रीय विज्ञापन कार्यालय:** ए1-ए2, एनके सेंटर, विनुज्य निकुंज, उद्योग विहार, फेज-5, गुड़गांव, हरियाणा, फोन: 0124-4948400;
- 201-204 रिचमंड टावर्स, द्वितीय मंजिल, 12 रिचमंड रोड, बंगलुरू-560 025 फोन: 2212448, 226233, टेलेक्स: 0845-2217 INTO IN. फैक्स: 080-2218335.
- रजिस्टर्ड कार्यालय: एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

- लिविंग मीडिया इंडिया लि. विश्व भर में सर्वाधिकार सुरक्षित. किसी भी रूप में सामग्री की नकल प्रतिबंधित. इंडिया टुडे अनिमंत्रित प्रकाशन सामग्री को लौटाने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता.

- सभी विवादों का निबटारा दिल्ली/नई दिल्ली की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों और फोरमों में किया जाएगा.
- **लिविंग मीडिया इंडिया लि. के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक मनोज शर्मा द्वारा एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और थॉमसन प्रेस इंडिया लि., 18-35, माइलस्टोन, दिल्ली-मथुरा रोड, फरीदाबाद-121 007 (हरियाणा) में मुद्रित. संपादक: राज चेंगप्पा**

चंद्रदीप कुमार

20

वादों का पुलिंदा
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने के लिए जाती हुईं

आवरण कथा

नौकरियां बढ़ाने पर जोर

देश में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बजट 2023 में आखिर क्या उपाय किए गए हैं?

भीतर

सुर्खियां
गौतम अदाणी: अग्निपरीक्षा की घड़ी
पेज 7

राजस्थान: सियासी जमीन पाने की जद्दोजहद
पेज 9

फुरसत
सवाल+जवाब/अनुराग कश्यप
पेज 52

समाजवादी पार्टी
14 पिछड़ों-दलितों में अगड़ा बनने का दांव
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने स्पष्ट की पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग.

पंजाब
36 भाजपा में दलबदलुओं की बहार
राज्य में भाजपा बाहरी नेताओं को पार्टी में लेकर आई.

उत्तर-पूर्व
41 पूर्वोत्तर में मुकाबला
इन तीन राज्यों के चुनाव भाजपा के लिए पूर्वोत्तर में पैठ बनाने का मौका.

बिहार जीविका
44 आमदनी नहीं इकन्नी जिम्मेदारी सोलह आना
इससे जुड़ीं 1.3 करोड़ महिलाएं इसका लाभ पाने से कोसों दूर.

मिशन शक्ति
48 जीवन बदलने का ओड़िया मॉडल
ओडिशा की यह योजना लाखों महिलाओं का जीवन बदल रही है.

खुशी की खोज
50 सब मिल गाएं सा रे गा
वंचित बच्चों का शास्त्रीय संगीत से तआरुफ कराने की पहल.

आवरण: नीलांजन दास

पाठकों के लिए सूचना: कभी-कभी आपको इंडिया टुडे पत्रिका में 'इम्पैक्ट फीचर' या 'एडवरटोरियल' या 'फोकस' के पन्ने नजर आते होंगे. ये विज्ञापन हैं और इन्हें बनाने में पत्रिका का संपादकीय स्टाफ शामिल नहीं होता.

पाठकों को सलाह दी जाती है कि पत्रिका में प्रकाशित किसी भी सेवा या व्यक्ति के विज्ञापन और प्रचार से संबंधित सामग्री से वचनबद्धता कायम करने, पैसा भेजने या खर्च करने से पहले उचित जांच-पड़ताल कर लें. विज्ञापनदाताओं के किसी भी दावे का उत्तरदायित्व इंडिया टुडे ग्रुप का नहीं है. ऐसे किसी भी तरह के दावों को विज्ञापनदाता अगर नहीं पूरा करता है तो इंडिया टुडे ग्रुप के प्रकाशनों के मुद्रक, प्रकाशक, एडिटर-इन-चीफ और एडिटर इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे.

राजस्थान : सियासी जमीन पाने की जद्दोजहद
पेज 9

सपा : पिछड़ों-दलितों में अगड़ा बनने का दांव
पेज 14

मध्य प्रदेश पुलिस: जवान सब्जी लाएगा
पेज 10

उपेंद्र कुशवाहा: चंद लोग नीतीश जी को डिक्टेट करते हैं
पेज 18

सुर्खियां

बंदीप सिंह

बड़ा झटका

हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद अदाणी ग्रुप की कंपनियां कैसे फिसल गईं

तीन सत्रों के दौरान मार्केट कैप में बदलाव

कंपनी	करोड़ रु.	% में
एसीसी	-8,103	-18.5
अदाणी एंटरप्राइजेज	-64,325	-16.4
अदाणी ग्रीन एनर्जी	-1,14,977	-37.9
अदाणी पोर्ट्स & एसईजेड	-35,426	-21.6
अदाणी पावर	-15,100	-14.2
अदाणी टोटल गैस	-1,69,129	-39.6
अदाणी ट्रांसमिशन	-1,16,686	-38
अदाणी विल्मर	-10,618	-14.3
अंबुजा सीमेंट्स	-22,061	-22.3
एनडीटीवी	-260	-14.2
कुल	-5,566,85	-29

स्रोत: 25, 27 और 30 जनवरी को बीएसई के प्राइस और शेयरहोल्डिंग डेटा के आधार पर

गौतम अदाणी

अग्निपरीक्षा की घड़ी

एम.जी. अरुण

अहमदाबाद स्थित अदाणी ग्रुप के चेयरमैन 60 वर्षीय गौतम अदाणी के लिए यह अग्निपरीक्षा है. अमेरिका की इनवेस्टमेंट रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से इस ग्रुप पर बाजार में जोड़-तोड़ और धन शोधन के आरोपों के बाद इसकी कंपनियों के शेयरों को जबरदस्त झटका लगा. इस प्रसंग के बाद भारतीय शेयर बाजार भी धड़ाम से नीचे आ गए. सेंसेक्स और निफ्टी में 27 जनवरी को क्रमश: 874.16 अंकों और 287.60 अंकों की गिरावट आई, जो सूचकांकों में बीते चार महीनों की सबसे बड़ी गिरावट थी. अदाणी ग्रुप की तरफ से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का 417 पन्नों

का खंडन जारी करने के बाद शेयर बाजार 30 जनवरी को थोड़ा पहले की स्थिति में लौट आए. महज तीन कारोबारी सत्रों में अदाणी ग्रुप का 29 फीसद बाजार पूंजीकरण या करीब 5.6 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए. ग्रुप के शेयरों में गिरावट 1 फरवरी को तब भी जारी रही जब वित्त मंत्री केंद्रीय बजट पेश कर रही थीं, और अकेले अदाणी एंटरप्राइजेज में 30 फीसद की गिरावट हो रही थी. यह मीडिया रिपोर्टों में आए उस दावे के बाद हुआ जिनमें कहा गया कि क्रेडिट सुइस ने प्राइवेट बैंकिंग ग्राहकों से अदाणी की कंपनियों के बॉंडों को मार्जिन लोन के एवज में गिरवी रखने से मना कर दिया है. 1 फरवरी को फोर्ब्स की वास्तविक समय पर अमीरों की फेहरिस्त के मुताबिक, अदाणी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स से लुढ़ककर 15वें पायदान पर आ गए, जिनकी कुल संपदा 75.1 अरब डॉलर (करीब 6.2 लाख करोड़ रु.) रह गई. अदाणी, मुकेश अंबानी से पीछे खिसक गए जिन्होंने 83.7 अरब डॉलर (करीब 6.86 लाख करोड़ रुपए) के साथ भारत के सबसे अमीर शख्स का तमगा फिर से हासिल कर लिया.

जनवरी की 14 तारीख को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ऐसे वक्त आई जब अदाणी समूह की ध्वजवाहक कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज कंपनी की विस्तार योजनाओं के वास्ते धन जुटाने और अपने कुछ कर्ज चुकाने की खातिर बाजार से 20,000 करोड़ रुपए उगाहने के लिए फॉलो-ऑन पब्लिक इश्यू (एफपीओ) लाने जा रही थी. मगर रिसर्च फर्म के आरोपों की वजह से अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयर एफपीओ के आधार मूल्य—जो प्रति शेयर 3,112-3,276 रुपए के बैंड में था—से कम कीमत पर खरीदे-बेचे जा रहे थे. 1 फरवरी को अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयर बीएसई पर 2,128.70 रु. के भाव पर बंद हुए. हालांकि 31 जनवरी तक खासतौर पर धन्नासेठों (हाइ नेटवर्थ इंडीवीजुअल) की बदौलत एफपीओ पूरी तरह सब्स्क्राइब हो चुका था, फिर भी अदाणी ग्रुप ने 1 फरवरी को एफपीओ वापस ले लिए और कहा, ''निवेशकों के हित में'' और ''नैतिक रूप से उचित न होने'' की वजह से यह कदम उठाया गया है. 2 फरवरी को जारी एक बयान में गौतम अदाणी ने कहा, ''फैसले का हमारे मौजूदा कारोबार और भविष्य की योजनाओं पर कोई असर नहीं होगा. हम परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और डिलीवरी पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखेंगे.''

दावों की जंग

हिंडनबर्ग के आरोप

- अदाणी की कंपनियों ने बहुत भारी-भरकम कर्ज ले रखा है, जिससे समूह डांवांडोल वित्तीय जमीन पर खड़ा है
- अदाणी के बड़े भाई विनोद अदाणी करीबी सहयोगियों के जरिये विदेशों में कई शेल संस्थाओं का प्रबंधन करते हैं; उनमें 38 की पहचान कर ली गई है
- अदाणी एंटरप्राइजेज में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के नौकरी छोड़ने की दर अधिक रही है जो बही-खाते में मसलों का संकेत है
- अदाणी एंटरप्राइजेज और अदाणी टोटल गैस के स्वतंत्र ऑडिटर शाह ढांढरिया ऑडिट के पेचीदा काम में नाकाबिल और अनुभवहीन शख्स नजर आते हैं
- अदाणी के छोटे भाई राजेश पर डीआरआइ ने हीरा घोटाले का आरोप लगाया था और वे गिरफ्तार हुए थे. वे एमडी हैं. उनके बहनोई समीर वोरा पर भी डीआरआइ ने आरोप लगाया था

अदाणी के जवाब

- समूह ने कर्ज को लगातार कम किया है और इसका ईबीआइटीडीए अनुपात 7.6 गुना से 3.2 गुना हो गया है
- ये बिना किसी सबूत पेश किए और पार्टी लेन-देन से जुड़े भारतीय कानूनों की समझ के बिना दिए गए ''लापरवाही भरे बयान'' हैं
- हिंडनबर्ग ने जिनका दावा किया है, उनमें से कई सीएफओ अब भी पहले से ज्यादा बड़ी या अन्य अहम भूमिकाओं में संगठन का हिस्सा हैं
- शाह ढांढरिया एक पीयर-रिव्यू सीए फर्म हैं. बिग 6 वैधानिक ऑडिटरों समेत, 35 वैधानिक ऑडिट फर्में अदाणी एंटरप्राइजेज की विभिन्न संस्थाओं का ऑडिट करती हैं
- एक अपीलीय न्यायाधिकरण ने डीआरआइ के सभी आरोपों को रद्द कर दिया था और सभी लेन-देन को वैध तथा सही बताया था. सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके फैसले को सही ठहराया था

हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 218 अरब डॉलर (17.8 लाख करोड़ रुपए) का अदाणी ग्रुप ''दशकों के दौरान शेयरों के हेर-फेर और लेखाबही में धोखाधड़ी की योजनाओं में लिप्त'' रहा. उसने खुलासा किया कि उसने यूएस-ट्रेडेड बॉन्ड और नॉन-इंडियन-ट्रेडेड बॉन्ड के जरिए अदाणी ग्रुप की कंपनियों में 'शॉर्ट पोजिशन' ले रखी है. इस अमेरिकी फर्म का बड़े कॉर्पोरेट घरानों को 'शॉर्टिंग' करने का इतिहास रहा है. उसने कहा कि समूह ने अपनी सात सूचीबद्ध कंपनियों का टर्नओवर कृत्रिम ढंग से बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने के लिए विदेशों में स्थित शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया, जिनका कामकाज गौतम के बड़े भाई विनोद अदाणी संभालते थे.

अपने स्पष्टीकरण में अदाणी ग्रुप ने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में उठाए गए 88 सवालों में से 65 के जवाब का खुलासा अदाणी पोर्टफोलियो कंपनियां समय-समय पर कर चुकी हैं. बाकी 23 में से, 18 सवाल सार्वजनिक शेयरधारकों और थर्ड पार्टी से जुड़े थे, जबकि पांच निराधार आरोप थे. उसने कहा कि रिपोर्ट में लगाए गए आरोप ''झूठा नैरेटिव गढ़ने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में पहले से मौजूद मामलों की चालाक प्रस्तुति'' हैं. अदाणी ग्रुप ने जोर देकर कहा कि वह सभी कानूनों और नियम-कायदों का पूरी तरह पालन करता रहा है और ''सभी उपयुक्त अथॉरिटीज के समक्ष अपने शेयरधारकों की हिफाजत के उपायों'' की तलाश कर सकता है. उसने आरोपों को राष्ट्र पर हमला करार दिया. हिंडनबर्ग ने जवाबों को असंतोषजनक बताया और उनपर कायम रहा. उसने यह भी कहा कि ''धोखाधड़ी को राष्ट्रवाद की आड़ में छिपाया नहीं जा सकता.'' कांग्रेस ने बाजार नियामक सेबी और आरबीआइ से आरोपों की जांच करवाने की मांग की है.

हिंडनबर्ग की स्थापना 2017 में इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवैटिव बाजारों के विश्लेषण के लिए हुई थी. इसका नाम 1937 में न्यू जर्सी

में हुए एयरशिप विस्फोट के नाम पर रखा गया था, जिसमें 35 यात्रियों की मौत हो गई थी. अभी तक यह कम से कम 16 कंपनियों को निशाना बना चुका है. उसके बयान में स्पष्ट किया गया है कि—उसका मकसद अपनी रिसर्च की मार्फत निशाना बनाई गई कंपनी के शेयरों के टूटने की आशंका में उनकी अग्रिम बिक्री, या 'शॉर्टिंग' के जरिए मुनाफा कमाना है. हिंडनबर्ग का एक प्रमुख आरोप यह है कि अदाणी की कंपनियों ने भारी-भरकम कर्ज ले रखा है, जिससे समूह भुरभुरी वित्तीय जमीन पर खड़ा है. अदाणी ने इसका खंडन करते हुए कहा कि कंपनी ने कर्ज का स्तर लगातार कम किया है, जिससे ईबीआइटीडीए के साथ उसके पोर्टफोलियो शुद्ध ऋण का अनुपात (कंपनी की ऋणग्रस्तता का पैमाना) 7.63 गुना से घटकर 3.23 गुना पर आ गया है. अदाणी का कर्ज बढ़ते-बढ़ते मार्च 2022 में 1.88 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया था. आशंका यह भी थी कि सरकारी बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम (एलआइसी) की बहुत बड़ी रकम अदाणी ग्रुप की फर्मों में जोखिम से घिरी है. एलआइसी ने 30 जनवरी को एक बयान में कहा कि अदाणी ग्रुप में शेयर और कर्ज की मार्फत उसकी हिस्सेदारी 35,917 करोड़ रुपए थी. उसने जनता को भरोसा दिलाया कि एलआइसी के पास रखी अदाणी की ऋण प्रतिभूतियों की क्रेडिट रेटिंग आइआरडीएआइ (भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण) के नियमों का पालन करती हैं.

हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया कि अदाणी की फर्मों के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (सीएफओ) के पद पर नौकरी छोड़ने की दर—आठ साल के दौरान पांच सीएफओ—काफी अधिक रही है. यह लेखा-बही के संभावित दिक्कतों की तरफ इशारा करता है. उसने यह भी कहा कि अदाणी एंटरप्राइजेज और अदाणी टोटल गैस के स्वतंत्र ऑडिटर शाह ढांढरिया ऑडिट के पेचीदा काम में नाकाबिल लगते हैं. अदाणी ने इसे बकवास बताते हुए कहा कि ढांढरिया को 20 साल से ज्यादा का अनुभव है. उसने यह भी कहा कि अदाणी एंटरप्राइजेज नए कारोबारों का इंक्यूबेटर है. कानून के मुताबिक तय 35 से ज्यादा वैधानिक ऑडिट फर्म अदाणी एंटरप्राइजेज में तमाम संस्थाओं का ऑडिट करती हैं.

एक और आरोप यह था कि गौतम अदाणी के छोटे भाई राजेश अदाणी पर राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआइ) ने 2004-2005 के आसपास हीरों की ट्रेडिंग आयात/निर्यात स्कीम में मुख्य भूमिका निभाने का आरोप लगाया था. डीआइआर ने उनके बहनोई समीर वोरा पर भी हीरा ट्रेडिंग घोटाले का सरगना होने का आरोप लगाया था. अदाणी ग्रुप ने कहा कि एक अपीलीय न्यायाधिकरण ने डीआरआइ के सभी आरोपों को रद्द कर दिया और सभी लेन-देन के वैध बताया था, और सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधिकरण के आदेश को सही ठहराया था.

विशेषज्ञों का मानना है कि अदाणी ग्रुप हिंडनबर्ग के इस अफसाने से उबर जाएगा, पर कुछ दाग लगे रह सकते हैं. ■

राजस्थान

सियासी जमीन पाने की जद्दोजहद

आनंद चौधरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिन में दूसरी बार राजस्थान आ रहे हैं. प्रधानमंत्री 28 जनवरी को भीलवाड़ा जिले के गुर्जर तीर्थस्थल मालासेरी आए थे और 12 फरवरी को उनका दौसा जिले के नांगल राजावतान में आने का कार्यक्रम है. नांगल राजावतान को मीणा हाइकोर्ट भी कहा जाता है क्योंकि यह इलाका मीणा बाहुल्य माना जाता है.

राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, प्रधानमंत्री के ये ताबड़तोड़ दौरे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की खोई हुई सियासी जमीन तलाशने की कोशिश हैं. साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को इन्हीं क्षेत्रों में सर्वाधिक नुक्सान हुआ था. उस वक्त भाजपा का परंपरागत वोट बैंक माना जाने वाला गुर्जर और मीणा समुदाय उससे दूर छिटककर कांग्रेस के पाले में चला गया था. गुर्जर और मीणा बाहुल्य माने जाने वाले भरतपुर संभाग की 19 सीटों में से भाजपा को सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल हुई थी. यहां कांग्रेस को 13 सीटों और निर्दलीय एवं अन्य दलों के उम्मीदवारों को पांच सीटों पर जीत मिली थी.

इसी तरह जयपुर संभाग में भी भाजपा को 54 में से महज 11 सीटें ही मिली थीं. जयपुर संभाग के अलवर, दौसा, टोंक, झुंझुनूं और जयपुर के ग्रामीण इलाकों को भी गुर्जर और मीणा बाहुल्य माना जाता है. 2018 में कांग्रेस को जयपुर संभाग में एक तिहाई यानी, 33 सीटें हासिल हुई थीं.

इसके अलावा उदयपुर संभाग जिसे आदिवासी बाहुल्य माना जाता है, वहां भी भाजपा अब अपना राजनीतिक वजूद हासिल करने की फिराक में है. साल 2018 में इस संभाग की 28 सीटों

में से 15 सीटों पर भाजपा को जीत हासिल हुई थी. साल 2008-09 के बाद राजस्थान का आदिवासी वोट बैंक भाजपा की तरफ मुड़ा है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनावों में यहां कांग्रेस को भी 10 सीटें मिली थीं. इसके अलावा दो सीटें भारतीय ट्राइबल पार्टी (बीटीपी) के खाते में गई.

पिछले विधानसभा चुनावों में जोधपुर संभाग भी भाजपा के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा. इस संभाग की 40 में से 22 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी. भाजपा को इस संभाग में सिर्फ 14 सीटें ही मिलीं. 4 सीटें निर्दलीय एवं अन्य पार्टियों को हासिल हुई. जोधपुर संभाग में पार्टी को फिर से मजबूती प्रदान करने के लिए गृहमंत्री अमित शाह पांच माह पहले 9-10 सितंबर, 2022 को भाजपा के ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक कर चुके हैं.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा इन्हीं चार संभागों में अपना वोट बैंक तलाश रही है. राजनीतिक मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार त्रिभुवन कहते हैं, ''भाजपा ने राजस्थान में अपनी कमजोर नब्ज पहचानकर पहले से ही शुरूआत कर दी है जिसका फायदा उसे आने वाले चुनाव में मिल सकता है.''

आदिवासी संभाग में पिछले पांच माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो बड़ी सभाएं हो चुकी हैं. बांसवाड़ा के आदिवासी महाकुंभ मानगढ़ धाम में 1 नवंबर, 2022 और सिरोही जिले के आबू रोड में 30 सितंबर, 2022 को मोदी का दौरा हो चुका है. गुर्जर बहुल भीलवाड़ा में प्रधानमंत्री मोदी 28 जनवरी को बड़ी सभा कर चुके हैं. इस सभा में प्रधानमंत्री ने गुर्जर समाज के साथ भाजपा का नाता जोड़ने की कोशिश की. मोदी ने कहा कि गुर्जर समाज के लोक देवता देवनारायण का अवतरण कमल पर हुआ था और भाजपा की पैदाइश भी कमल के साथ हुई.

राजस्थान में गुर्जर समाज की करीब 50 लाख आबादी है तथा प्रदेश की 35 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां गुर्जर मतदाता हार-जीत में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं. गुर्जर समाज भाजपा का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है, लेकिन पिछले चुनाव में सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनाए जाने की अटकलों के चलते गुर्जरों ने भाजपा से किनारा कर लिया और कांग्रेस का जमकर साथ दिया था. पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 9 गुर्जर उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जिसमें से सिर्फ एक को जीत मिली थी. वहीं कांग्रेस

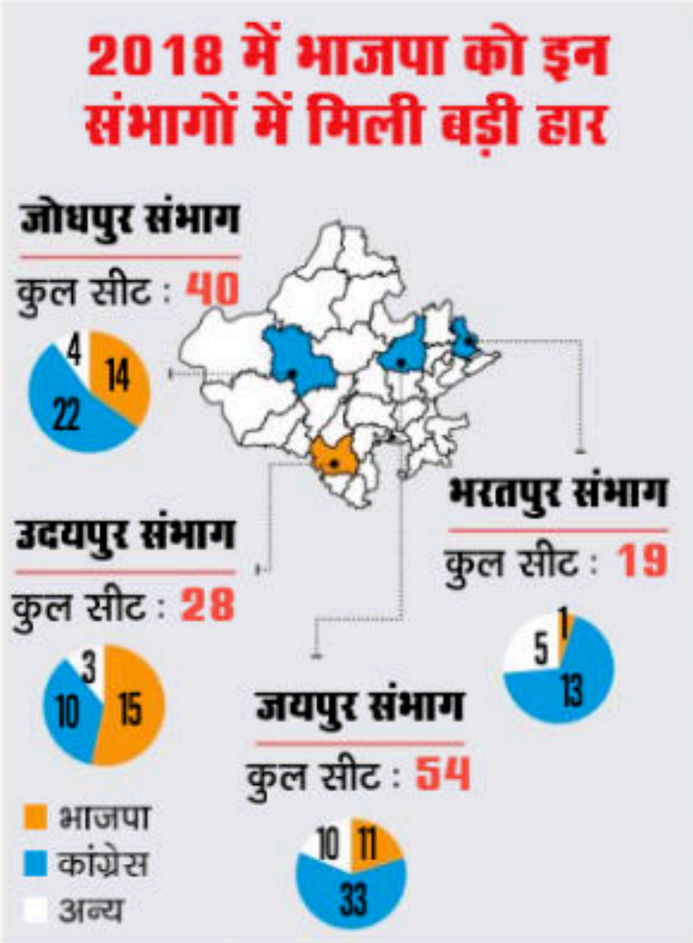

ने 12 गुर्जर उम्मीदवार उतारे जिसमें से 7 विधायक चुने गए.

कुछ ऐसा ही हाल मीणा बाहुल्य क्षेत्रों में रहा. कांग्रेस के टिकट पर 9 मीणा विधायक जीते तो भाजपा के टिकट पर सिर्फ एक मीणा विधायक को जीत हासिल हुई थी. 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मीणा हाइकोर्ट माने जाने वाले नांगल राजावतान में आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है. यहां मोदी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के सोहना-दौसा खंड का उद्घाटन करेंगे. राजस्थान में मीणा समुदाय करीब 40 सीटों पर निर्णायक भूमिका में है.

हालांकि, राजस्थान में भाजपा के प्रदेश मंत्री लक्ष्मीकांत भारद्वाज प्रधानमंत्री मोदी के इन दौरों को राजनीतिक नहीं मानते. भारद्वाज का कहना है, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मालासेरी दौरा शुद्ध रूप से धार्मिक कार्यक्रम था और आगामी दौसा दौरा सरकारी कार्यक्रम है. रहा सवाल राजनीतिक फायदे का तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश-दुनिया में इतने चर्चित हैं कि वे जहां जाते हैं, वहां भाजपा को फायदा मिलता ही है.''

लेकिन, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी प्रधानमंत्री मोदी के राजस्थान दौरों को राजनीतिक ही मानते हैं. चतुर्वेदी कहते हैं, ''प्रधानमंत्री के दन दौरों से भाजपा को कुछ हासिल नहीं होने वाला क्योंकि प्रधानमंत्री ने पिछले चुनाव से पहले पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) लागू करने का वादा किया था. अगर यह लागू होता इसका सबसे ज्यादा फायदा गुर्जर-मीणा बहुल इलाकों को ही मिलता. लेकिन इस पर आज तक कोई फैसला नहीं हुआ है. यहां के लोग अब भाजपा के भुलावे में नहीं आने वाले.'' ■

दुआ मैसाज उवनी

राहुल नरोन्हा

हाल में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस नब्ज पर उंगली रखी उसने हिंदुस्तान में सामंती राज में सेवा-चाकरी करवाने वाले दिनों की याद ताजा कर दी. उन्होंने प्रदेश की भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) के अधिकारियों को चेताया कि पुलिस वालों को अपने घरों में घरेलू कामों के लिए बहुत ज्यादा तैनात करने से बाज आएं. मुख्यमंत्री दरअसल इस आशय की खबरों पर प्रतिक्रिया जता रहे थे जिनमें कहा गया था कि राज्य की राजधानी भोपाल में डीआइजी रैंक के एक अधिकारी के घर पर 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं. हालांकि संबंधित अधिकारी ने इन खबरों का खंडन किया. लेकिन ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री ने पहली बार इस मुद्दे को उठाया हो. आइपीएस लॉबी अपने इस 'विशेषाधिकार' की पूरी ताकत से रखवाली करती रही है. निचले पायदानों के पुलिसकर्मियों के बड़े हिस्से को उनके मूल कर्तव्य पूरे नहीं करने दिए जा रहे, जिससे उस तबके में खासा असंतोष और नाराजगी है.

तमाम राज्यों की पुलिस की तरह मध्य प्रदेश पुलिस भी पैरामिलिटरी शाखा विशेष सशस्त्र बल (एसएएफ) के जरिए कॉन्स्टेबल कारिंदों की भर्ती करती है. इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई, ड्राइवर और दर्जी सरीखे तकनीकी पदों पर आसीन लोगों के अलावा इनमें गैर-तकनीकी रंगरूट जैसे रसोइए, नाई, मोची और मेहतर भी हैं. मूलत: ये एसएएफ की बटालियनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए होते थे. मगर कांस्टेबल कारिंदों की फौज लगातार बढ़ती गई, जिसमें रसोइयों, ड्राइवरों और ऐसे बाकी कारिंदों की बहुत ज्यादा भर्तियां की जातीं और उन्हें बड़े अफसरों के घरों में घरेलू सहायकों के तौर पर तैनात किया जाता. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में करीब 11,000 कॉन्स्टेबल कारिंदे हैं. मोटे अनुमान से इनमें से 5,500 या 50 फीसद घरेलू कामों के लिए तैनात हैं.

ऐसा भी नहीं कि हमेशा से इसी तरह की व्यवस्था रही हो. 1993 के बाद एक आदेश का पालन करते हुए इन कर्मियों को पांच साल बाद नियमित पुलिसबल में समायोजित किया जाता था, बशर्ते उन्होंने

जवान सब्जी लाएगा

जरूरी प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो. मगर 2013 में उस वक्त के डीजीपी नंदन दुबे ने इन कांस्टेबल कारिंदों के लिए उन्हीं के काडर के भीतर पदोन्नति का हवाला देते हुए इस प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगा दी.

इसके खिलाफ हाइ कोर्ट में गए कुछ कर्मचारियों को 2019 में मंदसौर जिले में नियमित बल में जरूर समायोजित कर लिया गया लेकिन नीतिगत तौर पर ऐसी भर्तियां बीते एक दशक से बंद ही हैं—इस हद तक कि राजनैतिक आकाओं की तरफ से किए गए हस्तक्षेप भी ताकतवर आइपीएस लॉबी को झुकाने में कामयाब नहीं हो पाए. मसलन, मार्च 2022 में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने राज्य पुलिस महकमे को चिट्ठी लिखकर इस प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने के लिए कहा. यहां तक कि वित्त महकमे ने भी 2019 में स्पष्ट कर दिया कि कांस्टेबल कारिंदों को नियमित बल में समायोजित करने पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं आएगा.

नाम न छापने की शर्त पर इंडिया टुडे से बात करने वाले कुछ प्रभावित कॉन्स्टेबलों ने कहा कि उन्हें उनके ''अधिकार'' से इसलिए वंचित किया जा रहा है ताकि बड़े अफसरों को अपने घरों पर सेवा-चाकरी करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी मिल सकें. हालांकि एक बड़े अफसर इससे उलट मिसालों की तरफ इशारा करते हैं जिनमें हाल ही घरेलू ड्यूटी से हटाए गए कुछ कॉन्स्टेबलों ने उन्हीं कामों में बहाल करने की गुजारिश की क्योंकि वहां काम का बोझ ''हल्का'' था.

एमपी के आइपीएस अफसर पूरा जोर लगा रहे हैं कि घरेलू सेवा-चाकरी के लिए पुलिस बल में निचले पदों से लिए गए कर्मियों को वापस न करना पड़े

एसएएफ के एडिशनल डायरेक्टर जनरल साजिद फरीद शापू इस मुद्दे पर बस इतना भर कहते हैं कि ''मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता लेकिन संज्ञान में लाए जाने पर कोई भी नाइंसाफी निश्चित ही दुरुस्त की जाएगी.'' पुलिस मुख्यालय के एक और बड़े अफसर का कहना है कि ''जनरल ड्यूटी कॉन्स्टेबल के तौर पर लिए जाने के विकल्प का अधिकार के तौर पर दावा नहीं किया जा सकता.'' वजह? इसलिए क्योंकि यह 1993 में ''उस वक्त कुछ निश्चित मुद्दों पर विचार करते हुए'' दिया गया था और बाद में वापस ले लिया गया. अलबत्ता ''इन दोनों मुद्दों को अलग करने की जरूरत'' पर जोर देते हुए वे इतना स्वीकार करते हैं कि ''बड़े अफसरों के घरों पर काम करने वाले सहायकों की फौजों को किसी भी तरह सही नहीं ठहराया जा सकता''.

इसके अलावा यह मुद्दा राज्य की माली हालत पर भी असर डालता है. अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी घरेलू सहायकों की फौज रखने के लिए जाने जाते हैं. मगर आइएएस और वन सेवा के विपरीत, आइपीएस अधिकारियों के पास आउटसोर्स किए गए ''सस्ते'' स्टाफ के बजाय ज्यादातर कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल और कुछ मामलों में असिस्टेंट इंस्पेक्टर होते हैं.

इसका नतीजा यह है कि इन 'घरेलू सेवाओं' का भारी-भरकम बिल आ रहा है. मिसाल के तौर पर कॉन्स्टेबल को हर महीने करीब 25,000 रुपए तनख्वाह मिलती है. एएसआइ के मामले में यह 70,000 रुपए जितनी ज्यादा है. उनमें से ज्यादातर बगीचे की साज-संभाल, खाना बनाने या साफ-सफाई सरीखे काम कर रहे हैं, जिनके लिए 10,000 रुपए जितनी कम तनख्वाह पर आउटसोर्स किए गए कर्मचारी रखे जा सकते हैं. ऐसे कदम से न केवल वर्दी की इज्जत बहाल होगी बल्कि कॉन्स्टेबल कारिंदे नियमित पुलिसबल में समायोजित किए जाने के लिए मुक्त हो जाएंगे. और इस तरह से पुलिस के मूल कामों के लिए अतिरिक्त कर्मी मिल जाएंगे. मगर सवाल है कि क्या आइपीएस लॉबी टस से मस होगी? ■

इलस्ट्रेशन: सिद्धांत जुमडे

manipalhospitals
LIFE'S ON

ऑर्गन ट्रांसप्लांट

में आशा की नई किरण मणिपाल हॉस्पिटल, जयपुर

किसी को नया जीवन देना–इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है? सैकड़ों लोग, जो अंतिम चरण के ऑर्गन फेलियर से जूझ रहे हैं, उन्हें और उनके परिवार को अंग दान के माध्यम से एक उम्मीद दी जा रही है। इस नेक काम के जरिए कोई भी व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद भी इस संसार में मौजूद रह सकता है। जिंदा और साथ ही साथ ब्रेन डेड व्यक्ति भी अंग दान करके, लोगों की जान बचा सकता हैं।

डॉ. शैलेंद्र लालवानी (एचओडी और कंसल्टेंट - लिवर ट्रांसप्लांट एंड हेपेटो-पैंक्रिएटिक बिलियरी सर्जरी) और डॉ. जितेंद्र गोस्वामी (कंसल्टेंट - नेफ्रोलॉजी, मणिपाल हॉस्पिटल्स, जयपुर) ने ऑर्गन डोनेशन और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के महत्व पर चर्चा की और बताया कि कैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट में प्रगति आखिरी स्टेज के लिवर और किडनी की बीमारी से जूझ रहे लोगों में आशा की किरण जगा रहा है।

डॉ. शैलेंद्र लालवानी (एचओडी और कंसल्टेंट - लिवर ट्रांसप्लांट एंड हेपेटो-पैंक्रिएटिक बिलियरी सर्जरी) समझाते हैं, ''वो रोगी जो अंतिम स्टेज लिवर की बीमारी से पीड़ित हैं, उनके लिए लिवर ट्रांसप्लांट सबसे बेहतर विकल्प है। मेडिकल टेक्नोलॉजी और सर्जिकल टेक्निक में प्रगति होने से, लिवर ट्रांसप्लांट अब अधिकांश रोगियों, खासकर अंतिम स्टेज के लिवर की बीमारी से जूझ रहे लोग, यहां तक कि जो एचआईवी पॉजिटिव हैं या जिनके ब्लड ग्रुप को लेकर समस्या है, उनके लिए भी एक बेहतर विकल्प बन गया है।

अन्य बीमारियों से जूझ रहे लोगों की तुलना में, हेपेटाइटिस से पीड़ित रोगियों में एंटीवायरल उपचार के कारण, लिवर ट्रांसप्लांट के बाद जिंदा रहने की संभावना अधिक होती है। रोगियों की सावधानीपूर्वक स्क्रीनिंग से, एल्कोहलिक सिरोसिस के मरीजों को भी, लिवर ट्रांसप्लांट के जरिए एक नया जीवन जीने का अवसर मिलता है। क्लीनिकल एक्सीलेंस में प्रगति के कारण, लिवर ट्रांसप्लांट अब जीवित डोनर के साथ-साथ ब्रेन डेड डोनर के साथ भी संभव है। लिवर ट्रांसप्लांट से कई लोगों को नई उम्मीद और अधिक सक्रिय जिंदगी मिली है।

वैसे तो एडल्ट रोगियों में सिरोसिस और लिवर का खराब होना अधिक आम बात है, लेकिन बच्चे भी कभी-कभी गंभीर

हुआ मैं साहब उखबार

ऑर्गन प्रोक्योरमेंट ऑफ ट्रांसप्लांट नेटवर्क के अनुसार (ओ पी टी एन, 2015), एक ब्रेन डेड डोनर द्वारा डोनेट किये गए ऑर्गन से आठ लोगों को जान मिल सकती है। इसके अलावा ऑर्गन डोनेशन वैश्विक प्राथमिकता भी है फिर भी भारत और दुनिया के बाकी सभी देशों में ऑर्गन की आपूर्ति से ज्यादा ऑर्गन की मांग है। भारत में ऑर्गन डोनेशन रेट 0.80 लोग प्रति मिलियन है। ऑर्गन डोनेशन को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी के कारण ये आकड़े कम हैं। इसलिए लोगों को ऑर्गन डोनेशन से अवगत कराना महत्वपूर्ण है। ये ज़िन्दगी बदल सकता है। मणिपाल हॉस्पिटल्स जयपुर, राजस्थान के उन चुनिंदा अस्पतालो में से एक है जिनमे सौ से भी ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट हुए हैं और जहां नियमित रूप से लिवर ट्रांसप्लांट होता है। हम ऑर्गन डोनेशन की वकालत करते है, उसका परिणाम ये है की हमने पिछले छह महीनो में तीन ब्रेन डेड ऑर्गन डोनेशन परफॉर्म किए हैं (2 किडनी ट्रांसप्लांट और 1 लिवर ट्रांसप्लांट)।''

– रंजन ठाकुर (हॉस्पिटल डायरेक्टर, मणिपाल हॉस्पिटल्स, जयपुर)

मणिपाल अस्पताल ब्रेन डेड लोगों के अंग दान और ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहा है। यह वास्तव में अद्भुत है कि उन्होंने जीवन बचाने को एक उद्देश्य के रूप में लिया है और इसके लिए वो पूरी लगन और नैतिक रूप से काम कर रहे हैं।''

– डॉ अनीता हाड़ा (प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एमएफजेसीएफ- मोहन फाउंडेशन जयपुर सिटीजन फोरम)

लिवर फेलियर के शिकार हो सकते हैं। इसके इलाज के लिए अब बच्चों का पीडियाट्रिक लिवर ट्रांसप्लांट करना संभव है, जिसके जरिए खराब हो चुके लिवर को एक स्वस्थ लिवर के साथ बदल दिया जाता है। इसके अलावा, रोबोटिक डोनर हेपेटेक्टोमी (लिवर के हिस्से को निकालने के लिए सर्जरी) और रोबोटिक-असिस्टेड लिवर ट्रांसप्लांट ने इस सर्जरी के दौरान होने वाले दर्द को काफी हद तक कम कर दिया है, जिससे डोनर और रिसीवर, दोनों के रिकवरी समय में सुधार हुआ है।

इस तरह के सफल ट्रांसप्लांट को करने के लिए हमारे पास एक बड़ी टीम है, जिसमें डॉ. संदीप कुमार झा (लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी), डॉ. ललित सहगल (मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी), डॉ. शंकर लाल जाट (कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी), डॉ. रोहित सुरेका (मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी) और डॉ. मोनिका गुप्ता (सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी) शामिल हैं।''

लास्ट स्टेज की किडनी की बीमारी वाले मरीजों के लिए किडनी ट्रांसप्लांट सबसे अच्छा विकल्प है। डॉ. जितेंद्र गोस्वामी (कंसल्टेंट - नफ्रोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन, मणिपाल अस्पताल, जयपुर)कहते हैं , ''यह शायद ट्रीटमेंट का एकमात्र तरीका है, जिसके जरिए रोगियों की पूरी किडनी ठीक ढंग से काम करने लगती है। साथ ही साथ उनके जीवन जीने के तरीके में भी काफी सुधार होता है।

एक सफल किडनी ट्रांसप्लांट रोगी को एक नयी ज़िन्दगी दे सकती है। इसके अलावा, यह उन्हें रोज की गतिविधियों पर अधिक नियंत्रण देकर और डायलिसिस की आवश्यकता को खत्म करके, उन्हें बेहतर जिंदगी प्रदान करती है। जीवन जीने की उम्मीद छोड़ चुके कई लोगों के लिए, अब किडनी ट्रांसप्लांट संभव है, जो कि मेडिकल रिसर्च में तरक्की के कारण हो पाया है। रुटीन किडनी ट्रांसप्लांट के अलावा, अब हम उन रोगियों, जिनका डोनर से ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता, उनका भी किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। साथ ही कम दर्द वाली सर्जरी के जरिए हम पीडियाट्रिक किडनी ट्रांसप्लांट और किडनी नेफ्रेक्टोमी भी करते हैं।

यहां तक कि जरूरत पड़ने पर हम एक ही मरीज पर बार-बार किडनी ट्रांसप्लांट भी कर रहे हैं। हालिया सर्जिकल तकनीकों के जरिए डोनर और रिसीवर दोनों के रिकवरी टाइम में सुधार हुआ है। डोनर को अब ट्रांसप्लांट के 2-3 दिनों के भीतर ही छुट्टी दे दी जाती है।

मणिपाल हॉस्पिटल्स, जयपुर में हमने अब तक 100 से अधिक किडनी ट्रांसप्लांट को सफलतापूर्वक करने की उपलब्धि हासिल की है। जिसका श्रेय डॉ. ज्योति बंसल (कंसल्टेंट - यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट सर्जरी), डॉ. डीआर धवन (कंसल्टेंट - यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट सर्जरी), डॉ श्याम सुंदर नोवल (कंसल्टेंट - नेफ्रोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन) और डॉ राम सरन चतुर्वेदी (कंसल्टेंट - एनेस्थीसिया एंड ECMO स्पेशलिस्ट) को जाता है।''

दुआ मंगल स्वयं

राजस्थान में मृतक अंग दान और ट्रांसप्लांट कार्यक्रम साल 2015 में शुरू किया गया था और स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट संगठन, राजस्थान की स्थापना साल 2019 में की गई थी। मौजूदा समय में पूरे राजस्थान में 14 ट्रांसप्लांट सेंटर काम कर रहे हैं और राज्य सरकार राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी (RAJMES) कॉलेजों को या तो ट्रांसप्लांट सेंटर या नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर में बदलने की योजना बना रही है। SOTTO राजस्थान की स्थापना के बाद से ब्रेन डेड लोगों का अंग दान और ट्रांसप्लांट कार्यक्रम नई बुलंदियों पर पहुंच गया है।

अंगदान के आंकड़े:

कैडेवरिक		(कुल- 51)	
किडनी	- 95	लीवर	- 45
दिल	- 27	फेफड़े	- 04
पैंक्रियास	- 01	हार्ट वाल्व	- 02
कॉर्निया (आंख का हिस्सा)	-14		

मैं अंगदान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए मणिपाल अस्पताल की सराहना करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि SOTTO राजस्थान और मणिपाल इस जीवन पहल कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।''

–डॉ मनीष शर्मा (स्टेट ऑर्गन एवं टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन)

मैनपुरी लोकसभा
उपचुनाव के दौरान एक रैली में मौजूद अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य

मनीष अग्निहोत्री

समाजवादी पार्टी

पिछड़ों-दलितों में अगड़ा बनने का दांव

राष्ट्रीय कार्यकारिणी के ऐलान के जरिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने स्पष्ट की पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग. परिवार को साथ लेकर आगे बढ़ने की रणनीति

आशीष मिश्र

वैसा हुआ नहीं जैसी कि अटकलें थीं. समाजवादी पार्टी (सपा) के विधान परिषद सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य ने तुलसीदास के लोकप्रिय ग्रंथ रामचरितमानस को जातिवादी बताकर पूरे सियासी हलके में बावेला मचा दिया था. 28 जनवरी को लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग स्थित सपा कार्यालय में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और मौर्य के बीच बंद कमरे में मुलाकात हुई तो लगा कि इस संवाद के बाद मौर्य का 'मानस' बदलेगा और मानस पर चल रहे विवाद का पटाक्षेप होगा. पर हुआ लगभग उलटा. मुलाकात के बाद बाहर निकलकर दोनों नेताओं ने जाति जनगणना पर बयान दिया. और फिर अखिलेश ने लखनऊ में गोमती नदी के किनारे झूलेलाल घाट पीतांबरा महायज्ञ स्थल की परिक्रमा करने के बाद बयान दिया ''भाजपा पिछड़ों और दलितों को शूद्र मानती है.'' इस बयान से ही सपा की आगे की रणनीति का संकेत मिलने लगा था. करीब 24 घंटे बाद जब अखिलेश ने 64 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान किया तो साफ हो गया कि पिछड़ों और दलितों के बीच जनाधार बढ़ाकर सपा यूपी में अपना पुराना गौरव वापस लाना चाहती है.

सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जरिए अखिलेश ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण साधने की भरपूर कोशिश की है. स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बनाकर अखिलेश ने स्पष्ट

जातियों में ऐसे दौड़ी साइकिल

- वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में कुल 52 ब्राह्मण विधायक जीते जिनमें 5 सपा के हैं. ठाकुर समाज से जीतने वाले 49 विधायकों में 4 सपा से हैं.
- सपा के टिकट पर 19 यादव नेता विधानसभा चुनाव जीते. कुल 41 कुर्मी विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे. इनमें 13 सपा गठबंधन से जीते.
- विधानसभा चुनाव जीतने वाले सभी 34 मुस्लिम विधायक सपा गठबंधन से ताल्लुक रखते हैं. इनमें अकेले सपा के 32 विधायक हैं.
- मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी बिरादरी से 2 नेता सपा विधायक बने. निषाद, बिंद, कश्यप, मल्लाह समाज से भी दो सपा विधायक जीते. कलवार, तेली, सोनार जाति से सपा गठबंधन का केवल 1 विधायक जीता.
- दलितों की जाटव बिरादरी से सपा गठबंधन के 10 विधायक और पासी बिरादरी से 8 विधायक जीते. खटीक समाज से सपा गठबंधन का एक विधायक जीता.

कर दिया कि मानस के कुछ प्रसंगों पर आपत्ति जताकर पिछड़ी और दलित जातियों का समर्थन पाने की रणनीति पर सपा की मौन सहमति है.

जातिगत समीकरणों की इसी बिसात में सपा का जोर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की जंग को 80 बनाम 20 करने का है. 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का साथ छोड़कर सपा में शामिल होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ा बनाम अगड़ा की बात कहकर 80 बनाम 20 की जंग का आह्वान कर रहे थे. विधानसभा चुनाव में उनका दांव नहीं चला और सपा गठबंधन महज 125 सीटें ही जीत सका लेकिन अब रामचरितमानस के जरिए इस जंग को आगे बढ़ाने की रणनीति है. हालांकि पार्टी कार्यालय में हुई बैठक में अखिलेश ने मौर्य को समझाया कि वे मानस के बहाने धार्मिक मसले को हवा न देकर ओबीसी आरक्षण और जातिगत जनगणना को पुख्ता ढंग से उठाएं ताकि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और दलितों को सकारात्मक संदेश पहुंच सके. इसी संदेश को स्पष्ट करते हुए अखिलेश ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल 64 चेहरों में 10 यादव, 5 कुर्मी और 16 अति पिछड़े वर्ग के लोगों को शामिल किया है. कार्यकारिणी में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के नेताओं की कुल संख्या 31 है यानी कार्यकारिणी की कुल संख्या की करीब आधी.

कार्यकारिणी में राष्ट्रीय महासचिव के कुल 14 पदों पर बहुप्रतीक्षित नाम जसवंतनगर से विधायक और सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव का है जिन्होंने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव का नतीजा आते ही अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) का सपा में विलय कर दिया था. राष्ट्रीय महासचिव पद पर यादव समाज से शिवपाल के अलावा बलराम सिंह यादव, कुर्मी समाज से लालजी वर्मा और रवि प्रकाश वर्मा, जाट समुदाय से हरेंद्र मलिक और नीरज चौधरी को जगह दी गई है. पिछड़ी जाति राजभर, मौर्य और निषाद समाज से भी एक-एक नेता को जगह मिली है. दलित समाज से तीन राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं जिनमें अवधेश प्रसाद और इंद्रजीत सरोज पासी समाज से संबंध रखते हैं जबकि रामजीलाल सुमन जाटव हैं. राष्ट्रीय महासचिव पद पर आजम खान इकलौते मुस्लिम नेता हैं. लखनऊ के प्रतिष्ठिगत अवध कॉलेज की प्राचार्य और राजनीतिशास्त्र विभाग की प्रमुख डॉ. बीना राय बताती हैं, ''सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची पार्टी की विधानसभा चुनाव के दौरान अपनाई गई रणनीति का विस्तार है. कार्यकारिणी के बड़े पदों पर भले ही मुस्लिम प्रधिनिधित्व कम हो लेकिन यादव समाज की भांति मुस्लिम समुदाय की पहली पसंद सपा ही है. ऐसे में अखिलेश यादव ने पार्टी के परंपरागत वोट बैंक मुसलमान-यादव के साथ दलित और गैर यादव पिछड़ा की जुलगबंदी करने की कोशिश की है.''

''सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची पार्टी की विधानसभा चुनाव के दौरान अपनाई गई रणनीति का ही विस्तार है. संगठन के जरिए गैर यादव ओबीसी को साधने की भरपूर कोशिश की गई है''

–प्रो. बीना राय, प्रधानाचार्य, अवध कॉलेज, लखनऊ

लोकसभा चुनाव में गिरता गया प्रदर्शन

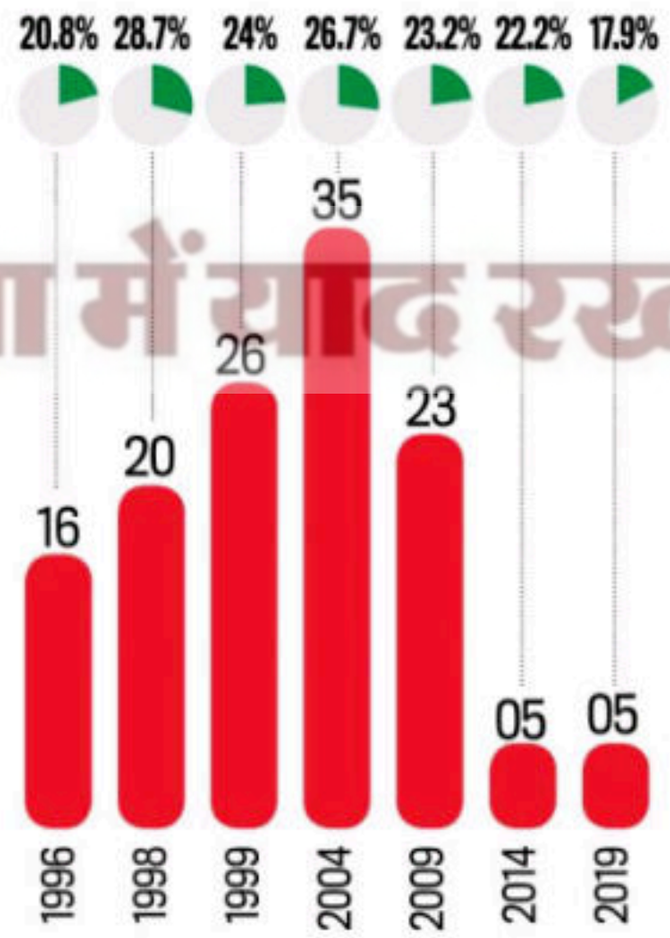

नोटः ये आंकड़े चुनाव आयोग के हैं. यूपी की कुल लोकसभा सीटें 80 हैं. वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव सपा ने बसपा के साथ मिलकर लड़ा था

वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के दलित वोट बैंक में तगड़ी सेंधमारी करने वाली सपा को अगले लोकसभा चुनाव में भी इसी वोट बैंक में बड़ी संभावनाएं नजर आ रही हैं. 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश लोहियावादियों और आंबेडकरवादियों का साथ लेने की घोषणा करते रहे हैं. इसी रणनीति के तहत उन्होंने बसपा से सपा में आए नेताओं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रमुखता से जगह दी है. कभी बसपा का गढ़ रहा आंबेडकर नगर जिला 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के मजबूत गढ़ में तब्दील हो गया. विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सपा में शामिल होने वाले बसपा नेता और पूर्व मंत्री राम अचल राजभर और लालजी वर्मा का साथ मिलते ही आंबेडकरनगर जिले की सभी पांचों सीटों पर साइकिल ने विरोधियों को धूल चटा दी थी. ऐसे में इस जिले के नेताओं को कार्यकारिणी में प्रमुखता मिलना लाजिमी था. यहां के चार विधायकों को कार्यकारिणी में जगह मिली है. अकबरपुर के विधायक रामअचल राजभर और कटेहरी के विधायक लालजी वर्मा को राष्ट्रीय महासचिव तथा टांडा के विधायक राममूर्ति वर्मा और आलापुर विधायक त्रिभुवन दत्त को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है. सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप कहते हैं, ''2022 के विधानसभा चुनाव में ओबीसी और दलित समुदाय के बीच सपा के जनाधार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और इसी सिलसिले को आगे जारी रखने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं.''

अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची इस मायने में भी पहली है कि इससे मुलायम परिवार में एका का संदेश गया है. पिछली कार्यकारिणी में मुलायम सिंह यादव के चचेरे भाई रामगोपाल और उनके बेटे अक्षय ही शामिल थे लेकिन नई सूची में मुलायम के छोटे भाई शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव और तेज प्रताप सिंह यादव को भी शामिल किया गया है. कार्यकारिणी में कुल 10 यादव नेता हैं जिनमें छह मुलायम परिवार के ही हैं. प्रो. बीना राय बताती हैं, ''भाजपा लगातार सपा पर परिवारवाद का आरोप लगाती रही है पर अखिलेश ने जिस तरह से परिवार के नेताओं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी है, उससे साफ है कि सपा अब भाजपा के सामने आक्रामक राजनीति की रणनीति तय कर चुकी है.''

बहरहाल, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची ने सपा के भीतर असंतोष को भी शह दी है. शिवपाल के साथ सपा में आने वाले वरिष्ठ नेताओं और लंबे समय से जिम्मेदारी की आस तक रहे युवा नेताओं का समायोजन, गोरखपुर और बस्ती मंडल जैसे कई इलाकों का संगठन में कमजोर प्रतिनिधित्व जैसे कई मुद्दे हल होने के लिए सपा की प्रदेश कार्यकारिणी की सूची का इंतजार शुरू कर चुके हैं. ■

दुआ में याद रखना

भलाई की राजनीति
भारत जोड़ो यात्रा के दौरान चिरंजीवी योजना के लाभार्थियों से मिलते राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत

दुआ में याद रखना

राजस्थान

कैसे बना "चिरंजीवी" राजस्थान

आनंद चौधरी

भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 16 दिसंबर, 2022 को राहुल गांधी ने जब यह कहा कि राजस्थान में चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना ने लोगों के दिलों से डर मिटा दिया है तो उस वक्त बहुत से लोगों ने इसे महज एक राजनीतिक बयान से ज्यादा कुछ नहीं समझा. इससे पहले एक नवंबर को बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राजस्थान की चिरंजीवी योजना का परीक्षण करवाने और इसे पूरे देश में लागू करने की बात कही तब भी यह बात यूं ही राजनीतिक बयान की तरह आई गई हो गई. लेकिन बीती 18 जनवरी को नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (एनएचए) के सीईओ राम सेवक शर्मा ने जब चिरंजीवी योजना को देश की सबसे बेहतरीन योजना कहा तो पूरे देश की निगाहें इस योजना की तरफ टिक गईं.

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की यह तारीफ बेवजह नहीं है. इसे कुछ आंकड़ों से बड़ी आसानी से समझा जा सकता है. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे–4 के अनुसार वर्ष 2016-17 तक राजस्थान की महज 19 फीसदी आबादी स्वास्थ्य बीमा योजना से कवर थी जो अब बढ़कर 88 फीसदी तक पहुंच चुकी है. यानी, पिछले पांच-छह साल में राजस्थान में 69 फीसदी आबादी को स्वास्थ्य बीमा से जोड़ा गया है. इसी का नतीजा है कि पांच साल पहले स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में राजस्थान देश में 23वें नंबर पर था जो अब पहले पायदान पर पहुंच चुका है. बीमा कवरेज के मामले में राजस्थान ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में मॉडल माने जाने वाले केरल और आंध्र प्रदेश, जैसे राज्यों को पीछे छोड़ दिया है (देखें ग्राफ).

राजस्थान में स्वास्थ्य बीमा कवरेज पाने वाले परिवारों की तादाद राष्ट्रीय औसत से भी दो गुना ज्यादा है. देश में करीब 41 फीसदी आबादी स्वास्थ्य बीमा से कवर है वहीं राजस्थान की 88 फीसदी आबादी बीमित है. इस समय राजस्थान में कुल 1.75 करोड़ परिवारों में से 1.38 करोड़ परिवार मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े हुए हैं.

कई मायनों में राजस्थान की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से भी आगे है. आयुष्मान भारत योजना के तहत बीमित परिवार को 5 लाख रुपए तक के सालाना इलाज की सुविधा उपलब्ध है लेकिन चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 10 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा मिल रही है. आयुष्मान भारत में 1350 तरह के पैकेज और दवाइयां शामिल हैं जबकि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 1733 तरह की दवाइयां और पैकेज निशुल्क रूप से मिल रहे हैं. आयुष्मान भारत योजना में सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवारों को ही जोड़ा गया है जबकि चिरंजीवी योजना में अधिकांश आबादी को शामिल किया गया है.

आयुष्मान भारत योजना में अंग प्रत्यारोपण (ऑर्गन ट्रांसप्लांट) और दुर्घटना बीमा शामिल नहीं है जबकि चिरंजीवी योजना में ऑर्गन ट्रांसप्लाट और कॉकलेयर ट्रांसप्लांट (बहरेपन को दूर करने वाली सर्जरी) का पूरा खर्च सरकार की ओर से वहन किया जा रहा है. अंग प्रत्यारोपण की पूरी प्रक्रिया बेहद महंगी है. इस लिहाज से यह आम परिवारों के लिए बहुत बड़ी आर्थिक चुनौती बन सकती है. हालांकि चिरंजीवी जैसी योजना के चलते ऐसे कई लोग इस चुनौती से आसानी से पार पा रहे हैं. जयपुर के रामसिंहपुरा गांव के मोहन लाल मीणा का मामला ऐसा ही है. 34 साल के मोहन लाल की पिछले दो साल में हार्ट और किडनी की दो बड़ी सर्जरी हो चुकी हैं. अक्तूबर 2021 में उनकी हार्ट सर्जरी हुई और

बड़े राज्यों में स्वास्थ्य बीमा के दायरे में आबादी

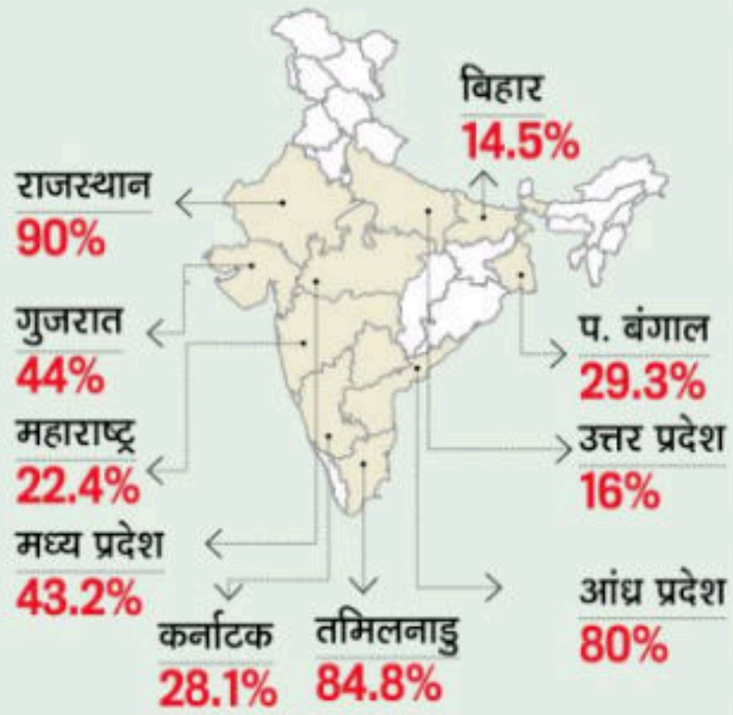

राजस्थान के 1.25 करोड़ लोगों का मुफ्त बीमा

एक साल बाद ही अगस्त 2022 में उनकी एक किडनी के खराब हो जाने पर पिता की किडनी ट्रांसप्लांट की गई. निजी अस्पतालों में हुई इन दोनों सर्जरी पर 30 लाख रुपए से ज्यादा राशि खर्च हुई लेकिन राजस्थान चिरंजीवी योजना के तहत हुए इस इलाज के लिए मोहन लाल को एक रुपया भी नहीं देना पड़ा. एक टेंट हाउस में काम करने वाले मोहन लाल कहते हैं, ''अगर चिरंजीवी योजना नहीं होती तो मैं अपना घर और जमीन बेचकर भी इलाज नहीं करवा पाता.''

जयपुर की ही 19 साल की अंतिमा पिछले दो साल से फेफड़ों के कैंसर से लड़ाई लड़ रही हैं. उनका इलाज जयपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है. अब तक अंतिमा के इलाज पर 7 लाख रुपए खर्च हुए हैं जिसका पूरा वहन राजस्थान चिरंजीवी योजना के तहत हुआ है. भविष्य में भी अंतिमा के इलाज पर जितना खर्चा होगा वह इसी योजना के तहत किया जाएगा. कैंसर जैसी घातक बीमारियों के इलाज के साथ ही लाभार्थी परिवार का पांच लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी इस योजना में शामिल है.

मुफ्त दवा व जांच लागू करने में पहला राज्य

देश में मुफ्त दवा व जांच प्रणाली लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने दूसरे कार्यकाल में 2 अक्तूबर 2011 को मुफ्त दवा योजना लागू की थी. शुरुआत में 971 तरह की दवाइयां व सर्जिकल आइटम इस योजना में शामिल किए गए थे लेकिन बाद में धीरे-धीरे इनका दायरा बढ़ाकर 1500 तक कर दिया गया. मुफ्त दवा योजना की सफलता को देखते हुए राज्य सरकार ने 7 अप्रैल, 2013 को प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में निशुल्क जांच योजना भी शुरू कर दी. शुरुआत में इस योजना में 271 तरह की जांचें शामिल हुईं बाद में इस श्रेणी में सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी महंगी जांचों को भी शामिल कर लिया गया. इस बार सरकार ने इसके आगे जाकर निजी अस्पतालों में भी निशुल्क जांच के लिए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की है.

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत आने वाले करीब 1 करोड़ 25 लाख परिवार ऐसे हैं जिनसे किसी तरह का प्रीमियम नहीं लिया जाता. राजस्थान में महज 13 लाख 20 हजार परिवार ऐसे हैं जिनसे 8 50 रुपए सालाना प्रीमियम लिया जाता है तथा बदले में उन्हें किसी भी सरकारी और निजी अस्पताल में भर्ती होने पर 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है. 1 मई, 2021 को शुरू हुई इस योजना से 846 सरकारी और 874 निजी अस्पताल जुड़े हैं. इस योजना के तहत राजस्थान में बीमित परिवारों को सरकारी और निजी अस्पतालों में 10 लाख रुपए तक की कैशलेस सुविधा उपलब्ध है. हार्ट, किडनी जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने पर कैशलेस सुविधा 10 लाख रुपए से ज्यादा भी हो सकती है.

इसी का नतीजा है कि अंतिमा और मोहन लाल जैसे 32 लाख लोगों का चिरंजीवी योजना के कारण मुफ्त इलाज संभव हो पाया है और इसी कारण यूनिवर्सल हेल्थ केयर मॉडल में राजस्थान की देश में अलग पहचान बनी है. ■

एएसईआर 2022

सबक दे गया महामारी का दौर

लगता है महामारी और लॉकडाउन ने ग्रामीण भारत के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की पढ़ाई को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है. वर्ष 2023 में जारी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 से कुछ परेशान करने वाले संकेत मिलते हैं:

नोटः इस राष्ट्रव्यापी सर्वे में 616 ग्रामीण जिलों के 19,060 गांवों में 6,99, 597 बच्चों (3-16 आयुवर्ग) को शामिल किया गया है

ग्राफिक: लक्ष्य चक्रवर्ती

"दुआ" शाहरुख खान

रंजन राही

बातचीत/उपेंद्र कुशवाहा

'चंद लोग नीतीश जी को डिक्टेट करते हैं'

"दुआ में याद रखना"

उपेंद्र कुशवाहा बिहार की गठबंधन सरकार, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री, 62 वर्षीय कुशवाहा कभी भी अपना रास्ता बदल सकते हैं. वे ऐसा पहले भी कर चुके हैं. वे मार्च 2021 में अपनी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जद (यू) में विलय करने से पहले 2009-13 के दौरान जद (यू) के साथ रह चुके हैं. बताया जाता है कि वे मंत्रिमंडल में शामिल न किए जाने और नीतीश कुमार की ओर से राजद नेता तेजस्वी यादव को अपने उत्तराधिकारी के रूप में प्रोत्साहित करने से परेशान हैं. विशेष संवाददाता **पुष्यमित्र** *ने उनके घर पर उनसे उनके असंतोष की वजह और भावी योजनाओं के बारे में बातचीत की. पेश है कुछ अंश:*

● आपकी नीतीश कुमार से आखिर नाराजगी क्या है?

पहली नाराजगी तो यह है कि वे पार्टी खुद नहीं चला रहे. पार्टी में ज्यादातर फैसले दूसरे लोग ले रहे हैं. नीतीश जी को उनके आसपास के लोग डिक्टेट करते हैं. इस बात पर हमें ऐतराज है. इसके अलावा राजद के कई नेता सार्वजनिक रूप से एक डील की चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़ें और तेजस्वी को सौंप दें. इन लोगों का दावा है कि महागठबंधन के वक्त यह डील हुई थी. इसको लेकर लोगों में, खास कर जद (यू) कार्यकर्ताओं में काफी कन्फ्यूजन है. अगर इस मामले पर एक तरफ से चुप्पी रहेगी तो दिक्कत होगी, इसलिए इस संबंध में स्थिति जल्द स्पष्ट होनी चाहिए.

● चर्चा तो यह भी थी कि जब तेजस्वी सीएम बनेंगे तो जद (यू) की तरफ से आपको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा. अब क्या उस डील में कोई दिक्कत आ गई?

यह मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है कि वे किसको कहां फिट करेंगे. यह बड़ा विषय नहीं है. बड़ा विषय वह है जो राजद की तरफ से नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कहा जा रहा है.

● आप कहते हैं कि पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर जद (यू) आपको निकाल दे तो फिर कहां जाएंगे?

हमको ऐसा नहीं लगता. भले पांच वोट का हो या पच्चीस का, मेरे रहने से पार्टी को फायदा तो होता ही है. ऐसे में पार्टी हमें क्यों निकालेगी.

● चर्चा है कि आप लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के साथ जा सकते हैं.

न-न, अभी तो जद (यू) की मजबूती के लिए हम अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं. मुख्यमंत्री जी पर मेरा भरोसा अभी भी है. हम उनसे ही आग्रह कर रहे हैं. करोड़ों लोगों के अरमानों की पार्टी को बचा लीजिए. अभी तो हम इसी अभियान में लगे हैं और इस उम्मीद के साथ कि नीतीश जी निश्चित रूप से इस दिशा में कोई कदम उठाएंगे.

● क्या कुशवाहा जाति यह मानती है कि उसकी सत्ता में भागीदारी अभी बाकी है?

अगर बहुत सारे लोगों को यह बात लगती है तो उनकी बातों को खंडन हम क्यों करें. स्वाभाविक तौर पर देखें तो त्रिवेणी संघ जो बना था, उसका एक मकसद था. इस मकसद को पूरा करने के लिए लालू जी ने भूमिका निभाई, नीतीश जी ने भूमिका निभाई तो स्वाभाविक रूप से बचे हुए लोगों को लगेगा कि हमारी भी भूमिका होनी चाहिए.

● और कुशवाहा जाति के सबसे बड़े नेता आप हैं?

नहीं, हम खुद को उस रूप में नहीं मानते मगर समाज की अपेक्षा तो रहती है.

● तो आपका समाज चाहता है कि आप बिहार के सीएम बनें?

हम सीएम बनें या न बनें यह सवाल नहीं है, मगर समाज के लोग चाहते हैं कि कोई न कोई उनके बीच से हो.

● अगले पांच साल में दोनों बड़े चुनाव के बाद खुद को कहां देखना पसंद करेंगे. केंद्र में मंत्री या बिहार में सीएम-डिप्टी सीएम?

उधर मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं है, मगर मेरा ध्यान इस तरफ जरूर है कि लोगों के हितों की रक्षा के लिए, जो भी दबे कुचले लोग हैं, उनकी बेहतरी के लिए जहां भी मेरी आवश्यकता हो उस भूमिका में रहूं. ■

इलस्ट्रेशनः सिद्धांत जुमडे

समाचार सार

बायजू को अब मिला चैन

भारत जोड़ो यात्रा पूरी होने पर कांग्रेस में सबसे ज्यादा राहत अगर किसी को महसूस हुई है तो वे हैं के. बी. बायजू. वैसे तो वे पार्टी में किसी पद पर नहीं हैं लेकिन यात्रा के मार्ग और लॉजिस्टिक्स का सारा जिम्मा उन्हीं का था. वे राहुल और दूसरी सांगठनिक इकाइयों, बुनियादी सपोर्ट सिस्टम और राज्य पुलिस बलों के बीच मुख्य कड़ी थे. राहुल गांधी के स्पेशल पुलिस प्रोटेक्शन ग्रुप के पूर्व सदस्य 55 वर्षीय बायजू 2007 में राहुल के पार्टी महासचिव बनने के बाद से उनकी टीम का अभिन्न हिस्सा बन गए और सुरक्षा की निगरानी कर रहे हैं. मीडिया से कोसों दूर रहने वाले बायजू को सोनिया और प्रियंका गांधी का भी भरोसा हासिल है क्योंकि उनको जितना कहा जाता है, वे उतना ही करते हैं. यात्रा भी उन्होंने निर्विघ्न संपन्न करवा ही दी.

करें तो क्या करें कैप्टन

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन **अमरिंदर सिंह** के बारे में खबर उड़ गई कि उन्हें भगत सिंह कोश्यारी की जगह महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया जा सकता है. कैप्टन के करीबियों का दावा है कि अब तक भाजपा आलाकमान की ओर से सिंह को इस बारे में कोई सूचना नहीं मिली है. ऐसे में उनकी दुविधा बढ़ गई है. कैप्टन तय नहीं कर पा रहे कि पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रमों में भागीदारी पहले की तरह ही रखनी है या खुद को सीमित कर लेना है. प्रदेश की आम आदमी पार्टी की सरकार और पंजाब को लेकर कांग्रेस की राजनीति पर कैप्टन लगातार आक्रामक रहे हैं.

चलो मुंबई में देखें

अपने तीखे बयानों के चलते यूपी में सुर्खियों में रहने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष और विधायक **ओमप्रकाश राजभर** आजकल समझ नहीं पा रहे कि करें क्या. 2017 में भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े पर उससे रिश्ते बिगड़े तो 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के साथ जुड़े. चुनाव बाद वहां भी दाल खट्टी हो गई. शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) के सपा में शामिल होने पर उनके सियासी दोस्त गिनती के बचे. गुणा-गणित लगाकर राजभर ने अब मुंबई की राह पकड़ी है. 29 जनवरी को वे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से उनके घर पर मिले. बताते हैं, बीएमसी चुनाव में वे ठाकरे का सहयोग करेंगे. अच्छा? देखते हैं.

बाबा लगने लगे प्यारे

राजस्थान में पांच साल तक विपक्ष की भूमिका निभाने वाले **डॉ. किरोड़ी लाल मीणा** उर्फ बाबा अचानक कई भाजपा नेताओं के चहेते बन गए हैं. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनियां और विधानसभा में विपक्ष के उप नेता राजेंद्र राठौड़ वगैरह ने पांच साल तक उनकी सुध नहीं ली पर इन दिनों वे उनका गुणगान कर रहे हैं. इसकी वजह है. पेपर लीक मामलों की आवाज उठाते-उठाते वे युवाओं के चहेते बन गए हैं. 10 महीने बाद विधानसभा चुनाव हैं. तभी तो राठौड़ जहां किरोड़ी के साथ धरने में पहुंच गए तो राजे ने बयान जारी कर किरोड़ी का साथ निभाने का वादा किया.

चीते की चाकरी

नामीबियाई चीतों की एक खेप तो कूनो नेशनल पार्क पहुंच ही चुकी है. अगली खेप लाने के लिए एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल फरवरी में दक्षिण अफ्रीका जाने की तैयारी में है. इसके लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जिन सदस्यों के नाम तय किए हैं, उनमें सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी अनीश गुप्ता भी हैं. वे शीर्ष अधिकारी, वन महानिदेशक सी.पी. गोयल के दामाद हैं. तर्क है कि उनके जाने से कस्टम संबंधी औपचारिकताएं आसानी से पूरी हो जाएं. पर ये औपचारिकताएं तो भारत लौटने पर बंदरगाह पर पूरी करनी होंगी. तो क्या आगे से हर आयात के लिए सीमा शुल्क अधिकारी साथ जाएगा?

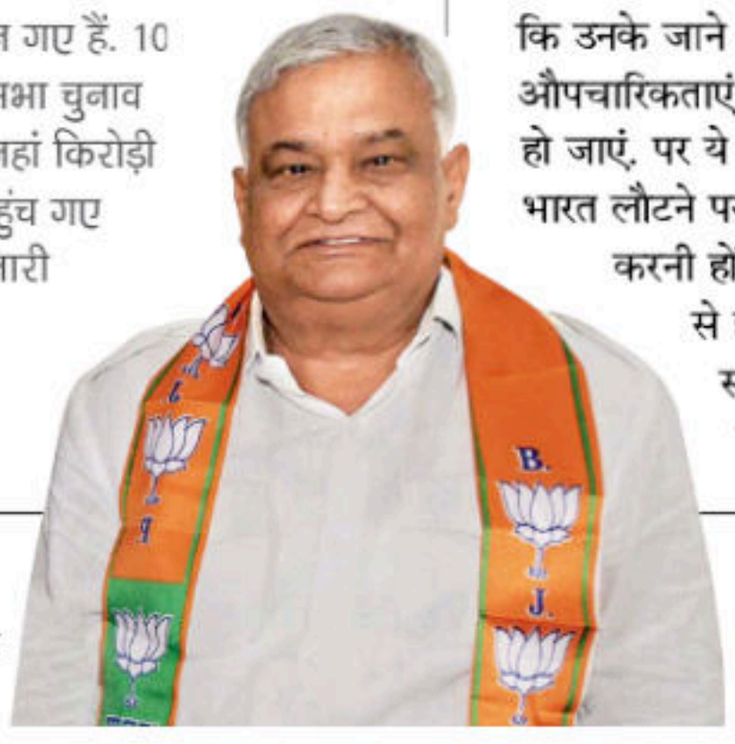

पुरुषोत्तम दिवाकर

–कौशिक डेका, साथ में आशीष मिश्र, हिमांशु शेखर, आनंद चौधरी और राहुल नरोन्हा

"दूसरा मंदराचल"

बजट 2023

रोजगार को भारी तवज्जो

कड़े राजकोषीय संतुलन की हिमायती मोदी सरकार ने रोजगार और नौकरियां पैदा करने के लिए प्रमुख क्षेत्रों में पूंजीगत खर्च में इजाफा किया, कामयाबी इस पर निर्भर कि अमल कितना माकूल हो पाता है

एम.जी. अरुण | फोटोः चंद्रदीप कुमार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2023 पेश करने खड़ी हुईं, तो हर कोई जानता था कि यह संतुलन साधने की मुश्किल कवायद होने वाली है. भले इस वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7 फीसद रहने का अनुमान है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ऊंची है और वित्त मंत्री ने खुद उसे दुनिया में ''चमकता सितारा'' कहा है, मगर उन्हें कई अहम मसलों से टकराना है. कोविड-19 और रूस के युक्रेन युद्ध की वजह से भारी महंगाई और तीखी आर्थिक ढलान के चलते दुनिया भर में छाई मंदी के साए लंबे होते जा रहे हैं. जी-20 देशों के ताकतवर समूह का अध्यक्ष होने के नाते भारत के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में देशों के रुख में फर्क पाटने और भरोसा बहाली की प्रेरणा बनना भी बेहद जरूरी है. यह साल नरेंद्र मोदी के लिए राजनैतिक तौर पर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नौ राज्यों के विधानसभा और 2024 में आम चुनाव भी होने हैं. विपक्ष, खासकर कांग्रेस बढ़ती बेरोजगारी के साथ-साथ महंगाई के लिए सरकार पर बुरी तरह हमलावर है.

मकसद पर नजर
बजट 2023 पेश करने संसद पहुंचतीं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

काम की चिंता

हर साल 1.2 करोड़ की तादाद नौकरी/काम मांगने वालों की जमात में शामिल हो रही. ऐसे में देश में बेरोजगारी के हालात और बिगड़ते जा रहे

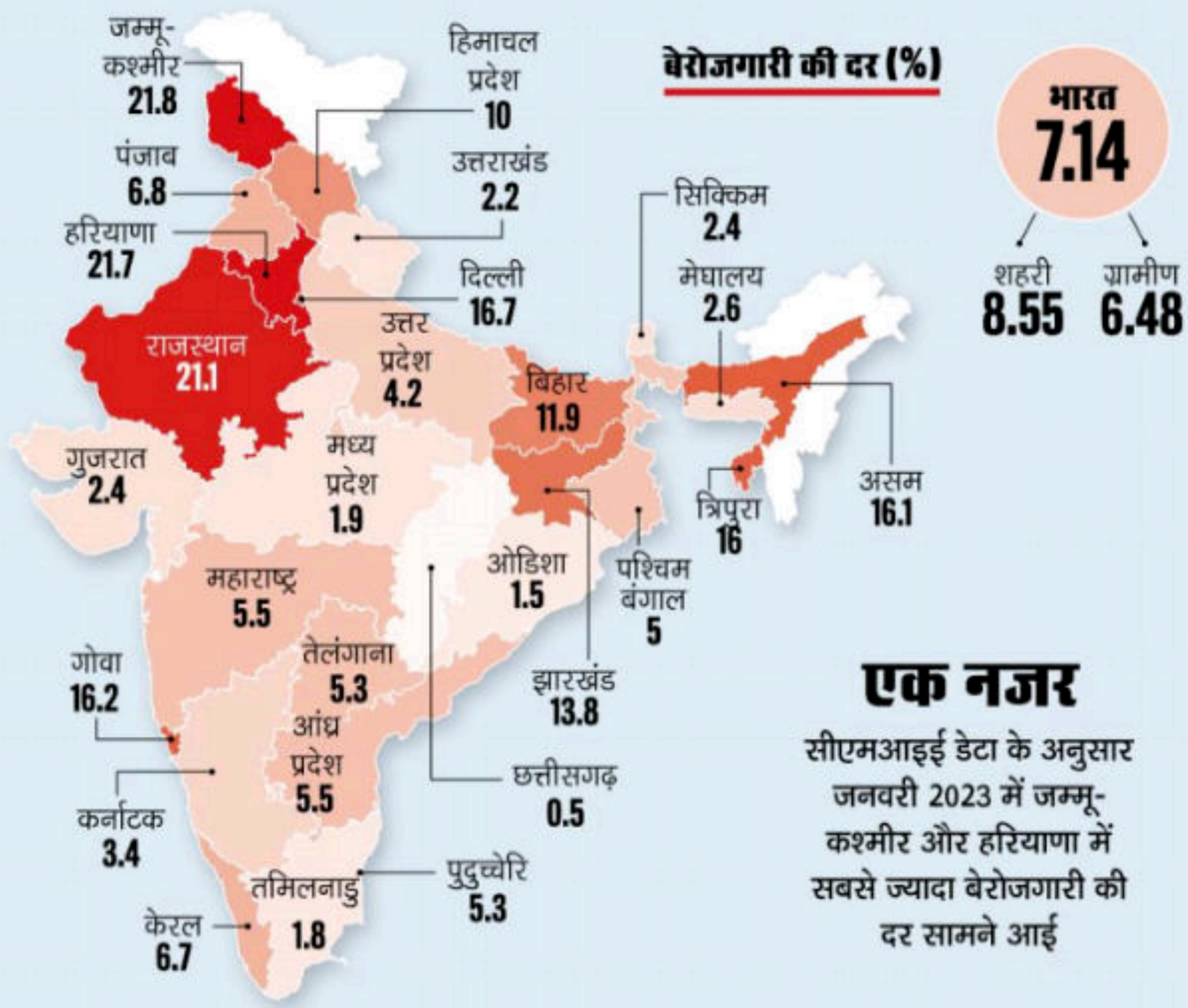

एक नजर

सीएमआइई डेटा के अनुसार जनवरी 2023 में जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर सामने आई

उफ, इतने बेरोजगार!

रोजगार मांगने वालों की तादाद पिछले साल के आखिरी महीने में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई

हाथ धरे बैठे नौजवान

कोविड के बाद से युवाओं में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा हो गई है. 50 फीसद तक युवाओं में बेरोजगारी देखी गई है

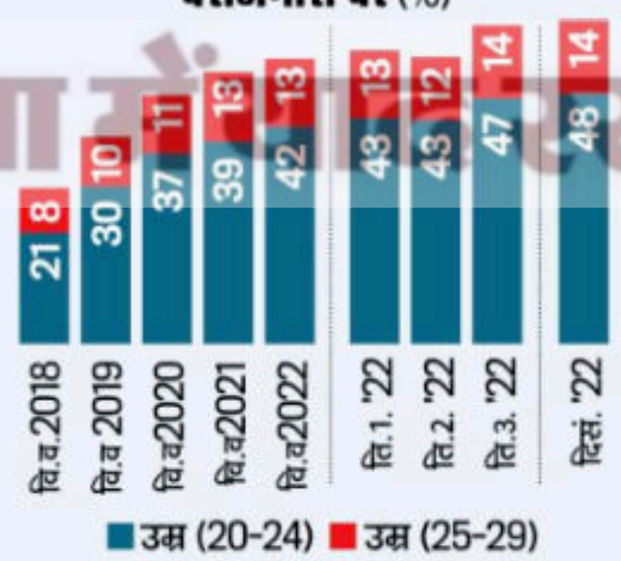

महिलाओं पर ज्यादा चोट

पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में बेरोजगारी दर ज्यादा है. कोविड के दौरान इसमें 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई

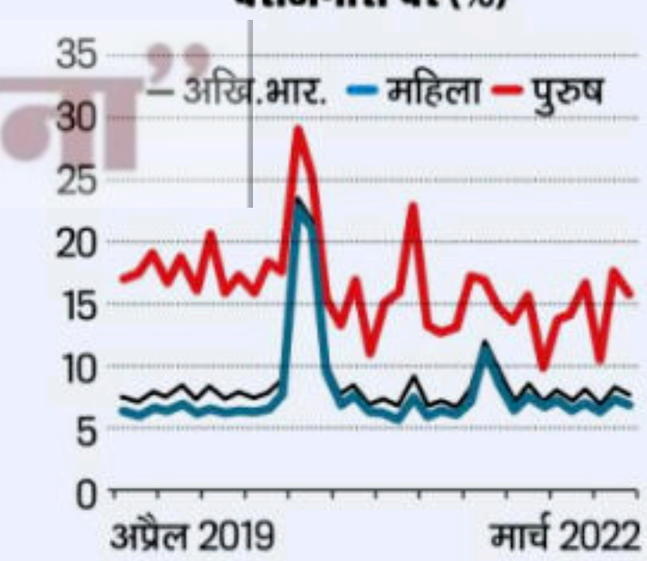

"दुआ में याद रखना"

कामकाजी आबादी और श्रमबल

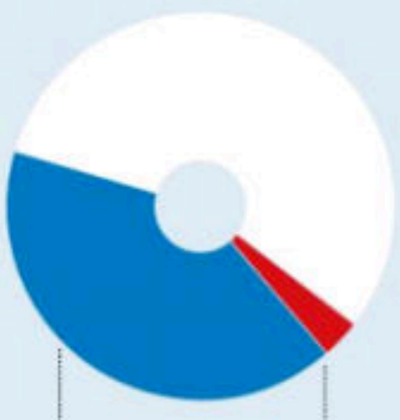

100 करोड़ भारत की कुल कामकाजी आबादी (15 वर्ष से ऊपर की उम्र के लोग)

41 करोड़ रोजगार में + **3.3 करोड़** बेरोजगार = **44.3 करोड़** श्रमिक बल (काम की तलाश में)

सेक्टरवार रोजगार का खाका

- 2009 में 52.5 फीसद कृषि में कार्यरत थे, 21.1 फीसदी उद्योगों में और 26.4 फीसद सर्विस सेक्टर में
- अब यह काफी बदल गया है. कृषि क्षेत्र में काम करने वाले 46 फीसद ही रह गए, उद्योग क्षेत्र में 21 फीसद ही हैं और सर्विस सेक्टर में बढ़कर 32.3 फीसद जा पहुंचा
- नीति आयोग का एक अध्ययन कहता है कि 2019-20 में 23.32 करोड़ लोग खेती में लगे थे, 12.12 करोड़ उद्योगों में और 15.75 करोड़ सर्विस सेक्टर में

कुल रोजगार में सरकारी नौकरियों का हिस्सा

(सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों की संख्या)

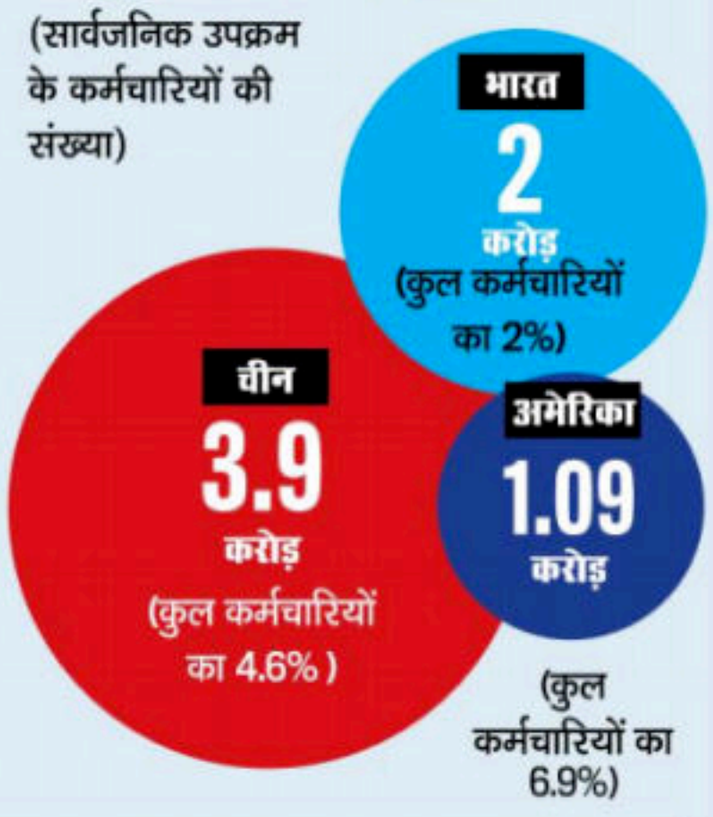

ग्राफिकः तन्मय चक्रवर्ती

स्रोतः सीएमआइई; मीडिया रिपोर्टें

एएनआइ

क्या इतना काफी है?
पटना में नौकरी पाने वाले कुछ युवा 20 जनवरी को रोजगार मेले में पीएम के कटआउट के साथ

अपने भाषण की शुरुआत में सीतारमण ने तीन महत्वपूर्ण आर्थिक एजेंडों का जिक्र किया, जो बजट का फोकस है. पहला, ''वृद्धि और रोजगार सृजन को सर्वाधिक प्रोत्साहन देना.'' पहले से ही जुड़ा दूसरा यह है कि ''देश के लोगों, खासकर युवाओं को अपनी आकांक्षाएं पूरी करने के लिए ढेर सारे अवसर मुहैया कराना.'' तीसरा, राजकोषीय घाटे को काबू में रखकर ''व्यापक आर्थिक स्थायित्व को प्रश्रय देना.'' यह आसान काम नहीं था. अलबत्ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन से वित्त मंत्री ने पूंजीगत खर्च में भारी इजाफे का ऐलान किया और उसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया, जो 2022-23 के मुकाबले 33 फीसद की बढ़ोतरी थी. रेलवे और सड़क तथा राजमार्ग के लिए भी भारी प्रावधान किया गया, जो क्रमश: 48 फीसद और 24.4 फीसद की बढ़ोतरी थी. पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए घर की मद में भी 66 फीसद बढ़ोतरी का प्रावधान है. इसके अलावा पर्यटन और सूक्ष्म, लघु, और मझोले उद्योग (एमएसएमई) जैसे प्रमुख रोजगार संभावना वाले क्षेत्रों के लिए भी कई प्रोत्साहन का प्रावधान है, जिनमें बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की गुंजाइश है.

ऐसा बजट पेश करने के लिए मोदी सरकार की काफी वाहवाही हुई, जिसमें पूंजीगत खर्चों में इजाफा और कर काटौती के जरिए वृद्धि को रफ्तार देने और साथ ही राजकोषीय प्रबंधन को दुरुस्त रखने का प्रावधान है. आदित्य बिड़ला समूह के कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा, ''वित्त मंत्री ने ठोस वित्तीय प्रबंधन को ध्यान में रखकर वृद्धि को बढ़ावा देने का अनोखा कार्य किया है. वह भी ऐसे समय में जब ज्यादातर विकसित अर्थव्यवस्थाएं मंदी के हालात से जूझ रही हैं.'' हालांकि सबके के लिए कुछ न कुछ वाले सीतारमन के खुशनुमा बजट की आखिरी परीक्षा इसी से होगी कि इसके प्रावधान बेरोजगारी की स्थिति को किस कदर सहज कर पाते हैं, जो खासकर महामारी के बाद युवाओं में नाजुक स्थिति में पहुंच गई है. केंद्रीय श्रम मंत्रालय के सावधिक श्रम बल सर्वे (पीएलएफएस) की ताजा सितंबर 2022 की रिपोर्ट में कुल बेरोजगारी दर को 7.2 फीसद आंका गया है, जो महामारी के चरम पर 9.8 फीसद से कुछ कम है. सरकार भले बेरोजगारी दर में कमी श्रेय ले सकती है, मगर असली मुद्दा यह है कि यह दर 20-29 वर्ष आयु वर्ग में सर्वाधिक है, जिसके दायरे में देश का ज्यादातर कार्यबल आता है.

"कैपेक्स मद में केंद्र के 10 लाख करोड़ रु. और राज्यों को 3.7 लाख करोड़ रु. अनुदान जीडीपी का 4.5% बैठेगा. इससे खूब रोजगार पैदा होगा."

—विनायक चटर्जी
चेयरमैन, फीडबैक इन्फ्रा

असली दुखती रग

दिसंबर में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआइई) के आंकड़ों के मुताबिक, 20-24 आयु वर्ग के लोगों में बेरोजगारी दर 48 फीसद (2017-18 में 20 फीसद की तुलना में दोगुनी से अधिक, जबकि महामारी से ठीक पहले यह दर 30 फीसद थी) और 25-29 वर्ष आयु वर्ग में 14 फीसद रही. इसकी तुलना में अमेरिका में दिसंबर 2022 में 20-24 वर्ष आयु वर्ग में बेरोजगारी दर 7.3 फीसद और कुल दर 3.5 फीसद थी. चीन में दिसंबर में 16-24 वर्ष आयु वर्ग में 16.7 फीसद यानी भारत से 2.8 फीसद अंक कम थी. हालांकि भारत में फरेबी रोजगार से समस्या और गंभीर हो जाती है, क्योंकि रोजगार की तलाश में अनेक युवा बेहद कम तनख्वाह वाली अल्पकालिक नौकरियां कर लेते हैं, जब तक उन्हें अपने योग्य नौकरियां नहीं मिलती हैं.

लखनऊ के इंदिरा नगर में रहने वाले 24 वर्षीय कुलदीप नारायण त्रिपाठी जानते हैं कि इंतजार लंबा रहने वाला है. बजट के दिन वे भोपाल हाउस पार्क की बेंच पर अपने मोबाइल एसेसरी सजाने में लगे थे. उनके संभावित ग्राहक पार्क से ही सटे शर्मा टी हाउस में चाय पीने आते हैं. वे मोबाइल कवर, हेडफोन और चार्जर बेचकर रोजाना 400-500 रु. कमा लेते हैं. हालांकि, त्रिपाठी ने 2019 में लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज से बी.कॉम की अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इस तरह के किसी काम की तो उम्मीद नहीं की थी. लेकिन कोविड-19 महामारी के दौरान जब उनके पिता को फोटो स्टूडियो बंद करना पड़ा तो परिवार की पूरी जिम्मेदारी कुलदीप पर आ पड़ी. अपना छोटा-मोटा व्यवसाय चलाने और परीक्षाओं की तैयारी के बीच संतुलन साधते हुए त्रिपाठी ने कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा दी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी. हताश होने के बावजूद, वे फिलहाल राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन चयन प्रक्रिया जल्द शुरू होने पर संदेह बना हुआ है.

त्रिपाठी ने वित्त मंत्री के भाषण को कुछ मिलेजुले भाव से सुना. उनके लिए खुशखबरी यह थी कि मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग के कच्चे माल पर उत्पाद शुल्क में कटौती से फोन की बिक्री में इजाफा हो सकता है और उनके धंधे को फायदा हो सकता है. लेकिन उन्हें लगता

बजट के रास्ते से बढ़ावा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वृद्धि को रफ्तार देने और इस तरह रोजगार के साथ नौकरी चाहने वालों में हुनर बढ़ाने के लिए एक के बाद एक कई उपायों का ऐलान किया

बुनियादी ढांचा

- प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए धनराशि 66 फीसद बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए की गई
- पूंजीगत निवेश खर्च में लगातार तीसरे साल भारी इजाफा करते हुए 33 फीसद बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए या जीडीपी का 3.3 फीसद कर दिया. यह 2019-20 के खर्च से यही कोई तीन गुना है
- राज्यों को सहायता अनुदान के जरिए पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण का प्रावधान. बजट में केंद्र के प्रभावी पूंजीगत खर्च के लिए 13.7 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं, जो जीडीपी के 4.5 फीसद हैं
- कुल 1.3 लाख करोड़ रुपए की बढ़ी हुई धनराशि के साथ राज्य सरकारों को 15-साल का ब्याज मुक्त कर्ज एक और साल तक जारी रहेगा ताकि बुनियादी ढांचे में निवेश को अच्छी तरह से गति मिल सके
- बुनियादी ढांचे में ज्यादा निजी निवेश लाने की गरज से सभी हितधारकों की सहायता के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटरिएट की स्थापना का ऐलान
- रेलवे के लिए अब तक की सबसे ज्यादा 2.4 लाख करोड़ रुपए की धनराशि, जो 2013-14 के परिव्यय से करीब नौ गुना ज्यादा है
- बंदरगाहों, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों में अंतिम और पहले मील की कनेक्टिविटी के लिए सौ बेहद अहम ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की पहचान की गई. उन्हें प्राथमिकता से लेते हुए 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिनमें 15,000 करोड़ रुपए निजी स्रोतों से आएंगे
- श्रेणी 2 और 3 के शहरों में शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण के वास्ते सार्वजनिक एजेंसियों के लिए शहरी अवसंरचना विकास निधि (अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड/यूआइडीएफ) बनाई जाएगी
- पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चैलेंज मोड के जरिए 50 गंतव्य चुने जाएंगे
- युवा ग्रामीण उद्यमियों के कृषि स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड बनाया जाएगा

एमएसएमई

- सरकार और सरकारी उद्यम कोविड-19 की अवधि के दौरान अनुबंध के निष्पादन में एमएसएमई की नाकामी के मामलों में बोली या परफॉर्मेंस सिक्योरिटी से जुड़ी जब्त की गई धनराशि का 95 फीसद हिस्सा लौटाएंगे
- कोष में 9,000 करोड़ रुपए डालकर चुस्त-दुरुस्त कर्ज गारंटी योजना 1 अप्रैल, 2023 से शुरू होगी. इससे वे 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त जमानत मुक्त और गारंटीशुदा कर्ज ले पाएंगी. कर्ज की लागत करीब 1 फीसद घटाई जाएगी

कौशल विकास

- अगले तीन साल में लाखों युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी. ऑन-जॉब ट्रेनिंग, इंडस्ट्री पार्टनरशिप और उद्योग की जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों पर जोर दिया जाएगा. योजना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ), रोबोटिक्स, मेकेट्रॉनिक्स, आइओटी, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल्स जैसे नए जमाने के पाठ्यक्रम भी शामिल होंगे. अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को हुनरमंद बनाने की खातिर विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया अंतरराष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे
- मांग-आधारित औपचारिक हुनर विकसित करने और आंत्रेप्रेन्योरशिप योजनाओं तक पहुंच आसान बनाने के लिए एकीकृत स्किल इंडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा, जिससे एसएमएसई सहित नियोक्ता जुड़े होंगे
- 2014 के बाद स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों से जुड़ी को-लोकेशंस पर 157 नए नर्सिंग कॉलेज शुरू किए जाएंगे
- अनुसंधान में साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक और निजी मेडिकल कॉलेजों के संकायों और निजी क्षेत्र की रिसर्च ऐंड डेवलपमेंट टीमों के अनुसंधानों के लिए आइसीएमआर की चुनिंदा प्रयोगशालाओं की सुविधाएं मुहैया की जाएंगी
- मौजूदा संस्थाओं में चिकित्सा उपकरणों के प्रति समर्पित मल्टी डिसिप्लिनरी पाठ्यक्रमों को सहायता दी जाएगी ताकि भविष्य की मेडिकल टेक्नोलॉजी, महंगी मैन्यूफैक्चरिंग और रिसर्च के लिए हुनरमंद मानवबल की उपलब्धता आश्वस्त की जा सके
- नवाचारी शिक्षाशास्त्र, पाठ्यक्रम में आदान-प्रदान, निरंतर पेशेवर विकास, डिपस्टिक सर्वे और आइसीटी लागू करने के जरिए शिक्षकों के प्रशिक्षण का कायाकल्प किया जाएगा
- सरकारी कर्मचारियों का कौशल बढ़ाने और जन-केंद्रित नजरिए और तौर-तरीकों को सुगम बनाने के लिए एकीकृत ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म आइजीओटी कर्मयोगी लॉन्च किया जाएगा
- 5जी सेवाओं का इस्तेमाल करते हुए ऐप विकसित करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में सौ प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी

"दुआ मेरी याद रखना"

दीप सिंह

अपने वक्त का इंतजार

अंग्रेजी में बीए
मौजूदा स्थिति: ट्यूशन पढ़ा रहीं

दीक्षा कुमारी, 23 वर्ष

पटना, बिहार

बिहार के सहरसा जिले के बनगांव की रहने वाली दीक्षा कुमारी ने 2021 में पटना स्थित ए.एन. कॉलेज से 66 फीसदी अंकों के साथ अंग्रेजी में बीए किया था. अब पिछले तीन साल से वे कर्मचारी चयन आयोग के जरिए सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर रही हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग भी ले रही हैं. हालांकि, नौकरी अभी तक दूर की कौड़ी ही दिखती है. दीक्षा के मुताबिक, ताजा बजट से यह साफ नहीं हो रहा कि नौकरियों के मोर्चे पर कुछ ठोस करने के लिए सरकार के पास कोई योजना है. और अगर होती तो कम-से-कम चुनाव को ही ध्यान में रखते हुए इसे पेश किया गया होता. एक निम्न मध्यमवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाली दीक्षा की कोशिश है कि उसे जल्द से जल्द नौकरी मिल जाए ताकि वह एक निजी कंपनी में काम करने वाले अपने पिता का सहारा बन सके जो अकेले ही कमाकर परिवार का पेट पाल रहे हैं. सिविल सेवा परीक्षाओं में शामिल होना दीक्षा का सपना है लेकिन वे कहती हैं कि नौकरी तलाशने के इरादे के साथ पटना में दो साल से ज्यादा समय तक टिके रहना भी आसान नहीं क्योंकि यहां खर्च बहुत ज्यादा है. फिलहाल, वे खाली समय में कुछ छात्रों को ट्यूशन पढ़ाकर थोड़ा-बहुत हाथ का खर्च निकाल लेती हैं. —पुष्यमित्र

"ताजा बजट से यह साफ नहीं हो रहा कि नौकरियों के मोर्चे पर कुछ ठोस करने की सरकार के पास कोई योजना है."

है कि वित्त मंत्री को रोजगार के मोर्चे पर ज्यादा कुछ करना चाहिए था. वे कहते हैं, ''मेरे जैसे गरीब परिवार के युवाओं में सिर्फ सरकारी नौकरियों का ही आकर्षण है. हमें उम्मीद है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रावधानों में बढ़ोतरी से हमारी संभावनाएं सुधरेंगी.''

त्रिपाठी जैसे युवाओं की समस्या सीएमआइई के एमडी तथा सीईओ महेश व्यास एक संदर्भ में रखकर देखते हैं, ''सबसे ज्यादा मुश्किल तो कॉलेज से पढ़ाई पूरी करके निकले और कोई अनुभव न रखने वाले युवा की होती है. वह कम वेतन पर काम करने को तैयार नहीं है क्योंकि इससे उसका करियर हमेशा के लिए तबाह हो सकता है. इसलिए पढ़े-लिखे लोग अच्छी नौकरी की तलाश में कड़ी मेहनत करते हैं. उनमें बड़ी संख्या 30 साल की उम्र तक सरकारी नौकरी पाने के लिए हाथ-पैर मारते रहते हैं और अंततः हार मानकर कम वेतन वाली नौकरी के लिए तैयार हो जाते हैं.''

दूसरे आंकड़े भी हालात के संगीन होने का ही संकेत देते हैं. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की तरफ से 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल आंकड़ों के मुताबिक, उस साल 4.63 करोड़ सदस्यों ने ईपीएफ में अंशदान किया. यह आंकड़ा दर्शाता है कि महामारी से पहले वर्ष 2019-20 में अंशदान करने वाले 4.89 करोड़ सदस्यों की तुलना में संगठित क्षेत्र की नौकरियों में गिरावट आई है. व्यास कहते हैं, ''जाहिर है, ईपीएफओ अंशदान के जरिये मापी जाने वाली संगठित क्षेत्र की नौकरियां कम से कम 2021-22 तक तो महामारी से पहले के स्तर पर नहीं पहुंच पाई थीं. इसमें 5.3 फीसद की गिरावट दर्ज की गई है.'' अंतरराष्ट्रीय टेक कंपनियों और कुछ भारतीय स्टार्ट अप में छंटनी से भी हालात गंभीर ही हुए हैं. इन सबने ऐसे वक्त में लोगों को बेसहारा कर दिया, जब महामारी के दो वर्षों की मार से लोग और उद्यम उबर भी नहीं पाए थे. कंपनियां छंटनी कर रही हैं या भर्ती पर रोक लगा रही हैं (देखें, *नौबत सिस्टम ही क्रैश होने की*). गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक ने दुनिया भर में 12,000 लोगों को निकाल दिया, माइक्रोसॉफ्ट

की इस साल 10,000 नौकरियां कम करने की योजना है, और मेटा ने इस साल 11,000 लोगों से ज्यादा को निकाला. ट्विटर ने पिछले साल नए मालिक एलॉन मस्क के आने के हफ्ते भर में 7,500 लोगों को चलता किया. रिपोर्टों के मुताबिक, सोशल मीडिया सर्विस ने भारतीय स्टाफ में से 90 फीसद की छंटनी कर दी, यानी 200 में से महज दर्जन भर रह गए हैं.

असल में भारत में रोजगार और नौकरियों के मुद्दे का सही पैमाना जानने के लिए देश में रोजगार के ढांचे पर गौर करने की दरकार है. देश में100 करोड़ कार्यबल होने का अनुमान है, इनमें से 41 करोड़ या 41 प्रतिशत के पास कोई न कोई रोजगार है. इनमें से 46 फीसद कृषि क्षेत्र में, 21 फीसद उद्योगों में और 32 प्रतिशत सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं. कृषि देश में आजीविका का मुख्य साधन बना हुआ है, यही बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि जीडीपी में योगदान सिर्फ 20 फीसद है. जबकि उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान क्रमशः 26 प्रतिशत और 54 प्रतिशत है. लिहाजा कृषि से उद्योगों और सेवा क्षेत्र की ओर रोजगार सृजन का बदलाव होना चाहिए था लेकिन दशकों से यह कई सरकारों के कार्यकाल में उस अपेक्षित तेजी से नहीं हुआ. देश के कार्यबल में हर साल 1.2 करोड़ का इजाफा हो जाता है. दिसंबर में देश में बेरोजगारों की कुल संख्या 3.3 करोड़ थी.

भारत की स्थिति में अलग बात यह है

दूसरी-तीसरी श्रेणी के शहरों के बुनियादी ढांचे पर जोर और पीएम आवास योजना के जरिए हाउसिंग को 79,000 करोड़ रु. दिए जाने से बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा हो सकता है.”

—निरंजन हीरानंदानी
सह-संस्थापक, एमडी, हीरानंदानी ग्रुप

मनीष अग्निहोत्री

“हमें उम्मीद है कि बजट में तमाम सरकारी योजनाओं के लिए जो धन आवंटित किया गया है, उससे हमारे लिए संभावनाएं बढ़ेंगी.”

नौकरी का इंतजार

बी.कॉम ग्रेजुएट
मौजूदा स्थितिः अनौपचारिक व्यवसाय

कुलदीप त्रिपाठी, 24 वर्ष

लखनऊ, उत्तर प्रदेश

लखनऊ के क्रिश्चियन कॉलेज से कॉमर्स ग्रेजुएट कुलदीप त्रिपाठी शहर के भोपाल हाउस पार्क के बाहर एक बेंच पर मोबाइल एसेसरीज बेचते हैं, इस उम्मीद में कि नजदीकी शर्मा टी हाउस पर आने वालों में से ग्राहक मिल पाएंगे. वे कर्मचारी चयन की परीक्षा में बैठे पर कामयाबी नहीं मिली. अब वे राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं. इस बजट में कई सारे क्षेत्रों पर सरकार के ज्यादा जोर देने से उपयुक्त रोजगार पाने की उनकी उम्मीदें बढ़ी हैं.

—आशीष मिश्र

कि निजी क्षेत्र में बढ़ोतरी के बावजूद सरकारी नौकरियों पर ही नौजवानों की नजर रहती है, क्योंकि उससे सुरक्षा, निश्चित वेतन और सम्मान का भाव जुड़ा हुआ है. देश के 100 करोड़ कार्यबल में केंद्र और राज्यों में 2 करोड़ या 2 फीसद लोग ही सरकारी नौकरियों में हैं. यह संख्या भी चीन से कम है, जहां 3.9 करोड़ या 4.6 फीसद कार्यबल सरकारी नौकरियों में है. अमेरिका में भी 1.09 करोड़ या 6.9 फीसद कार्यबल फेडरल या राज्य संस्थाओं में कार्यरत है. अलबत्ता, मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, पिछले साल सरकारी नौकरियों में अनुमानित 60 लाख पद खाली थे. पिछले अक्तूबर में प्रधानमंत्री मोदी ने 'रोजगार मेला' की शुरुआत की, जिसका मकसद ज्यादातर सरकारी पदों पर भर्ती करके दस लाख लोगों को नौकरी मुहैया कराना था. हालांकि समस्या की गंभीरता के मद्देनजर पच्चीकारी के समाधान काफी नहीं हो सकते हैं. यहीं बजट 2023 की अहमियत है.

बजट-2023 का वादा

हमेशा 'आत्मनिर्भरता' की पुरजोर वकालत करने वाली मोदी सरकार ने बजट 2023 में बेरोजगारों के लिए निर्धारित राशि में कटौती करके, इसके बजाय निवेश पर पूरा जोर दिया है ताकि विकास के साथ रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकें. ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का बजट 2022-23 में 73,000 करोड़ रुपए की तुलना में काफी ज्यादा घटाकर 2023 में 60,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है. इसके बजाय पूंजीगत व्यय में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है जिसे 2022-23 में 7.5 लाख करोड़ रुपए की तुलना में एक-तिहाई बढ़ाकर वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 10 लाख करोड़ रुपए यानी जीडीपी का 3.3 प्रतिशत और 2019-20 में परिव्यय का करीब तीन गुना कर दिया गया है. फीडबैक इंफ्रा के चेयरमैन विनायक चटर्जी कहते हैं, ''केंद्र की तरफ से 10 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय को राज्यों को दिए जाने वाले 3.7 लाख करोड़ रुपए के अनुदान के साथ जोड़ लिया जाए तो प्रभावी तौर पर पूंजीगत व्यय कुल मिलाकर 13.7 लाख करोड़ रु. का हो जाएगा जो जीडीपी का करीब 4.5 फीसदी होता है. यह कदम बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने वाला होगा.''

फिर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के लिए बजटीय आवंटन को 1.34 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.62 लाख करोड़ किया गया. इसके अलावा 100 महत्वपूर्ण परिवहन इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए 75,000 करोड़ रुपए का आवंटन शामिल है. इन परियोजनाओं के तहत बंदरगाह, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों के लिए एंड-टू-एंड कनेक्टिविटी सुविधा प्रदान की जानी है. 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और वाटर एयरोड्रोम के निर्माण के लिए भी धनराशि आवंटित की गई है. रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय आवंटित किया गया है, जो पिछले साल आवंटित 1.37 लाख करोड़ रुपए से 70 फीसद ज्यादा और अब तक का सर्वाधिक पूंजी परिव्यय है. यह राशि 500 नई वंदे भारत ट्रेनों और 1,275 से अधिक स्टेशनों के पुनर्विकास सहित विभिन्न परियोजनाओं पर खर्च की जानी है. परिवहन क्षेत्र के लिए इतनी बड़ी राशि के आवंटन से लाखों मजदूरों को रोजगार मिलने की संभावना है.

बजट 2023 में निर्माण क्षेत्र के वित्तीय आवंटन में भी भारी बढ़ोतरी की गई है, जो संबंधित उद्योग में 50 फीसदी के करीब रोजगार प्रदान करता है. शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंदों के लिए 1.2 करोड़ घरों के निर्माण के लक्ष्य के साथ चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाइ) के लिए बजटीय आवंटन 66 फीसदी बढ़ाकर 48,000 करोड़ रुपए से 79,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है. हीरानंदानी समूह के सह-संस्थापक और प्रबंध निदेशक निरंजन हीरानंदानी कहते हैं कि पीएमएवाइ के तहत आवास पर पूंजीगत व्यय के अलावा, बजट में टियर-2 और टियर-3 शहरों में शहरी बुनियादी ढांचे पर जोर दिए जाने से भी बड़े पैमाने पर रोजगार उत्पन्न होंगे. क्रिसिल के मुख्य अर्थशास्त्री डी.के. जोशी कहते हैं, ''बुनियादी ढांचा और निर्माण ऐसे क्षेत्र हैं, जो बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा कर सकते हैं. कृषि के बाद जो क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराता है, वह निर्माण क्षेत्र ही है.'' पर्यटन क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करने की संभावनाएं हैं. होटल और रेस्तरां जैसे संपर्क-आधारित उद्योगों की तरह, महामारी के कारण बड़े पैमाने पर प्रभावित पर्यटन क्षेत्र भी अब धीरे-धीरे पटरी पर लौटने लगा है. बजट में देशभर में 50 गंतव्य स्थलों का चयन कर वहां बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए निवेश बढ़ाने की घोषणा की गई है, जिसमें होटल और साइटों के निर्माण के जरिये घरेलू और विदेशी पर्यटन को बढ़ावा देना और

"नौकरियों पर सीधा फोकस नहीं है लेकिन (दूसरे क्षेत्रों में निवेश के असर से) कहीं ज्यादा रोजगार पैदा हो सकता है. स्किलिंग यानी हुनर पैदा करने पर फोकस अच्छी बात है पर यह ठीक से लागू तो हो."

— डी.के. जोशी
मुख्य अर्थशास्त्री, क्रिसिल

"सहकारिता को प्रोत्साहन से खेती की प्राथमिक सहकारी इकाइयों की जिंदगी आसान होगी, गांवों में आमदनी बढ़ेगी, काम मिलेगा और विस्थापन घटेगा."

— सतीश मराठे
सहकार भारती; आरबीआइ बोर्ड में निदेशक

"कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप और अत्याधुनिक तकनीक लाने वाली इकाइयों को प्रोत्साहन हौसला बढ़ाने वाला है. बजट नौकरियों के मोर्चे पर भारत की खास चुनौतियों का जवाब है."

— अश्वनी महाजन
राष्ट्रीय सह संयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

इंडिया टुडे

नौबत सिस्टम ही क्रैश होने की

कोविड-19 महामारी के दौरान अपना भरपूर विस्तार करने वाली ग्लोबल टेक इंडस्ट्री अब छंटनी की जबरदस्त लहरों की चपेट में. इससे नौकरियों का संकट और बढ़ गया

अजय सुकुमारन

मोहाली के बीटेक ग्रेजुएट पवन (बदला हुआ नाम) सात महीनों से एक अव्वल भारतीय आइटी कंपनी के फोन या ईमेल का इंतजार कर रहे हैं. 23 वर्षीय पवन को एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रोल के लिए चुना गया था, पर उसके बाद कोई खबर ही नहीं. उसने दूसरी एमएनसी का दरवाजा खटखटाया तो जवाब मिला कि वहां भर्तियां रोक दी गई हैं. मगर पवन को तो एजुकेशन लोन चुकाना था, सो अब वे बीपीओ में काम रहे हैं.

ऐसी मुसीबत झेलने वाले पवन अकेले नहीं हैं. उनके कई साथी इसी नाव पर सवार हैं. ग्लोबल टेक इंडस्ट्री या दुनिया भर के टेक्नोलॉजी उद्योग में कोहराम मचा है. विडंबना ही है कि भारत में 50 लाख की मजबूत वर्कफोर्स वाली टेक इंडस्ट्री अभी हाल तक बल्ले-बल्ले कर रही थी और कोविड-19 महामारी के चलते भारी विस्तार में जुटी थी. वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत की चार शीर्ष आइटी फर्म—टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), इंफोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और विप्रो—ने तकरीबन 2,40,000 नए कर्मचारी जोड़े. ऊंची तनख्वाहें दी जा रही थीं. एक-दूसरे में सेंध लगाकर प्रोफेशनल लाए जा रहे थे. कुछ ही महीने पहले 'मूनलाइटिंग' यानी कर्मचारियों के छिपकर दूसरों के लिए काम करने को लेकर चिंताएं जताई जा रही थीं.

फिर चीजें धड़धड़ाकर जमीन पर आ गिरीं. यह पिछले साल नवंबर में अमेरिका से शुरू हुआ. अमेजन, ट्विटर, मेटा और सेल्सफोर्स सरीखी बड़ी फर्में हजारों की छंटनी का ऐलान करने लगीं (देखें: *कंपा देने वाली 'शीतलहर'*). भारतीय प्रवासी समुदाय के लोगों की नौकरियां जाने को लेकर न्यूयॉर्क के आइटी के एक सीनियर बंदे ने कहा, ''उथल-पुथल तो है ही. एनाउंसमेंट (पगार) के साथ हर हफ्ते बुरी खबर भी आती है...उथल-पुथल इसलिए है क्योंकि वे अगले 60 दिनों में नौकरी नहीं खोज लेते तो उनके वीजा बेकार हो जाएंगे और उन्हें लौटना पड़ेगा.''

इधर भारत में यहीं बने-बढ़े स्टार्ट-अप इस दलदल में धंसने लगे. बताया जाता है कि इस साल के पहले दो हफ्तों में ही कम से कम 11 भारतीय स्टार्ट-अप ने यही कोई 1,400 कर्मचारियों को निकाल दिया. इनमें शेयरचैट, डुंजो और ओला सरीखे नाम थे. भारत में टेक्नोलॉजी क्षेत्र की भर्तियों में दबदबा रखने वाली बड़ी कंपनियों में भी चीजें अंधेरे से घिर गईं. भारत की चार शीर्ष आइटी कंपनियों ने पिछले साल की अक्तूबर-दिसंबर तिमाही में महज 1,940 नए कर्मचारी जोड़े, जबकि जुलाई-सितंबर की तिमाही में 28,836 जोड़े थे. विशेषज्ञों की भर्ती करने वाली बेंगलूरु स्थित फर्म एक्सफीनो के मुताबिक भारत में सक्रिय व्हाइट-कॉलर नौकरियों में आइटी सेक्टर का योगदान इस साल जनवरी में घटकर 40 फीसद के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया, जो मार्च 2022 में 80 फीसद से ज्यादा था. एक्सफीनो के सह-संस्थापक कमल कारंत कहते हैं, ''मैं इसे (भर्ती पर) रोक नहीं कहूंगा क्योंकि कंपनियां नौकरी छोड़ने वालों की जगह भरने के लिए तो भर्ती कर ही रही हैं... हां, विस्तार के लिए भर्तियां नहीं हो रही हैं.''

कंपनियां इस भेड़ियाधसान से निबटने के लिए अब धीरे-धारे अपनी रणनीति नए सिरे से तय कर रही हैं. टीसीएस के वित्तीय नतीजों के ऐलान के लिए की गई वीडियो कॉन्फ्रेंस में सीईओ राजेश गोपीनाथन ने कहा कि 2021 में राजस्व वृद्धि से पहले अच्छी-खासी भर्तियां करने के बाद फर्म को ''भर्ती के ज्यादा सामान्य किस्म के रुझान'' की तरफ लौट आना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस साल फोकस ''उस अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करने और अपने

कंपा देने वाली 'शीतलहर'

2022 में: 1,040 टेक कंपनियों ने दुनिया भर में 159,684 कर्मचारियों को निकाला

2023 में: (30 जनवरी तक): 229 टेक कंपनियों ने दुनिया में 68,502 कर्मचारियों की छंटनी की है

टेक कंपनियों में विश्वव्यापी छंटनी

अमेजन	18,000
गूगल	12,000
मेटा	11,000
माइक्रोसॉफ्ट	10,000
आइबीएम	3,900
एसएपी	3,000

(स्रोतः कंपनियों की घोषणाएं और मीडिया रिपोर्ट)

भारत में स्टार्ट-अप में हुई छंटनी

शेयरचैट	500
स्विगी	380
ओला	200
कैप्टन फ्रेश	120
स्किट.एआइ	115
कैशफ्री पेमेंट्स	100

(स्रोतः लेआफ्स.एफवाइआइ)

(स्रोतः Layoffs.fyi यह एक ऐसी वेबसाइट है जो कोविड-19 के दिनों से ही टेक कंपनियों में होने वाली छंटनी से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों को ट्रैक करती आ रही है)

हुआ में याद रखना

नए कर्मचारियों को ज्यादा उत्पादक बनाने'' पर है. हर कंपनी में अलहदा मंजर है. बेंगलूरू स्थित एक एमएनसी के मैनेजर कहते हैं, ''इस तिमाही हमारे यहां भर्तियों पर रोक और प्रोमोशन पर पाबंदी है.'' हाल में करीब 500 टेक क्लाइंट के एक सर्वे में रैंडस्टेड इंडिया ने बताया कि उनमें से 4-5 फीसद ने भर्तियों पर रोक लगा रखी थी और दो फीसद ने रणनीतिक छंटनी की योजना अपनाई थी. बाकी ने भर्तियों में कमी कर दी और वेट ऐंड वाच की मुद्रा में हैं.

हालांकि कुल मिलाकर कुछ जानकारों की राय है कि भारत इस वैश्विक रुझान को शायद उलट पाए क्योंकि जो डिजिटल बदलाव आ रहा है, उसमें टेक्नोलॉजी की प्रतिभाओं की मांग बढ़ रही है. भर्तियां करने वाले कारंत सरीखे लोग मानते हैं कि भारत में इस साल तमाम स्तरों पर करीब 6,00,000

2023 का केंद्रीय बजट भारत की टेक इंडस्ट्री के लिए उम्मीद की किरण बन सकता है क्योंकि इसमें स्टार्ट-अप और आंत्रेप्रेन्योरशिप पर ज्यादा जोर दिया गया है

नौकरियां बढ़ सकती हैं. इसके पीछे तर्क यह है कि बड़ी आइटी सेवा कंपनियां दो तिमाही से ज्यादा भर्तियों के बाजार से दूर रहना गवारा नहीं कर सकतीं क्योंकि इससे उनकी टैलेंट सप्लाई चेन और कामकाज पर असर पड़ेगा.

हाल ही आए केंद्रीय बजट से भी उम्मीद की किरण दिखाई दी है, जिसमें ध्यान स्टार्ट-अप और उद्यमिता दोनों क्षेत्रों पर है. स्टार्ट-अप को दिए जा रहे कर लाभ साल भर (अप्रैल 2024 तक) के लिए बढ़ा दिए गए और वे अपने घाटे मौजूदा सात साल के बजाय कंपनी के गठन के बाद 10 साल तक आगे ले जा सकते हैं. वित्त मंत्री ने कृषि के ओपन-सोर्स, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रामीण इलाकों में युवा उद्यमियों के कृषि स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए एक्सेलरेटर फंड या त्वरण निधि बनाने का भी ऐलान किया. इसके अलावा नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी भी आने वाली है, जिसका मकसद गुप्त या गुमनाम डेटा स्टार्ट-अप और एकेडमिक दुनिया को सुलभ करवाना है. साथ ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) के लिए तीन उत्कृष्टता केंद्र भी शीर्ष शिक्षा संस्थानों में स्थापित किए जाएंगे.

आइआइएम बंगलौर के बिजनेस इंक्यूबेटर एनएसआरसीईएल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आनंद श्री गणेश कहते हैं, ''वित्त मंत्री की घोषणाएं और खासकर प्राथमिकता क्षेत्रों व हाइ-इंपैक्ट क्लस्टरों को बढ़ावा देने वाली घोषणाएं उत्साहवर्धक हैं. रोबोटिक्स और एआइ सरीखी उभरती टक्नोलॉजी के उत्कृष्टता केंद्र टेक्नोलॉजी में नवाचारों पर आधारित स्टार्ट-अप को और बढ़ावा देंगे.'' गणेश अलबत्ता यह भी कहते हैं कि बजट ने ''कमजोर पड़ते स्टार्ट-अप फंडिंग इकोसिस्टम खासकर एसेट-लाइट और शुरुआती अवस्था के नवाचार के लिए डेब्ट फंडिंग'' का मौका गंवा दिया.

बहरहाल भारत की डिजिटल ग्रोथ ही अंततः उसकी विलक्षण खूबी बन सकती है क्योंकि यह टेक्नोलॉजी के हुनर की मांग बढ़ा रही है. कौशल प्रशिक्षण के मोर्चे पर वित्त मंत्री ने नियोक्ताओं से जुड़े एकीकृत स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात कही. इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 का ऐलान किया, जिसमें कोडिंग, एआइ, रोबोटिक्स, मेकेट्रोनिक्स, आइओटी, 3डी प्रिंटिंग और ड्रोन के पाठ्यक्रम शामिल होंगे. गिरि के मुताबिक 2023 में डेटा एनैलिटिक्स, डेटा विजुएलाइजेशन, डेटा साइंस, फुल स्टैक डेवलपमेंट, और क्लाउड तथा डेवओप्स सरीखे क्षेत्रों में शायद मांग में बढ़ोतरी देखी जा सके, जो मौजूं हुनर से लैस प्रतिभाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सकती है. गिरि कहते हैं, ''हमने बदले हुए कारोबारी लक्ष्यों के लिए तमाम स्तरों पर छंटनी और व्यापक भर्तियां देखीं. फिर भी भारत सरीखे युवा और घनी आबादी वाले देश में टेक्नोलॉजी के हुनर की बढ़ती मांग के साथ नौकरियों का बाजार बेहद प्रतिस्पर्धी होने जा रहा है.''

जो भी हो, भारत की टेक इंडस्ट्री को एहतियात और सतर्कता में जरा भी कमी नहीं आने देना चाहिए क्योंकि तूफानी बादल तो उमड़-घुमड़ ही रहे हैं.■

सेवा क्षेत्र में नौकरियों में इजाफा करना शामिल है.

बजट 2023 में ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने पर भी खास जोर रहा है, खासकर कृषि और सहकारी क्षेत्रों में. पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्रों पर फोकस के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है. मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए एक नई सब-स्कीम पीएम मत्स्य संपदा योजना घोषित की गई है, जिसमें 6,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ लागत घटाने और सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए बाजार का विस्तार करने करने जैसी सुविधाएं मुहैया कराने का प्रस्ताव है. किसानों को ध्यान में रखकर बजट में बागवानी विकास को प्रोत्साहन और फसलों का उचित मूल्य आश्वस्त करने के खातिर भंडारण केंद्र स्थापित करने के लिए धन आवंटित किया गया है. अभी दायरे में न आने वाली पंचायतों और गांवों में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, प्राथमिक मत्स्य समितियों और डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना के लिए भी धन निर्धारित किया गया है. ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को प्रोत्साहन पर खास जोर है ताकि बड़ी संख्या में महिलाएं फिर कार्यबल का हिस्सा बन सकें. सहकार भारती के संस्थापक और भारतीय रिजर्व बैंक बोर्ड के निदेशक सतीश मराठे का कहना है कि सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिए जाने से कई परंपरागत मुद्दों को सुलझाकर प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का संचालन आसान हो सकेगा. व्यावहारिक तौर पर देश के सभी गांवों और 75 फीसदी परिवारों को कवर करने वाली 65,000 सहकारी समितियों का भरा-पूरा नेटवर्क है. उन्होंने कहा, ''यह न केवल ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने में मददगार है, बल्कि रोजगार के अवसर बढ़ाकर पलायन के कारण शहरों और कस्बों पर बढ़ने वाले दबाव को भी घटाता है.'' स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह-संयोजक अश्वनी महाजन का कहना है, ''अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ताओं के साथ कृषि क्षेत्र में स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन खासा उत्साहजनक है.''

असंगठित क्षेत्र के रोजगार में 50 फीसद की हिस्सेदारी रखने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के लिए बजट 2023 में कई प्रोत्साहन दिए गए हैं. कोविड अवधि के दौरान अपने सौदे पूरा न कर पाने वाले एमएसएमई के मामलों में सरकार और सरकारी उपक्रम जब्त की गई बोली या प्रदर्शन सुरक्षा से जुड़ी 95 फीसदी राशि लौटाएंगे. वहीं, कॉर्पस में 9,000 करोड़ रुपए डाले जाने के साथ 1 अप्रैल 2023 से संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना भी प्रभावी हो जाएगी. इससे 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त कोलैटरल-फ्री गारंटीशुदा ऋण मुहैया कराया जा सकेगा. इसके अलावा, ऋण लागत भी लगभग 1 फीसद घट जाएगी. फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज

"दुआएं याद रखना"

(एफआइएमएसएमई) के महासचिव अनिल भारद्वाज कहते हैं, ''एमएसएमई क्षेत्र अभी बेहद तनाव के दौर से गुजर रहा है, खासकर संपर्क-आधारित उद्योगों के लिहाज से.'' एफआइएमएसएमई ने क्रेडिट गारंटी फंड में 9,000 करोड़ रु. डाले जाने और एमएसएमई को खरीदारों की तरफ से समय पर भुगतान आश्वस्त करने के उपायों का स्वागत किया है. एफआइएमएसएमई के बयान में कहा गया, ''बजट में बड़ी संख्या में सरकारी आपूर्तिकर्ता एमएसएमई को राहत देने का प्रस्ताव है, जिन पर ऐसे समय में जुर्माना लगाया गया या बैंक गारंटी जब्त की गई जब दुनिया कोविड से बुरी तरह पस्त थी. अब, जब्त राशि में 95 फीसद लौटाई जाएगी.''

युवाओं को उद्योगों के लिहाज से कुशल बनाने के उद्देश्य के साथ बजट 2023 में कौशल विकास पर नए सिरे से फोकस किया गया है. अगले तीन साल में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू होगी. एकीकृत स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के लॉन्च के साथ डिजिटल स्तर पर कौशल विकास के उपयुक्त माहौल तैयार किया जाएगा. इसमें कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मैकेट्रोनिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल्स जैसे कोर्स होंगे. युवा अंतरराष्ट्रीय स्तर के अवसरों के अनुकूल बन सकें, इसके लिए बजट में विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोलने का प्रस्ताव है. जोशी कहते हैं, ''कौशल बढ़ाने के उपाय महत्वपूर्ण हैं. घोषित योजनाएं स्किलिंग, अपस्किलिंग और रिस्किलिंग के बिना फलदायी नहीं हो सकतीं. जब सीधे नौकरियों पर फोकस नहीं किया जा रहा है तो इन उपायों को ठीक से लागू करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए.''

अमल सबसे अहम

जोशी की बात एकदम सही है. कार्यान्वयन सबसे अहम है. कई विशेषज्ञों का मानना है कि पूंजीगत व्यय में वृद्धि ही काफी नहीं है, जरूरी यह भी है कि यह लागत घटाने, निवेश बढ़ाने और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने में कारगर साबित हो. हर सरकारी परियोजना में 100 से 150 कंपनियां जुड़ी होंगी, जिनमें ज्यादातर निजी क्षेत्र की है, और उन्हें मिलने वाले ऑर्डर के मुताबिक श्रम जरूरतों का आकलन करने की जरूरत पड़ेगी. बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदद सबनवीस कहते हैं, ''बड़े पैमाने पर पूंजीगत व्यय में अधिक रोजगार सृजन की क्षमता है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इस्पात या सीमेंट जैसे क्षेत्रों में कंपनियों को अधिक श्रमिकों की जरूरत है.'' ऐसे समय में जबकि भू-राजनीतिक परिदृश्य और वैश्विक मंदी को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, कंपनियां पहले से ही सतर्क रुख अपनाए हुए हैं. ज्यादातर कंपनियों में श्रम क्षमता का उपयोग 70 से 72 फीसदी रहा है, ऐसे में

"13.7 लाख करोड़ रु. का दमदार कैपेक्स अर्थव्यवस्था पर चौतरफा असर डालेगा. इससे रोजगार पैदा होगा और निजी क्षेत्र में निवेश आएगा."

—संजीव बजाज
सीएमडी, बजाज फिनसर्व; और अध्यक्ष, सीआइआइ

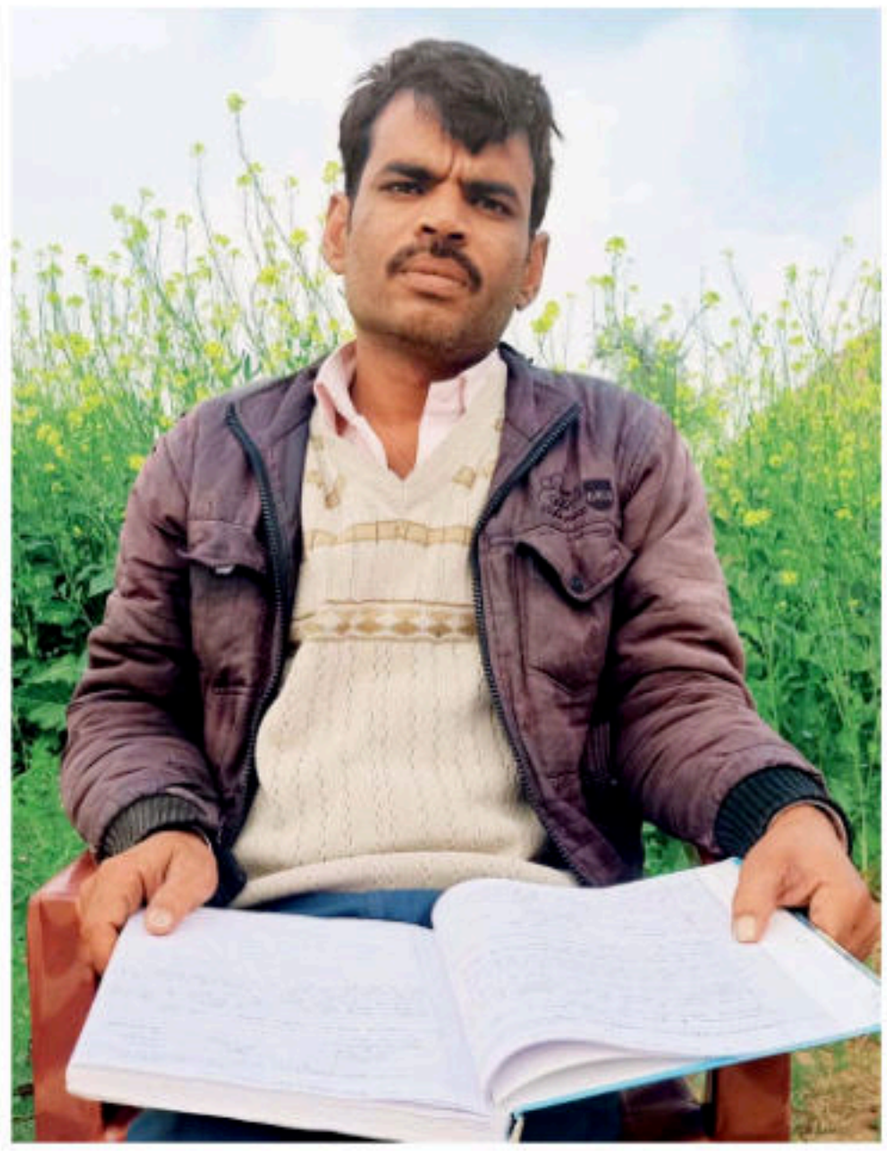

"बजट में मुझ जैसे करोड़ों बेरोजगारों के लिए सीधे नौकरी की कोई व्यवस्था होनी चाहिए थी?"

नौकरी की उम्मीद कायम

एम.एस.सी (गणित), बीएड
मौजूदा स्थिति: बेरोजगार

राजेश कुमार, 34 वर्ष

झुंझुनूं, राजस्थान

राजस्थान में झुंझुनूं जिले की चुहाना तहसील के पालोता गांव के रहने वाले राजेश कुमार गजराज ने गणित विषय में एमएससी और बीएड किया हुआ है. 2008 से ही वे केंद्र और राज्य की सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करते आ रहे हैं लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है. तीन साल तक उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग भी की लेकिन गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले राजेश के लिए परिवार का पेट पालना ही मुश्किल है. ऐसे में वे कोचिंग का पैसा कहां से चुकाएं? राजेश को द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, रीट, कांस्टेबल और लाइब्रेरियन भर्ती जैसी कुछ परीक्षाओं में पास होने की उम्मीद भी थी लेकिन नकल और दूसरी वजहों से इन परीक्षाओं के पेपर रद्द हो गए.
केंद्रीय बजट से उन्हें भरोसा था कि शायद इस साल उनकी सरकारी नौकरी की राह खुल जाएगी पर बजट से ज्यादा उम्मीद नहीं जगी है. राजेश कहते हैं, ''बजट में मुझ जैसे करोड़ों बेरोजगारों के लिए जब नौकरी की कोई व्यवस्था नहीं है तो अरबों-खरबों रुपए का यह बजट किस काम का है?''

—आनंद चौधरी

"दुआ में याद रखना"

ये रहीं कुछ दुखती रगें

कोविड-19 की महामारी ने रोजगार का संकट इतना बढ़ा दिया कि कुछ क्षेत्र बंद होने की कगार पर पहुंच गए और बड़ी तादाद में नौकरियां चली गईं. बजट इन मुद्दों को कैसे सुलझाता है?

ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी

कोविड-19 की सबसे ज्यादा मार ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र पर पड़ी. पिछले साल मार्च में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी. किशन रेड्डी ने बताया कि पर्यटन क्षेत्र से जुड़े 2.15 करोड़ लोग महामारी के चलते काम से हाथ धो बैठे.

बजट ने क्या किया: पर्यटन पर ध्यान केंद्रित हुए विशेष विकास के लिए 50 पर्यटन स्थलों की पहचान इस दिशा में एक बड़ा प्रोत्साहन है; लास्ट माइल कनेक्टिविटी में सहायता के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा.

टेक्सटाइल

अमेरिका और यूरोप में हाइ-स्ट्रीट सेल घटने का खमियाजा भारत से वैल्यू ऐडेड कपड़ों की बिक्री को और साथ ही नौकरियों को भी उठाना पड़ा. दिसंबर 2022 में भारत के निर्यात में सालाना आधार पर 12 फीसद की गिरावट आई. अमेरिका और यूरोप में मंदी के अंदेशों के चलते हालात बदतर हो सकते हैं.

बजट ने क्या किया: 2023-24 में एमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन योजना के लिए 900 करोड़ रुपए का आवंटन; मूल्य-संवर्धित परिधानों की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने में मदद के लिए एक्स्ट्रा-लॉन्ग स्टेपल कॉटन की पैदावार बढ़ाने पर जोर.

खुदरा

भारत का 950 अरब डॉलर का खुदरा क्षेत्र 4-6 करोड़ लोगों को सीधे-सीधे रोजगार देता था. मगर इसे महामारी का दंश झेलना पड़ा क्योंकि उपभोक्ताओं ने जरूरी चीजों के अलावा दूसरी चीजों की खरीदारी से हाथ खींच लिए. क्षेत्र के करीब 2 लाख रोजगारों पर असर पड़ा.

बजट ने क्या किया: अन्य वस्तुओं के अलावा टिकाऊ और इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर खर्च बढ़ाने के लिए मध्यम वर्ग के हाथ में धन दिया है.

एमएसएमई

भारत में करीब 6.3 करोड़ बहुत छोटे, छोटे और मध्यम उद्यम हैं, जिनमें 11.10 करोड़ लोग काम करते हैं. उद्योग के सूत्रों के मुताबिक इनमें से हजारों महामारी के दौरान ताले डालने को मजबूर हो गए. सबसे ज्यादा असर रिटेल, हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल तथा टूरिज्म सरीखे संपर्क आधारित क्षेत्रों पर पड़ा.

बजट ने क्या किया: कोष में 9,000 करोड़ रुपए डालकर चुस्त-दुरुस्त की गई कर्ज गारंटी योजना से कर्ज की लागत में कमी आएगी.

ऑटोमोटिव

महामारी के दौरान यह सबसे बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्रों में से एक था. अप्रैल 2020 में उत्पादन और बिक्री दोनों वाकई ठप पड़ गए. बाद में इस क्षेत्र को सेमीकंडक्टरों की कमी का असर झेलना पड़ा, जिससे उत्पादन और धीमा हो गया. कारों की बिक्री में हाल ही में जाकर जान आई, पर नौकरियां अब भी आर्थिक उतार-चढ़ावों की मोहताज हैं. महामारी के दौरान अकेले ऑटोमोटिव क्षेत्र में करीब 3.45 लाख लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा.

बजट ने क्या किया: वृद्धि को बढ़ावा देने और लोगों के हाथ में ज्यादा धन रखने के लिए पूंजीगत खर्च में बढ़ोतरी की; पुराने सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने की योजना से भी बिक्री में मदद मिलेगी.

रीयल एस्टेट और निर्माण

कुल 120 अरब डॉलर का रीयल एस्टेट और निर्माण क्षेत्र 5.2 करोड़ लोगों को काम देता था, जिसमें से 4.1 करोड़ अनौपचारिक कामगार हैं. कोविड-19 की महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन से देश भर में निर्माण गतिविधियां ठप पड़ गईं और लाखों कामगार बेरोजगार हो गए.

बजट ने क्या किया: प्रधानमंत्री आवास योजना में ज्यादा धनराशि; निर्माण गतिविधियां तेज करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्च किए जाएंगे.

दुआ रहेंगी याद रखना

विस्तार के प्रयास और अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर हिचक हो सकती है.

पुणे स्थित गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स ऐंड इकोनॉमिक्स के कुलपति अजीत रानाडे के मुताबिक, बजट बुनियादी ढांचे में खर्च पर केंद्रित है, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन होगा. वे कहते हैं, ''जहां तक प्रत्यक्ष रोजगार का सवाल है, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आवंटन में कटौती की गई है. यह नकारात्मक पहलू है, क्योंकि मनरेगा भारत में बेरोजगारी दूर करने के मामले में एक बड़ा उपाय है.'' इसके अलावा, पूंजीगत व्यय दीर्घावधिक परियोजनाओं पर किया जाता है, जबकि रोजगार सृजन के लिए अल्पावधि की योजनाओं में तेजी अहम होगा.

पश्चिम बंगाल के पूर्व वित्त मंत्री अमित मित्रा कहते हैं कि देश में 90 फीसदी नौकरियां असंगठित क्षेत्रों में हैं. उनके मुताबिक, ''ये जीडीपी में 40-50 फीसदी योगदान देते हैं. उनके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा या सामाजिक सुरक्षा जैसा कुछ नहीं है.'' कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने 1 फरवरी को नई दिल्ली में सवाल उठाया, ''इस बजट से किसे लाभ हुआ है? गरीबों को तो नहीं हुआ. बेसब्री से नौकरी तलाश रहे युवाओं को भी नहीं हुआ. और न ही उन्हें जिनकी नौकरियां चली गई हैं.''

रोजगार सृजन के लिए पूंजीगत व्यय के लिहाज से सरकार बस इतना ही कर सकती थी. निजी निवेश को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है. हालांकि, उद्योग पर्याप्त निवेश नहीं कर रहे, जिसमें नौकरियां प्रदान करने की क्षमता है. व्यास कहते हैं, ''यह समस्या 2011-12 से ही कायम है, रोजगार उत्पन्न करने के लिहाज से निवेश अनुपात अपर्याप्त रहा है.'' नए निवेश को दर्शाने वाला सकल स्थायी पूंजी निर्माण 2022 में सालाना आधार पर सिर्फ तीन प्रतिशत अधिक था. उद्योग रोजगार सृजक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लगभग 531,000 प्रतिष्ठानों में अनुमानित 3.18 करोड़ नौकरियां हैं. रियल एस्टेट और निर्माण क्षेत्र में 5.2 करोड़ लोग कार्यरत हैं, जिनमें 4.1 करोड़ अनौपचारिक श्रमिक हैं. खुदरा क्षेत्र चार से छह करोड़ प्रत्यक्ष रोजगार देता है. अनुमानित 6.3 करोड़ एमएसएमई हैं, जो 11 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं.

अर्थव्यवस्था आगे एक कठिन दौर की तरफ बढ़ रही जिसमें रोजगार के मोर्चे पर स्थिति और बिगड़ने की आशंका है. ऐसे में विकास की दिशा में बढ़ाने वाले ठोस प्रयास और रोजगार उत्पन्न करने वाले संभावना क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने से ही उन नौकरियों का सृजन हो सकता है जिनकी आज देश को सबसे ज्यादा जरूरत है. बजट 2023 इस दिशा में अच्छी शुरुआत करता है. ■

कुछ न कुछ सभी के लिए

अपने बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार के जिस आर्थिक एजेंडे को रेखांकित किया उसमें नागरिकों, खासकर युवाओं के लिए अवसर पैदा करना और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना, विकास और रोजगार सृजन को गति देना तथा अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों के खिलाफ मजबूती देना शामिल है. पूंजीगत व्यय को सबसे अधिक महत्व दिया गया है और इसमें सबसे अधिक आवंटन परिवहन क्षेत्र को मिला है. साथ ही मध्यम वर्ग को टैक्स में कुछ राहत दी गई है. बजट के मुख्य बिंदुओं, महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणाओं और नई कर व्यवस्था के संभावित असर पर एक नजर

रुपया

ऐसे आता है

उधारियां और अन्य उत्तरदायित्व	34%
जीएसटी और अन्य कर	17%
आयकर	15%
कॉर्पोरेशन टैक्स	15%
केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी	7%
गैर कर प्राप्तियां	6%
सीमा शुल्क	4%
गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	2%

इस तरह जाता है

20%	ब्याज का भुगतान
18%	करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा
17%	केंद्रीय सेक्टर की योजनाएं
9%	केंद्र प्रायोजित योजनाएं
9%	वित्त आयोग और अन्य
8%	प्रतिरक्षा
8%	अन्य खर्च
7%	सब्सिडी
4%	पेंशन

कुछ सालों का राजकोषीय घाटा

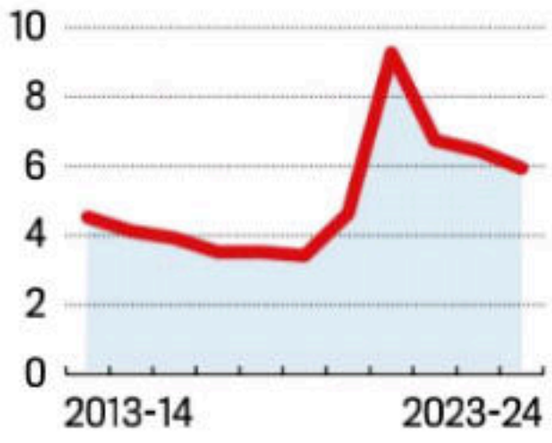

2.4 लाख करोड़ रु.
रेलवे के लिए आवंटित जो कि अब तक की सर्वाधिक रकम है

14.7 लाख करोड़ रु.
खर्च किए जाएंगे केंद्र सरकार की तरफ से प्रायोजित योजनाओं पर

ग्राफिक्सः तन्मय चक्रवर्ती

व्यय का हिसाब-किताब

परिवहन और ग्रामीण विकास की मद में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की गई जबकि शहरी विकास के लिए फंड में कमी आई

	2023-24	2022-23
प्रतिरक्षा	4,32,720	4,09,500
कृषि और संबद्ध गतिविधियां	84,214	83,521
पीएम किसान	60,000	68,000
ग्रामीण विकास	2,38,204	2,06,293
शिक्षा	1,12,899	1,04,278
स्वास्थ्य	88,956	86,606
समाज कल्याण	55,080	51,780
शहरी विकास	76,432	76,549
परिवहन	5,17,034	3,51,851
सब्सिडी	3,74,707	3,17,866
पेंशन	2,34,359	2,07,132
ब्याज का भुगतान	10,79,971	9,40,651

केंद्रीय योजनाओं के लिए रकम

प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन के लिए सर्वाधिक आवंटन हुआ

	2023-24	2022-23
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम*	60,000	73,000
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेवाइ)	7,200	6,457
जल जीवन मिशन (जेजेएम)/ राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन	70,000	60,000
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमवाइ)	79,590	48,000
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	19,000	19,000
शहरी नवीकरण मिशन: अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन	16,000	14,100
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान)	60,000	60,000

■ बजट 2023-24 ■ बजट 2022-23 (करोड़ रु.)

* 2022-23 का संशोधित अनुमान कहीं अधिक 89,400 करोड़ रु. था

बजट के मुख्य बिंदु

कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजीगत व्यय

- पूंजी निवेश परिव्यय 33 फीसद बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए या सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 फीसद हो गया
- राज्य सरकारों को 50 साल का ब्याज मुक्त कर्ज 1.3 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक साल तक और जारी रहेगा. इसे 2023-24 के दौरान पूंजीगत व्यय पर खर्च करना होगा
- राज्यों को जीएसडीपी के 3.5 फीसद राजकोषीय घाटे की इजाजत दी जाएगी, जिसमें से 0.5 फीसद बिजली क्षेत्र के सुधारों से जुड़ा होगा.

इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास

- 75,000 करोड़ रुपए के निवेश से 100 महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं शुरू होंगी, जिनमें 15,000 करोड़ रुपए निजी स्रोतों से लिए जाएंगे
- 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट, वॉटर एयरड्रोम और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड फिर से शुरू किए जाएंगे

बैंकिंग और वित्त

- बैंक प्रशासन में सुधार के लिए बैंकिंग रेग्युलेशन ऐक्ट, बैंकिंग कंपनीज ऐक्ट और भारतीय रिजर्व बैंक ऐक्ट में संशोधन किया जाएगा
- सेबी को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स में शिक्षा के लिए मानदंडों और मानकों को विकसित करने, नियंत्रित करने, बनाए रखने और लागू करने और डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र देने की मान्यता देने का अधिकार होगा

कृषि

- किसानों को प्रासंगिक जानकारी सुलभ कराने में मदद के लिए डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर; कृषि-स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने के लिए एक एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड
- अतिरिक्त लंबे स्टेपल कपास की उत्पादकता बढ़ाने के उपाय
- उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों की खातिर रोग मुक्त, गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम के लिए 2,200 करोड़ रुपए
- श्री अन्न या मिलेट्स की खातिर भारत को वैश्विक हब बनाने के वास्ते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रथाओं, अनुसंधान और प्रौद्योगिकियों को साझा करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में हैदराबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च की मदद की जाएगी
- पशुपालन, डेयरी और मछली पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा
- 10,000 बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाए जाएंगे, जो राष्ट्रीय स्तर पर वितरित माइक्रो-फर्टिलाइजर्स और कीटनाशक उत्पादन नेटवर्क का निर्माण करेंगे
- मछुआरों, मछली विक्रेताओं, और सूक्ष्म और लघु उद्यमों का समर्थन करने के लिए 6,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक उप-योजना शुरू की जाएगी
- विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए, अगले पांच वर्षों में बड़ी संख्या में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, प्राथमिक मत्स्य समितियों और डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना की जाएगी
- वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने की खातिर 'पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एमीलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ'

शिक्षा

- शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान विकसित किए जाएंगे
- बच्चों और किशोरों के लिए गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें उपलब्ध कराने की खातिर एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय
- 3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा करने वाले 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले तीन वर्षों में 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी
- शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तीन

"ज्ञान मंजाद रखना"

उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाएंगे

- नए अवसरों, व्यापार मॉडल और रोजगार की संभावनाएं साकार करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 5जी सेवा का उपयोग कर ऐप्लिकेशंस तैयार करने के लिए 100 लैब

स्वास्थ्य

- 2014 से स्थापित मौजूदा मेडिकल कॉलेजों के नजदीक 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे
- 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन शुरू किया जाएगा
- कोलैबोरेटिव रिसर्च एवं इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक और निजी मेडिकल कॉलेज फैकल्टी और निजी क्षेत्र की आरऐंडडी टीमों को अनुसंधान के लिए चुनिंदा आइसीएमआर प्रयोगशालाओं में सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी
- फार्मास्यूटिकल्स में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्रों के माध्यम से नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा
- भविष्य की चिकित्सा प्रौद्योगिकियों, हाइ-ऐंड मैन्युफैक्चरिंग और अनुसंधान के लिए कुशल कामगारों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा संस्थानों में चिकित्सा उपकरणों के लिए समर्पित बहु-विषयक पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहन दिया जाएगा

हरित ऊर्जा

- एनर्जी ट्रांजिशन और नेट जीरो लक्ष्यों, और ऊर्जा सुरक्षा के लिए प्राथमिकता के आधार पर 35,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश
- 4,000 एमडब्ल्यूएच क्षमता वाले बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को वायबिलिटी गैप फंडिंग से सपोर्ट किया जाएगा. पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं के लिए विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाएगी.
- 8,300 करोड़ रुपए की केंद्रीय मदद सहित 20,700 करोड़ रुपए के निवेश से लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी और ग्रिड एकीकरण के लिए इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम का निर्माण किया जाएगा
- कोस्टल शिपिंग को परिवहन के ऊर्जा कुशल और कम लागत वाले साधन के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा

कारोबारी सहूलियत

- 'सबके लिए एक ही योजना' दृष्टिकोण के बजाय 'जोखिम-आधारित' दृष्टिकोण अपनाते हुए केवाइसी प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी
- विभिन्न सरकारी एजेंसियों, नियामकों और विनियमित संस्थाओं की ओर से डिजीलॉकर सेवा और आधार को मूलभूत पहचान के रूप में उपयोग करके व्यक्तियों की पहचान और पते के मिलान और अपडेट करने का काम एक ही स्थान पर किया जाएगा; व्यक्तियों के लिए डिजिलॉकर में उपलब्ध दस्तावेजों का दायरा बढ़ाया जाएगा
- एमएसएमई, बड़े व्यवसाय और धर्मार्थ ट्रस्ट के उपयोग के लिए एक एंटिटी डिजिलॉकर स्थापित किया जाएगा. यह विभिन्न प्राधिकरणों, नियामकों, बैंकों और अन्य व्यावसायिक संस्थाओं के साथ, जब भी आवश्यक हो, दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से ऑनलाइन स्टोर करने, साझा करने के लिए होगा
- वित्तीय और संबंधित जानकारी के केंद्रीय भंडार के रूप में काम करने के लिए एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री बनाई जाएगी
- व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए पैन का उपयोग सामान्य आइडेंटीफायर के रूप में होगा
- फील्ड कार्यालयों में जमा विभिन्न फॉर्मों की केंद्रीकृत हैंडलिंग के माध्यम से कंपनियों को तेजी से प्रतिक्रिया देने के लिए कंपनी अधिनियम के तहत एक सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर बनाया जाएगा; विभिन्न सरकारी एजेंसियों को एक ही सूचना को अलग-अलग प्रस्तुत करने की जरूरत को कम करने के लिए, 'एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया' की प्रणाली तैयार की जाएगी
- सरकार और सरकारी उपक्रमों के ठेके संबंधी विवादों को, जिसमें आर्बिट्रल अवार्ड को किसी अदालत में चुनौती दी गई है, निपटाने के लिए मानकीकृत शर्तों के साथ एक स्वैच्छिक निपटान योजना शुरू की जाएगी

शहरी विकास

- टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए एक अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (यूआइडीएफ); हर साल 10,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे
- सभी शहरों-कस्बों को सेप्टिक टैंक और सीवरों की मशीन से 100 फीसद सफाई के लिए सक्षम बनाया जाएगा

एमएसएमई

- एमएसएमई क्रेडिट गारंटी योजना के लिए 9,000 करोड़ रु.; ऋण की लागत में 1 फीसद की कमी की जाएगी
- कोविड के दौरान करार पूरा करने में एमएसएमई की नाकामी

क्या सस्ता

- हवाई जहाज और अन्य एयरक्रॉफ्ट
- मोबाइल फोन के पार्ट्स
- टीवी पैनल के पार्ट्स

क्या महंगा

- सिगरेट
- नकली जेवरात
- इलेक्ट्रिक किचन चिमनी
- आयातित कारें
- साइकिल
- खिलौने
- चांदी

"दुआ याद रखना"

के मामलों में, बोली या प्रदर्शन सुरक्षा से संबंधित जब्त की गई राशि का 95 फीसद हिस्सा सरकार और सरकारी उपक्रम उन्हें वापस कर देंगे

पर्यटन

- 50 पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा
- घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कौशल और उद्यमिता विकास; वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती गांवों में पर्यटन ढांचा और सुविधाएं तैयार की जाएंगी
- राज्यों को अपने ओडीओपी (एक जिला, एक उत्पाद), जीआइ उत्पादों और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों के प्रचार-बिक्री की खातिर यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा

युवा

- अगले तीन वर्षों में युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0; स्किलिंग के लिए डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का और विस्तार किया जाएगा
- अगले तीन वर्षों में 47 लाख युवाओं को वजीफा देने के लिए अखिल भारतीय नेशनल एप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम

आदिवासी

- विशेष रूप से कमजोर जन जातीय समूहों (पीवीटीजी) की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए, अगले तीन वर्षों के लिए आवंटित 15,000 करोड़ रु. के साथ प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा

महिला

- एकमुश्त छोटी बचत योजना, महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र, दो साल की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा; 7.5 फीसद के फिक्स्ड ब्याज दर पर 2 लाख रु. का निवेश किया जा सकता है

वरिष्ठ नागरिक

- वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए की जाएगी
- मासिक आय खाता योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा एकल खाते के लिए 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए और संयुक्त खाते के लिए 9 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी जाएगी

अन्य घोषणाएं

- स्टार्ट-अप और शिक्षाविदों के नवाचार और अनुसंधान का समर्थन करने के लिए एक नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी
- लैब में बने हीरे (एलजीडी) के बीज (सीड्स) और मशीनों के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने और आयात निर्भरता घटाने के लिए, आइआइटी में से किसी एक को पांच साल के लिए अनुसंधान और विकास अनुदान दिया जाएगा; एलजीडी बीजों पर सीमा शुल्क घटाया गया
- 10,000 करोड़ रु. के निवेश से गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन) योजना के तहत 500 नए 'वेस्ट टू वेल्थ' प्लांट लगेंगे.

लगाएं अपने आयकर का हिसाब

- 7 लाख रुपये तक की सालाना आय वालों के लिए कोई कर नहीं
- यह छूट पाने की शर्तें पूरी करने वाले व्यापारों के लिए अनुमानित कर (अनुमानित आय के आधार पर भुगतान किया जाने वाला कर) की सीमा 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए और निर्दिष्ट व्यवसायों के लिए 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दी गई है.
- 5 लाख रुपए सालाना से अधिक प्रीमियम होने पर जीवन बीमा पॉलिसी की परिपक्वता से होने वाली आय पर कर लगाया जाएगा

नई कर व्यवस्था

आयकर स्लैब	टैक्स दर	सरचार्ज दर	प्रभावी टैक्स दर
3 लाख रुपए तक	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
3 लाख रु. से 6 लाख रु. तक	5%*	लागू नहीं	5.20%
6 लाख रु. से 9 लाख रु. तक	10%*	लागू नहीं	10.40%
9 लाख रु. से12 लाख रु. तक	15%	लागू नहीं	15.60%
12 लाख रु. से15 लाख रु. तक	20%	लागू नहीं	20.80%
15 लाख रु. से 50 लाख रु. तक	30%	लागू नहीं	31.20%
50 लाख रु. से1 करोड़ रु. तक	30%	10%	34.32%
1 करोड़ रु. से 2 करोड़ रु. तक	30%	15%	35.88%
2 करोड़ रु. से 5 करोड़ रु. तक	30%	25%^	39%
5 करोड़ रु. से अधिक	30%	25%	39%

ध्यान दें: *नई व्यवस्था डिफॉल्ट व्यवस्था होगी. अगर निर्धारित कटौती और छूट का लाभ न लिया जाए, तो घटी हुई कर दरों का लाभ उठाया जा सकता है; नई व्यवस्था में वरिष्ठ नागरिकों (60 से अधिक) और अति वरिष्ठ नागरिकों (80 से अधिक) के लिए उच्च छूट सीमा का प्रावधान नहीं है; * जिन निवासी नागरिकों की कुल आय 7 लाख रुपये से अधिक नहीं है, उन्हें 20,000 रुपये तक की छूट; ^दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ, धारा 111 ए के तहत आने वाले अल्पकालिक पूंजीगत लाभ और लाभांश आय के लिए सरचार्ज दर की सीमा 15 फीसद रखी गई है; आयकर और देय सरचार्ज पर 4% उच्च शिक्षा उपकर (सेस) लागू होगा; प्रभावी कर दर = कर की दर और सरचार्ज (यदि लागू हो) + 4% उच्च शिक्षा उपकर. स्रोतः ईवाइ इंडिया*

पुरानी कर व्यवस्था

आयकर स्लैब	टैक्स दर	सरचार्ज दर	प्रभावी टैक्स दर
2.5 लाख रुपए तक	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
2.5 लाख रु. से 5 लाख रु. तक	5%*	लागू नहीं	5.20%
5 लाख रु. से10 लाख रु. तक	20%	लागू नहीं	20.80%
10 लाख रु. से50 लाख रु. तक	30%	लागू नहीं	31.20%
50 लाख रु. से1 करोड़ रु. तक	30%	10%	34.32%
1 करोड़ रु. से 2 करोड़ रु. तक	30%	15%	35.88%
2 करोड़ रु. से 5 करोड़ रु. तक	30%	25%^	39%
5 करोड़ रु. से अधिक	30%	37%^	42.74%

ध्यान दें: *मूल छूट की सीमा अधिक है: 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए 3 लाख रुपये और वरिष्ठ नागरिकों (60 से अधिक) और अति वरिष्ठ नागरिकों (80 से अधिक) के लिए 5 लाख रुपये; * जिन निवासी नागरिकों की कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, उन्हें 12,500 रुपये तक की छूट; ^दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ, धारा 111 ए के तहत आने वाले अल्पकालिक पूंजीगत लाभ और लाभांश आय के लिए सरचार्ज दर की सीमा 15 फीसद रखी गई है; आयकर और देय सरचार्ज पर 4% उच्च शिक्षा उपकर (सेस) लागू होगा; प्रभावी कर दर = कर की दर और सरचार्ज (यदि लागू हो) + 4% उच्च शिक्षा उपकर. स्रोतः ईवाइ इंडिया*

नया ठिकाना : मनप्रीत बादल भाजपा में शामिल होने के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ

मनीष राजपूत

"दुआ में याद रखना"

भाजपा में दलबलुओं की बहार

पंजाब की राज्य इकाई को सहारा देने और चुनावी संभावनाएं चमकाने के लिए चौतरफा सेंध लगाकर भाजपा बाहरी नेताओं को पार्टी में लेकर आई. लेकिन इस रास्ते की अपनी खंदक-खाइयां हैं

अनिलेश एस. महाजन

जनवरी की 18 तारीख की बात है, राहुल गांधी की विशाल भारत जोड़ो यात्रा जब पंजाब के होशियारपुर के घटोटा गांव से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के मनसेर में दाखिल हो रही थी, तब टीवी न्यूज चैनल कांग्रेस में घट रही एक और घटना की तस्वीरें भी दिखा रहे थे. पार्टी के नेता और पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल उसकी धुर विरोधी भारतीय जनता पार्टी के झंडे तले आने को तैयार, पार्टी के दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मुख्यालय में मौजूद थे.

शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) को नियंत्रित करने वाले पंजाब के नामी-गिरामी बादल परिवार के युवा वंशज मनप्रीत उस गहन राजनैतिक हुनर के लिए नहीं जाने जाते जो उनके परिवार के अन्य मशहूर सदस्यों में है. मगर इसके बावजूद भाजपा के लिए वे

बेशकीमती उपलब्धि थे. आखिर क्यों न होते, कांग्रेस को शर्मसार करने के लिए तो उनका इस्तेमाल किया ही जा सकता है. उनके सहारे, एसएडी प्रमुख सुखबीर बादल के गढ़ रहे मुख्य मालवा क्षेत्र में पैठ बनाने की कोशिश भी की जा सकती है. नवंबर 2021 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गद्दीनशीन भाजपा को पीछे हटने और नए कृषि कानून वापस लेने को मजबूर कर दिया गया था, तभी से पार्टी पंजाब में ढलान पर है. कार्यकर्ताओं का मनोबल ध्वस्त है और समर्थन आधार सिकुड़ रहा है. राज्य इकाई की मजबूती के लिए पार्टी ने जल्द ही कांग्रेस और अकाली दल से नेताओं को अपनी तरफ लाने का रास्ता अपनाया. मनप्रीत पाला बदलने वालों की उस फेहरिस्त में नवीनतम हैं जिसमें पूर्व कांग्रेस मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनका परिवार भी शामिल है. बेशक इसका दूसरा पहलू भी है. ये नेता गुटबाजी, भ्रष्टाचार के आरोपों और प्रमुख पदों के लिए जोड़-तोड़ के अपने साजो-सामान के साथ आते हैं. इन नए बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई भी देने लगी है. नए आए कुछ नेताओं ने उनसे किए गए वादे पूरे होने तक पार्टी बैठकों में शामिल होने से इनकार कर दिया. फिर जो कि होना ही था, भाजपा के मूल कार्यकर्ताओं की भौंहे तन गई हैं.

मनप्रीत ने झंडा बदलने का यह कदम ऐसे समय उठाया जब वे हाल में विधानसभा का चुनाव हार चुके थे और उनके धुर विरोधी अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को कांग्रेस की राज्य इकाई का प्रमुख बना दिया गया. अपने दोस्त और पूर्व मुख्यमंत्री चरनजीत चन्नी की तरह बादल पिछले साल मई से नवंबर तक देश के बाहर थे और शायद विदेश के एकांत में उन्हें अहसास हुआ कि कांग्रेस में उनकी कोई गति नहीं है. मनप्रीत अब बठिंडा लौटकर स्थानीय पार्षदों से मिल रहे हैं और भाजपा को इस इलाके में उसका पहला मेयर देने की उम्मीद कर रहे हैं. मगर भगवा पार्टी के लिए अपना कायाकल्प कर पाना उनके लिए मुश्किल होगा.

बीते आठ साल से भाजपा देश भर में अपना विस्तार कर रही है और पंजाब भी उसके राडार पर है. यहां के ग्रामीण मतदाताओं (पंथिक वोटर) में 2015 की गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की घटना और उसके नतीजतन हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद से ही हलचल मची है. आंतक से भरे 1980 और 90 के दशकों में मुठभेड़ विशेषज्ञ रहे पुलिस अफसरों की शीर्ष पदों पर नियुक्ति, राजधानी चंडीगढ़ पंजाब को सौंपने में देरी, और न्यायपालिका व अफसरशाही के शीर्ष पदों पर सिखों की घटती तादाद सरीखे मुद्दों पर भीतर ही भीतर आक्रोश पनप रहा है. अकाली दल और अन्य दलों के कुछ नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार और नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोपों ने आग में घी का काम किया. विश्लेषकों का तो यहां तक कहना है कि 2020-21 में किसान यूनियनों के जबरदस्त विरोध प्रदर्शनों की एक वजह भीतर ही भीतर खदबदाता यह आक्रोश भी था. 2022 के राज्य विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) को इन्हीं भावनाओं का सीधा फायदा मिला. जबरदस्त जीत के करीब एक साल बाद आप के समर्थन आधार में भी बेचैनी घर करने लगी है.

इस सारी उथल-पुथल के बीच यह भी लग रहा है कि पंजाब का मतदाता कांग्रेस और अकाली दल सरीखे पारंपरिक दो ध्रुवीय राजनैतिक मोर्चों से आगे देख रहा है. बीजेपी इसमें मौका ताड़ रही है. मनप्रीत से पहले भाजपा ने अमरिंदर की नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस को अपने मिला लिया, जो उन्होंने सितंबर 2021 में मुख्यमंत्री पद से हटा दिए जाने के बाद बनाई थी. उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा, पर बुरी गत हुई. मार्च 2022 के चुनाव के बाद पिछले मंत्रिमंडल के उनके साथी बलबीर सिद्धू, गुरप्रीत कांगड़ और सुंदर श्याम अरोड़ा भी भाजपा में शामिल हो चुके हैं. कांग्रेस के पूर्व राज्य प्रमुख सुनील जाखड़ ने भी पाला बदल लिया.

भाजपा ज्यादातर दलबदलुओं को राज्य इकाइयों में कीमती पदों से नवाज कर भीतर ला रही है. कांगड़ को महासचिव के पांच पदों में से एक दिया गया. भाजपा के ढांचे में यह अहम ओहदा है क्योंकि उसे पार्टी संगठन चलाने के अलावा उसकी मातृ संस्था आरएसएस व उससे जुड़े दूसरे संगठनों के साथ तालमेल बिठाने का काम करना होता है. फतेहजंग बाजवा, राजकुमार वेरका, अरविंद खन्ना सरीखे कांग्रेस से आए दूसरे नेताओं को राज्य उपाध्यक्ष बनाया गया, तो अमरिंदर और जाखड़ को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिली. मंत्रिमंडल से आए एक अन्य नेता राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी को कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रण दिया गया है.

पंजाब में पार्टी की संभावनाएं बेहतर होने का नैरेटिव खड़ा करने के लिए भाजपा ने इन दलबदलुओं को रणनीतिक तरीके से तमाम टीवी बहसों में जाने का जिम्मा सौंपा है. लिहाजा जो नेता कुछ महीनों पहले तक भाजपा को बुरा-भला कहते थे, वे अब कांग्रेस पार्टी के तौर-तरीकों और पार्टी के भविष्य पर गांधी परिवार के कब्जे वगैरह पर सवाल उठा रहे हैं. जब मनप्रीत पार्टी में आए, तब जाखड़ इस कदम की आलोचना करने वालों से लोहा लेते नजर आ रहे थे.

दूसरे राज्यों में जहां भाजपा मजबूत है, पार्टी तीन चीजों पर ध्यान दे रही है जिनसे हाल में उसे अच्छा फायदा हुआ है—हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और विकास. मगर पंजाब में भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व इन आयातित नेताओं के लिए जगह बनाने की खातिर अपने मूल कार्यकर्ताओं को इस उम्मीद में दरकिनार कर रहा है कि ये नेता पार्टी के लिए चुनावी लिहाज से फायदेमंद साबित होंगे.

पंजाब में भाजपा ने पारंपरिक तौर पर खुद को शहरों और अपने मजबूत आधार वाले हिंदू बहुल इलाकों तक सीमित रखा, जबकि सिख और ग्रामीण वोटों के लिए अपने पूर्व सहयोगी अकाली दल पर निर्भर रही. इन दलबदलुओं (ज्यादातर कांग्रेस से) के जरिए पार्टी दो मकसद पूरे करने की उम्मीद कर रही है—अपने राष्ट्रीय विरोधी को कमजोर करना और पंजाब में अपनी संभावनाएं चमकाना.

पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं. 2019 में भाजपा-एसएडी ने दो-दो सीटें जीतीं, जबकि आठ कांग्रेस और एक आप की झोली में गई थी. बताया जाता है कि 2024 के लिए भाजपा नौ सीटों पर जोर दे रही है. बीते 15 साल से राज्य भाजपा ने अपने पारंपरिक शहरी हिंदू सवर्ण वोटरों से आगे जाकर ज्यादा दलित उन्मुख नेतृत्व खड़ा करने की कोशिश की है. केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रमुख विजय सांपला और पूर्व

इन नए बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई भी देने लगी है. नए आए कुछ नेताओं ने उनसे किए गए वादे पूरे न होने तक पार्टी की बैठकों में शामिल होने से इनकार कर दिया है

"दुआ में याद रखना"

पंजाब के दलबदलू कांग्रेसी

कैप्टेन अमरिंदर सिंह

दो बार मुख्यमंत्री रह चुके अमरिंदर सिंह ने अपनी नई नवेली पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भाजपा में विलय कर दिया. अब वे पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं.

मनप्रीत बादल

अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल के चचेरे भाई मनप्रीत पहले कांग्रेस में गए और अब भाजपा में. इन्हें लोकसभा चुनावों में बठिंडा से हरसिमरत बादल के खिलाफ उतारा जा सकता है.

राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी

पूर्व में मंत्री रह चुके गुरमीत अमरिंदर के करीबी हैं. इन्हें भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित का दर्जा मिला है.

सुनील जाखड़

पूर्व विधान सभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ के बेटे सुनील पंजाब कांग्रेस के मुखिया थे. अब भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं.

राजकुमार वेरका

चरनजीत चन्नी के मंत्रिमंडल में रहे वेरका अब भाजपा की राज्य इकाई के उपाध्यक्ष हैं और पार्टी का दलित-वाल्मीकि चेहरा भी.

अरविंद खन्ना

दो बार विधायक रहे अरविंद उद्योगपति हैं, जिनका संगरूर-बरनाला क्षेत्र में काफी प्रभाव है. अब वे पार्टी की राज्य इकाई के उपाध्यक्ष हैं.

लखविंदर गर्चा

मोहाली से पार्षद रह चुकीं गर्चा ने 2022 में अमरिंदर सिंह के लिए प्रचार किया. अब वे भाजपा की राज्य इकाई की उपाध्यक्ष हैं.

फतेह सिंह बाजवा

कादियान से विधायक फतेह सिंह, कांग्रेस के नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा के छोटे भाई हैं. अब वे भाजपा की राज्य इकाई के उपाध्यक्ष हैं.

केवल ढिल्लों

पूर्व में मंत्री रह चुके ढिल्लों को कांग्रेस ने दरकिनार कर दिया था. अब वे भाजपा की राज्य इकाई के उपाध्यक्ष हैं.

बलबीर सिद्धू

अमरिंदर सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे सिद्धू जून 2022 में भाजपा में शामिल हो गए. वे मोहाली क्षेत्र में काफी सक्रिय हैं.

सुंदर श्याम अरोड़ा

अमरिंदर सरकार में मंत्री रहे. अभी भाजपा में इन्हें जगह मिलना बाकी है. फिलहाल ये भ्रष्टाचार मामले में राज्य सतर्कता ब्यूरो की गिरफ्त में है.

परमिंदर बराड़

अमरिंदर के करीबी ब्रार अब भाजपा की राज्य इकाई में सचिव हैं. अन्य पार्टियों से नेताओं को भाजपा में लाने में इनका काफी योगदान है.

मंत्री भगत चुन्नी लाल बड़ी खोजों में शामिल हैं. पार्टी की नजर अब जाट सिख समुदाय पर भी है. दिसंबर में भाजपा की राज्य इकाई के पुनर्गठन और जिला प्रमुखों की नियुक्ति के बाद 27 शीर्ष पदाधिकारियों में से 11 इसी समुदाय के हैं. ज्यादातर पदाधिकारी अब वाकई पूर्व कांग्रेसी हैं और यह बात पंजाब में भाजपा और आरएसएस के पुराने लोगों को रास नहीं आ रही है. किसान यूनियनों के आंदोलन और भाजपा नेताओं के खिलाफ हुई हिंसा की यादें उनके दिमाग में अभी ताजा हैं. अबोहर से पार्टी के विधायक अरुण नारंग जब नए कृषि कानूनों के बारे में समझाने के लिए गए, मौर मंडी में उन्हें बेरहमी से पीटा गया था. राज्य भाजपा के कई नेता यह मानते बताए जाते हैं कि इसके पीछे जाखड़ परिवार था. इसी तरह जुलाई 2021 में किसान यूनियनों ने राजपुरा में पटियाला इकाई के प्रमुख विकास शर्मा के साथ मार-पीट की थी और अन्य भाजपा नेताओं के साथ उन्हें घंटों बंधक बनाए रखा था. तब पुलिस के नाकारापन के लिए मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को दोषी ठहराया गया था. अब भाजपा ने शर्मा की जगह अमरिंदर के वफादार सुरजीत सिंह गढ़ी को पटियाला नॉर्थ का प्रमुख बना दिया है. उनके वफादारों को पटियाला साउथ और शहर जिले में भी पद मिले हैं. भाजपा के पुराने लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए फ्लेक्सों पर अमरिंदर के तस्वीरें लगाने से इनकार कर दिया. राज्य भाजपा के एक नेता कहते हैं, ''हम उनकी भावनाएं समझते हैं और मानते हैं कि हमारे पास उनके सवालों के जवाब नहीं हैं.'' वे कहते हैं कि पार्टी के फूलने-फलने के लिए त्याग करना जरूरी था.

पार्टी की दुश्वारियां यहीं खत्म नहीं होतीं. भाजपा अकाली दल से भी नेताओं को ला रही हैं और कई जगहों पर हालात विस्फोटक हैं. मसलन, अकाली दल में मनप्रीत के विरोधी सरूप सिंगला और जस्सी जसराज अब भाजपा में हैं. सिंगला ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए मनप्रीत के खिलाफ राज्य सतर्कता ब्यूरो में शिकायत दर्ज की है, जिसे वे वापस लेने को राजी नहीं हैं. जाखड़ का भी फतेहजंग बाजवा और भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अपने साथी राणा सोढ़ी के साथ झगड़ों का इतिहास रहा है. इसी तरह अरविंद खन्ना और केवल ढिल्लों संगरूर में एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं.

इस बीच गद्दीनशीन आप सरकार ने कांग्रेस के कई दलबदलुओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच तेज कर दी है. सुंदर श्याम अरोड़ा को भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि बलबीर सिद्धू, कांगड़ और वेरका सरीखे दूसरे नेता भी सतर्कता ब्यूरो के राडार पर हैं. दिल्ली में भाजपा के नेता आस बांधे हुए हैं कि सुखबीर बादल की अगुआई वाले अकाली दल में चल रही जद्दोजहद और कांग्रेस की दुश्वारियों के चलते भगवा पार्टी को फिर से खड़ा होने के लिए वक्त और जगह मिल जाएगी. भाजपा के दलबदलुओं के लिए चुनावी इम्तहान जल्द ही आने वाला है—शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव और जालंधर लोकसभा सीट का उपचुनाव अब तकरीबन सिर पर है. ■

"दुआ में याद रखना"

INDIA TODAY

BREAKING NEWS

JUST A TAP AWAY

DOWNLOAD THE APP NOW

AVAILABLE ON

आज तक

देश का नं. 1 हिंदी न्यूज़ ऐप

जुड़े रहिए हर खबर से,
कहीं भी, कभी भी

अभी डाउनलोड करें

aajtak.in/app

उपलब्ध है

नया दांव
अगरतला में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ त्रिपुरा के नए सीएम मणिक साहा. दिसंबर 2022 की तस्वीर

"दुआ में याद रखना"

एएनआइ

विधानसभा चुनाव 2023

उत्तर-पूर्व

पूर्वोत्तर में मुकाबला

त्रिपुरा, नगालैंड और मेघालय के विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए पूर्वोत्तर में पैठ बनाने का मौका हैं. इनका असर इस साल होने जा रहे अन्य राज्यों के चुनावों पर भी दिखेगा

कौशिक डेका

पूर्वोत्तर के तीन राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नगालैंड में लोकसभा सीटें भले ही सिर्फ पांच हैं लेकिन फरवरी में यहां होने जा रहे विधानसभा चुनावों के नतीजे केंद्र और 14 राज्यों में सत्ता पर काबिज भाजपा के लिए महत्वपूर्ण हैं. साल के अंत में उसके सामने कर्नाटक और मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बचाए रखने की चुनौती होगी, साथ ही उसे राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में सत्ता के लिए लड़ना होगा. ऐसे में 2 मार्च को इन तीन राज्यों के नतीजे अगर भाजपा के पक्ष में आए, तो आगे का रास्ता आसान हो जाएगा. दूसरी तरफ, दशकों तक इस क्षेत्र में सत्तासीन रही कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने को लड़ रही है. त्रिपुरा और नगालैंड विधानसभाओं में इसका सूपड़ा साफ है, वहीं पिछली बार मेघालय में सबसे बड़ा दल बनकर उभरी कांग्रेस के सभी विधायक अन्य दलों में शामिल हो चुके हैं. हाल यह है कि अब भाजपा को पूर्वोत्तर में अपने विस्तार की योजना में थोड़ी-बहुत चुनौती क्षेत्रीय दलों से ही मिल रही है.

त्रिपुरा

त्रिपुरा एकमात्र ऐसा पूर्वोत्तर राज्य है जहां 2018 में भाजपा ने 60 सदस्यीय विधानसभा में 36 सीटें जीतकर अपने बलबूते बहुमत हासिल करते हुए दो दशक से अधिक समय तक सत्ता में रहे वाम मोर्चा को हराया. यहां आदिवासी पार्टी इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ

2018 में क्या था सूरत-ए-हाल

त्रिपुरा में सीपीआइ(एम) को हराकर भाजपा सत्ता में आई. नगालैंड और मेघालय में भाजपा ने स्थानीय पार्टियों के साथ सरकार बनाई

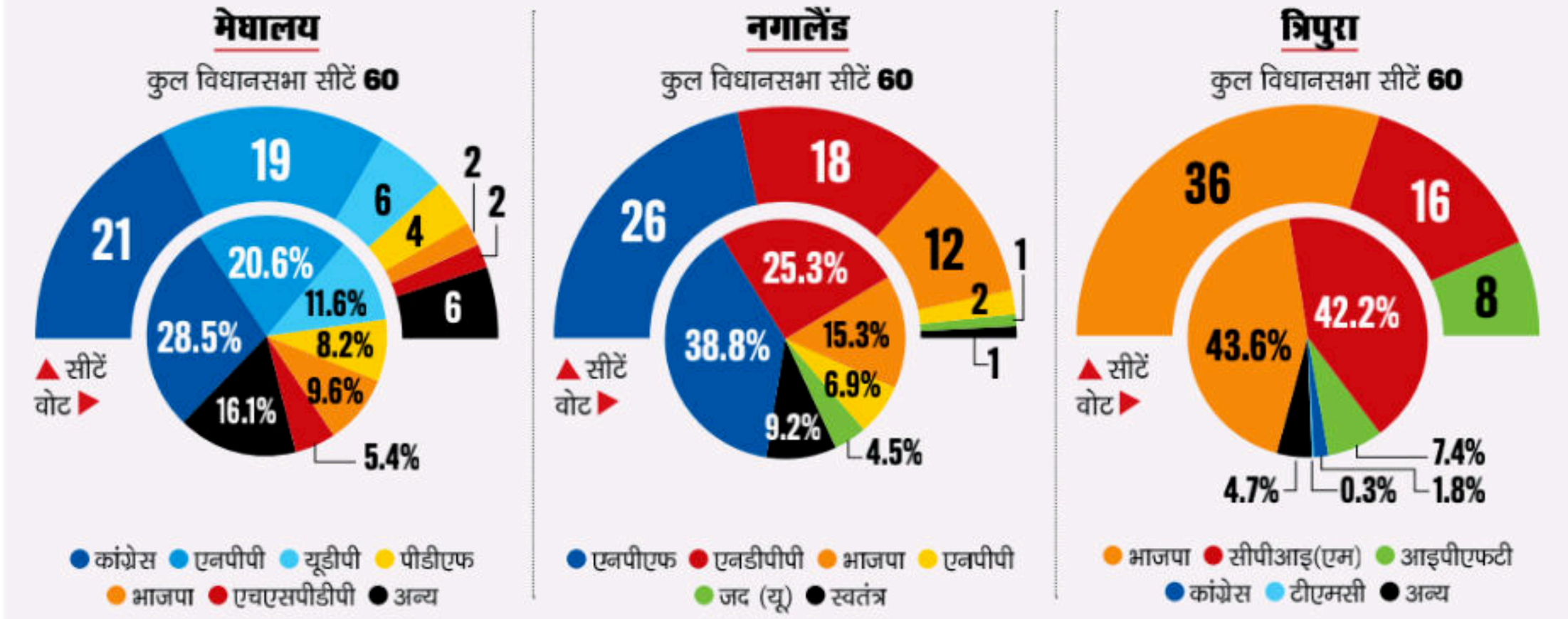

त्रिपुरा (आइपीएफटी) के साथ गठबंधन ने आदिवासियों के लिए सुरक्षित 20 सीटों में से 18 जीतने में मदद की (भाजपा ने 10 और आइपीएफटी ने 8 सीटें जीतीं).

अब, पांच साल बाद भाजपा सत्ता विरोधी लहर, उभरते विपक्षी गठबंधन और एक नई जनजातीय ताकत के उदय जैसी कई चुनौतियों से रू-ब-रू है. विपक्षी दलों ने वादे पूरे करने में नाकाम रहने और बढ़ती राजनीतिक हिंसा को लेकर सरकार को घेरा तो भाजपा ने इसका जवाब ऐन चुनाव से 10 महीने पहले मुख्यमंत्री बदलकर दिया—बिप्लब देब की जगह माणिक साहा सीएम बने. भाजपा को दो परंपरागत प्रतिद्वंद्वियों, माकपा और कांग्रेस के गठबंधन से भी सतर्क रहना होगा. 2018 में माकपा 16 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि कांग्रेस खाली हाथ रही. बहरहाल, एक तथ्य यह भी है कि माकपा का 42 फीसद वोट शेयर भाजपा के 44 फीसद वोट शेयर से बहुत पीछे नहीं था. नया गठबंधन, जिसके तहत माकपा 46 सीटों पर और कांग्रेस 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, सियासी समीकरण बदल सकता है. कांग्रेस इससे थोड़ी राहत महसूस कर सकती है कि उसने 2019 के लोकसभा चुनावों में अपना वोट शेयर, 2018 के 2 फीसद से सुधारकर 25 फीसद कर लिया था. फिर तृणमूल कांग्रेस भी मैदान में है, जो वामपंथियों और कांग्रेस के वोटबैंक पर नजरें टिकाए है और बंगाली बहुल क्षेत्रों में अन्य दलों के वोटों में सेंध लगा सकती है.

भाजपा के लिए सबसे बड़ी चिंता टिपरा मोथा है. शाही वंशज प्रद्योत माणिक्य देबबर्मा के नेतृत्व में यह पार्टी काफी हद तक खुद को मूल जनजातियों की अगुआ के तौर पर स्थापित करने में सफल रही है, जिनकी त्रिपुरा की आबादी में करीब 30 फीसद हिस्सेदारी है. भाजपा ने मोथा से गठबंधन की कोशिश की, लेकिन वह विफल रही क्योंकि देबबर्मा ने दो-टूक कह दिया कि उनकी पार्टी ग्रेटर तिप्रालैंड गठन के लिखित आश्वासन के बिना किसी से हाथ नहीं मिलाएगी. उनकी मांग है कि टीटीएएडीसी के तहत आने वाले क्षेत्र और 36 गांवों को मिलाकर अलग राज्य बनाया जाए.

मेघालय में मुख्य विपक्षी पार्टी टीएमसी उत्तरपूर्व में अपनी पहली जीत का दांव मुकुल संगमा और प्रशांत किशोर की आइ-पैक के भरोसे खेल रही है

मेघालय

मुकुल संगमा के नेतृत्व में दो बार सत्ता में रही कांग्रेस 2018 में 21 सीटें जीत सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि कॉनराड संगमा की पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) ने 19 सीटें जीतीं. एनपीपी ने अंततः भाजपा, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी (यूडीपी), पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट (पीडीएफ) और हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (एचएसपीडीपी) और कुछ निर्दलीय विधायकों के साथ एक इंद्रधनुषी सरकार बनाई. 75 फीसद ईसाई आबादी वाले मेघालय में दो विधायकों के साथ यह भाजपा की पहली जीत थी.

मेघालय में 27 फरवरी को मतदान होगा. एनपीपी भाजपा से नाता तोड़ चुकी है और मुकुल संगमा टीएमसी का चेहरा बन चुके हैं. राज्य चतुष्कोणीय मुकाबले के लिए तैयार है, जिसमें एनपीपी, भाजपा, कांग्रेस और टीएमसी किस्मत आजमा रही हैं. उम्मीदवार की निजी लोकप्रियता के आधार पर चुनावी जीत या हार निर्धारित करने वाले इस राज्य के बारे में राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि नितांत स्थानीय मुद्दे, जिसमें ज्यादातर आदिवासी समुदायों से जुड़े हैं, ही महत्वपूर्ण साबित होंगे.

भाजपा का दावा है कि वह 2018 की दो सीटों की तुलना में इस बार आंकड़ा 10-15 तक पहुंचा देगी. पार्टी की राज्य इकाई को कुछ मुद्दों पर अपने राष्ट्रीय रुख से पीछे हटने में भी कोई परहेज नहीं है. उदाहरण के तौर पर भाजपा के दो विधायकों में से एक संबोर शुल्लई सार्वजनिक तौर पर लोगों को अधिक गोमांस खाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं.

राज्य में कांग्रेस ही सबसे बुरी स्थिति में नजर आ रही है. 2018 के बाद सबसे पहले तो इसने चार विधायक गंवाए, जिसमें एक ने इस्तीफा दे दिया जबकि तीन की मृत्यु हो गई. नवंबर 2021 में मुकुल संगमा और 11 अन्य विधायक टीएमसी में शामिल हो गए और फिर पांच विधायकों ने एनपीपी के नेतृत्व वाली सरकार को अपने समर्थन की घोषणा कर दी जिसके बाद पार्टी आलाकमान ने उन्हें

इन पर है दांव

त्रिपुरा

माणिक साहा, 70 वर्ष
मुख्यमंत्री

कांग्रेसी साहा 2016 में भाजपा में आए. 2022 में पार्टी में बढ़ते असंतोष और सत्ता विरोधी लहर को साधने के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया. इन्हें सीपीआइ(एम) गठबंधन और नई आदिवासी पार्टी टिपरा मोथा से लोहा लेने का जिम्मा मिला है.

माणिक सरकार, 74 वर्ष
पूर्व मुख्यमंत्री

सीपीआइ(एम) के नेता पर मुकाबले का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी है. इन्होंने पुरानी विरोधी कांग्रेस से हाथ मिलाया है.

प्रद्योत माणिक्य देववर्मा, 44 वर्ष
प्रमुख, टिपरा मोथा

इस पूर्व कांग्रेसी ने आदिवासी हितों की लड़ाई के लिए नई पार्टी बनाई, जिसने 2021 में जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद का चुनाव जीता. यह पार्टी 20 एसटी सीटों फैसलाकुन किरदार निभा सकती है.

मेघालय

कॉनराड संगमा, 45 वर्ष
मुख्यमंत्री

एनपीपी प्रमुख के लिए पूर्व कांग्रेसी व सीएम मुकुल संगमा के नेतृत्व में बढ़ती टीएमसी की ताकत और पिछली बार सहयोगी रही भाजपा सबसे बड़ी चुनौतियां हैं.

मुकुल संगमा, 57 वर्ष
पूर्व मुख्यमंत्री

पूर्व कांग्रेसी मुकुल पिछले साल कई विधायकों के साथ टीएमसी में आए. प्रशांत किशोर की आइ-पैक इनकी मदद कर रही है. ये बड़े बदलाव का बायस हो सकते हैं.

नगालैंड

नेफ्यू रियो, 72 वर्ष
मुख्यमंत्री

नगालैंड की राजनीति के बड़े चेहरे रियो के सामने खास चुनौतियां नहीं हैं. अगर कोई समस्या हो सकती है, तो वह है सहयोगी भाजपा से किया गया सीटों का समझौता.

दुआएं याद रखना

निलंबित कर दिया. उनमें से दो बीते दिसंबर में भाजपा में शामिल हो गए. रातोरात राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी बनी तृणमूल कांग्रेस अब पूर्वोत्तर में अपनी पहली जीत हासिल करने के लिए मुकुल संगमा के सियासी असर और प्रशांत किशोर की आई-पैक के चुनावी प्रबंधन से आसरा लगाए बैठी है. हालांकि मुकुल का प्रभाव क्षेत्र गारो हिल्स है, जहां पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पी.ए. संगमा की राजनीतिक विरासत संभालने वाले कॉनराड और उनके रिश्तेदार अहम खिलाड़ी बने हुए हैं.

गारो हिल्स में 24 विधानसभा सीटें (करीब 20 फीसद आबादी) आती हैं, जबकि बाकी सीटें खासी जनजाति के वर्चस्व वाली खासी हिल्स और आमतौर पर जयंतिया जनजाति बहुल आबादी वाली जयंतिया हिल्स में आती हैं. कॉनराड और मुकुल, दोनों के लिए यह लड़ाई गारो हिल्स पर पकड़ बनाए रखने से ज्यादा खासी बहुल क्षेत्रों में भी अधिकतम सीटें जीतने की भी है.

नगालैंड

इस चुनाव में नगालैंड की मौजूदा सरकार के सामने सबसे कम चुनौती नजर आ रही है. यूं भी कह सकते हैं कि उसे शायद ही कोई विरोध झेलना पड़ रहा है. सितंबर 2021 में नगालैंड विधानसभा में प्रमुख विपक्षी दल नगा पीपल्स फ्रंट (एनपीएफ) भी राष्ट्रवादी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी) के नेतृत्व वाली सरकार का हिस्सा बन गया, जिससे राज्य विपक्ष-विहीन हो गया. 2018 में एनपीएफ 60 सदस्यीय सदन में 26 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरा. हालांकि, एनडीपीपी ने सरकार बनाई, जिसने भाजपा के साथ गठबंधन में 18 सीटें जीती थीं, और भाजपा ने 12 सीटों पर जीत हासिल की थी. पूर्वोत्तर में भाजपा के सबसे पुराने सहयोगी एनपीएफ से मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के अलग होने के बाद ही 2018 में एनडीपीपी अस्तित्व में आया था.

लंबे समय से अटके नगा राजनीतिक मुद्दे को 'शांतिपूर्ण ढंग से और परस्पर सौहार्द के साथ हल करने की दिशा में सामूहिक प्रयास' के इरादे के साथ एनपीएफ रियो सरकार का हिस्सा बना. हालांकि, इसका कोई समाधान नजर न आने के बीच 2022 में एनपीएफ के 21 विधायक एनडीपीपी में शामिल हो गए. और 2023 की चुनावी दौड़ में सरकार का हिस्सा होने के बावजूद पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है. एनडीपीपी-भाजपा गठबंधन ने अपना सीट बंटवारे का फॉर्मूला—एनडीपीपी को 40 और भाजपा को 20—घोषित किया है. इसमें एनपीएफ के लिए कोई जगह नहीं है. वहीं कांग्रेस भी कुछ ऐसे ही हाल से गुजर रही है, जिसके पास एक भी विधायक नहीं है. उसे अपनी जगह बनाने के लिए जदयू, राजद, आप और एनपीपी जैसी पार्टियों के साथ मुकाबला करना पड़ रहा है.

सुचारु ढंग से जारी रहने के आश्वासन के बावजूद एनडीपीपी-भाजपा गठबंधन आंतरिक चुनौतियों से जूझ रहा है. मौजूदा विधानसभा में एनडीपीपी के पास 48 विधायक हैं. लेकिन सीट-बंटवारे के समझौते के मुताबिक, पार्टी केवल 40 पर ही प्रत्याशी उतार सकती है. ऐसे में बाकी को दूसरे दल अपने पाले में लाने के लिए लुभा सकते हैं. 24 जनवरी को चार बार के विधायक और पूर्व मंत्री इमकोंग एल. एमचेन भाजपा में शामिल हुए थे. सीट बंटवारे पर 40:20 की व्यवस्था भी असंतोष का कारण बनी हुई है, राज्य भाजपा के कई नेताओं को लगता है कि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में संगठन खड़ा करने के लिए की गई मेहनत बेकार चली जाएगी यदि वे सीटें एनडीपीपी के लिए 'छोड़ी' गईं. इसके अलावा, 'टिकट मिलने के आश्वासन' पर भाजपा में शामिल हुए नेता भी अब बगावत पर उतारू हैं.

बहरहाल, भाजपा के शीर्ष नेता इस सबको लेकर बहुत चिंतित नहीं हैं, बहुत सारी बातों का घालमेल करीब 90 फीसदी ईसाई आबादी वाले राज्य में पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ने का ही संकेत देता है. अब जबकि भारत इस वर्ष जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की तैयारी में लगा है, भाजपा इसे वैश्विक मंच पर समावेशिता के एक शानदार उदाहरण के तौर पर प्रदर्शित कर सकती है. ■

खास रपट **बिहार जीविका**

आमदनी नहीं इकन्नी जिम्मेदारी सोलह आना

इन दिनों अपनी समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर जगह जीविका दीदियों से मिलकर उनकी सराहना करते हैं पर 2007 में बिहार में शुरू जीविका मिशन से जुड़ीं ये 1.3 करोड़ महिलाएं इसका लाभ ले पाने से कोसों दूर. सार्वजनिक मंचों पर आत्मविश्वास से भरी दिखने के बावजूद ये दीदियां अभी तक भी आत्मनिर्भर न हो सकीं

पुष्यमित्र

कामकाज
अरण्यक एग्री प्रोड्यूसर कंपनी के गोदाम में टैब पर हिसाब करतीं जीविका दीदियां

अपनी खाद और बीज की दुकान भी है. पिछले साल हमने 5.5 करोड़ रुपए के मक्के का कारोबार किया.'' पर जब उनसे पूछा जाता है कि पिछले 13-14 साल में कंपनी से उन्हें क्या हासिल हुआ, तो वे चुप्पी लगा जाती हैं. बहुत कुरेदने पर कहती हैं, ''हमलोगों को क्या लाभ होगा? कंपनी जो कमाती है, उसका ज्यादातर हिस्सा कंपनी के दफ्तर, स्टाफ और दुकान के मेंटेनेंस में खर्च हो जाता है. इस वक्त कंपनी में 150 से ज्यादा का स्टाफ काम करता है, उनको वेतन दिया जाता है. बचेगा क्या? हमको तो बस दो बार बोनस मिला. एक बार 8,000 रुपए और एक बार 3,000 रुपए. बस.''

अरण्यक एग्री प्रोड्यूसर कंपनी को मुंबई की नेशनल कमोडिटी ऐंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (नेस्डेक्स) संस्था वायदा कारोबार में बेहतरीन प्रयोग के लिए सम्मानित कर चुकी है. कंपनी के सीईओ की तनख्वाह 75,000-1,00,000 रु. महीने के बीच है. अकाउंटेंट तक की सैलरी 30,000 रुपए से ज्यादा है. मगर अपनी ही कंपनी के लिए परिवार गरीब है, जहां रोज की आय प्रति व्यक्ति दो डालर यानी 160 रुपये से कम हो. अगर जीविका दीदियों का पांच लोगों का भी परिवार है, तो ज्यादातर परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 40 रुपये से भी कम ठहरती है.''

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों अपनी समाधान यात्रा के तहत पूरे बिहार की यात्रा पर हैं. इस दौरान आमलोगों में वे सिर्फ जीविका दीदियों से ही मिलते हैं. 29 जनवरी को कैमूर में जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ''आपकी संख्या बहुत बढ़ी है, यह देखकर मुझे खुशी होती है. स्वयं सहायता समूह से अब 1.30 करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ गई हैं. 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह का गठन हुआ है. पहले महिलाएं सिर्फ घर में काम करती थीं, अब पुरुष के साथ महिलाएं भी कमा रही हैं जिससे परिवार की अच्छी आमदनी हो रही है. महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो समाज भी आगे बढ़ेगा.''

यह सच है कि 2007 में शुरू हुई जीविका संख्या के मामले में लगातार बढ़ रही है. इन्हें

"जीविका दीदियों का आर्थिक विकास तो थोड़ा हुआ है, लेकिन इनमें सामाजिक जागरूकता न के बराबर नजर आती है''

—शाहीना परवीन,
सामाजिक कार्यकर्ता

पूर्णिया जिले के ढोकवा गांव की किरण देवी 'अरण्यक एग्री प्रोड्यूसर कंपनी' की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सदस्य हैं. अरण्यक पहली कंपनी है, जिसे बिहार में स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में जुटी संस्था जीविका ने शुरू किया था. किरण देवी याद करती हैं, ''25 नवंबर 2009 को यह कंपनी स्थापित हुई थी. पहले इसमें शेयर धारक के रूप में सिर्फ 1,200 महिलाएं जुड़ी थीं. अब संख्या 5,753 हो चुकी है. कंपनी मक्का, मखाना और केला जैसे कृषि उत्पादों को किसानों से खरीदती है और फिर उन्हें ऊंची कीमत में बेचती है. इसके अलावा कंपनी की खट रहीं किरण देवी और उनके जैसी दूसरी जीविका दीदियों को हर साल औसतन एक हजार रुपए भी हासिल नहीं हो पा रहे. सारा लाभांश स्टाफ और मेंटेनेंस पर खर्च.

किरण देवी ही नहीं, बिहार में महिलाओं की आर्थिक सफलता के रूप में प्रचारित जीविका संस्था से जुड़ी 1.30 करोड़ से ज्यादा महिलाओं की यही कहानी है. तमाम कोशिशों के बावजूद जीविका से जुड़ी 65 फीसद महिलाओं की पारिवारिक मासिक आय 6,000 रु. महीने से कम है (देखें बॉक्स).

पटना स्थित एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट के पूर्व निदेशक डीएम दिवाकर कहते हैं, ''अगर आंकड़े यही हैं तो बिहार की ये जीविका दीदियां आज भी गरीबी की स्थिति में ही हैं. विश्व बैंक का मानक कहता है कि हर वह बैंकों से 26,708 करोड़ रु. का कर्ज मिला हुआ है. जीविका की तरफ से 14,000 करोड़ रु. का सपोर्ट ऊपर से. यानी कुल सपोर्ट 40,000 करोड़ रु. का. डीएम दिवाकर कहते हैं, ''इतने बड़े मैनपावर और धनराशि के दम पर 15 साल में एक संस्था के रूप में जीविका से जिस स्तर की उपलब्धि की आशा की गई थी, वह अब जमीन पर नहीं दिखती.''

जीविका के सीईओ राहुल कुमार कहते हैं, ''यह सच है कि हम जीविका को एक ऐसे ब्रांड के रूप में तैयार नहीं कर पाए जिसकी देश के हर कोने में मौजूदगी हो. मगर हम इस कोशिश में जुटे हैं. हमने अपने तीस उत्पादों की सूची तैयार की है, इनमें कुछ फूड प्रोडक्ट होंगे, कुछ क्राफ्ट बेस्ड. इनमें मधु और मखाना जैसे उत्पादन होंगे और मधुबनी

पेंटिंग और सिक्की के उत्पाद. हमने अपना ब्रांड लोगो और टैग लाइन फाइनल कर लिया है. अपने पोर्टल को इस रूप में विकसित कर रहे हैं, जिससे लोग आसानी से हमारे उत्पाद ऑनलाइन खरीद सकें.''

जीविका उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर बेचने की प्रक्रिया बहुत शुरुआती रूप में है जबकि एक स्वयं सहायता समूह अभियान को तभी सफल माना जाता है, जब उसको संचालित करने वाली संस्था 10 साल में खुद को समूहों से अलग कर ले और इस दौरान बने समूह और विकसित कंपनियां आत्मनिर्भर हो जाएं. राहुल के शब्दों में, इस अभियान से बाहर निकलने के बारे में ''सच तो यह है कि अभी हमने इस संबंध में कुछ सोचा भी नहीं है.''

राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री के तौर पर 2010 से 2015 तक इस अभियान से जुड़े रहे नीतीश मिश्र की राय में, ''लगता है, जीविका महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के बदले खुद की संस्था को ही किसी पीएसयू के रूप में स्थापित करने की कोशिश में है.''

इस वक्त जीविका में 8,000 से अधिक प्रोफेशनल ऊंची सैलरी पर काम कर रहे हैं. और 90,000 जमीनी कार्यकर्ता पूरे राज्य में जीविका के लिए काम करते हैं. सबकी सैलरी जीविका अभियान से दी जाती है. मगर जीविका दीदियों की अपनी आय राज्य के प्रति व्यक्ति के आसपास भी नहीं पहुंच पा रही. मिश्र आगे जोड़ते हैं, ''हमने जीविका को अच्छे मकसद के साथ शुरू किया था. यह एक तरह की मौन क्रांति थी. शुरुआती दौर में यह मकसद को हासिल करने में सफल भी रही. मगर बाद के वर्षों में इसका विकास ठिठक रहा दिखता है.''

मिश्र की बात अक्तूबर, 2020 में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट से भी जाहिर होती है. इस अध्ययन रिपोर्ट में बिहार की जीविका पर एक अलग अध्याय है. इसमें बताया गया है, ''ऐसा लगता नहीं कि जीविका दीदियों की स्थिति में 2017 के मुकाबले ज्यादा बदलाव हुआ है. 2017 के पहले असेसमेंट की रिपोर्ट जैसी स्थिति आज भी है. साथ ही यह भी दिख रहा है कि महिलाओं के सशक्तिकरण की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है, जबकि उन्हें रोजगार मिलने की संभावना घटी है. रिपोर्ट कहती है कि समूहों पर समृद्ध महिलाओं का कब्जा है और कर्ज बांटने के मामले में असमानता बरती जाती है. क्षेत्र में पलायन की दर तेज हुई है और समूहों के जरिए जीविका सदस्यों को होने वाली पारिवारिक आय में कमी आई है.''

''शुरुआती दौर में जीविका अपने मकसद को हासिल करने में सफल रही. मगर बाद के वर्षों में इसका विकास ठिठक गया''

—नीतीश मिश्र,
पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री, बिहार

ऐसे में जब जीविका के सीईओ राहुल कुमार से पूछा जाता है कि उनकी नजर में जीविका दीदियों की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो उनका उत्तर होता है: ''आत्मविश्वास.''

यह सच है कि पिछले 15 साल में जीविका से जुड़ी इन महिलाओं का आत्मविश्वास काफी बढ़ा है. मुख्यमंत्री के साथ बैठकों में ये घरेलू ग्रामीण महिलाएं पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखती नजर आती हैं. वे अकेले बैठकों में जाती हैं, लोन लेने और देने से जुड़े फैसले करती हैं. ट्रेनिंग लेने और देने

"दुआ में याद रखना"

जीविका के आंकड़े

कुल समूह
10,45,628

जीविका दीदियों की संख्या
1,30,00,584

बैंक से जुड़े जीविका समूहों की संख्या
9,27,295

कृषि उत्पाद कंपनियों की संख्या
33

दीदी की रसोइयों की संख्या
79

जीविका बाजार की संख्या
136

बैंक से कुल लोन
26,708.44 करोड़ रु.

जीविका से कुल सहायता
14,000 करोड़ रु.

समूहों की अपनी आय
2,000 करोड़ रु.

रीपेमेंट की दर
98.5 फीसद

आपसी लेन-देन में ब्याज की दर
1 फीसद

मुलाकात
समाधान यात्रा के दौरान जीविका दीदियों को चेक सौंपते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, साथ में जीविका के सीईओ राहुल कुमार

के लिए दूर-दराज की यात्राएं भी करती हैं. इससे इन महिलाओं की राजनीतिक क्षमता में भी बढ़ोतरी हुई है. हाल के पंचायती राज चुनाव में इनमें से 483 महिलाएं मुखिया के पद पर चुनी गईं तो 21,549 महिलाएं अलग-अलग पदों पर चयनित हुईं.

बिहार के गांवों में महाजनी प्रथा की समाप्ति भी इसकी एक उपलब्धि मानी जाती है. राहुल कहते हैं, ''पहले गांव के गरीब लोगों को 5 से 10 फीसद तक मासिक ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता था, अब लोग जीविका के माध्यम से महज एक फीसद मासिक दर पर कर्ज ले रहे हैं. अब महाजनी शहरों और कस्बों तक ही सीमित होकर रह गई है. बैंक भी जीविका के समूहों को आसानी से कर्ज देते हैं, क्योंकि उनकी रीपेमेंट दर 98.5 फीसद है.''

माना जाता है कि ये महिलाएं सामाजिक रूप से भी सजग हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कहते हैं कि उन्होंने शराबबंदी का फैसला एक जीविका दीदी के कहने पर लिया था. मगर शराबबंदी, बाल विवाह और दहेज प्रथा विरोधी अभियानों में इनकी भागीदारी बहुत कम नजर आती है. पंचायत से जुड़ी महिलाओं और किशोरियों के बीच काम करने वाली संस्था हंगर प्रोजेक्ट से जुड़ी शाहीना परवीन कहती हैं, ''इन महिलाओं का आर्थिक विकास तो थोड़ा-बहुत हुआ है, मगर सामाजिक जागरूकता न के बराबर लगती है. राज्य सरकार बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ बड़ा अभियान चला रही है. मगर जीविका दीदियां इस अभियान में बहुत कम शामिल होती हैं. बाल विवाह के खिलाफ सूचना या शिकायत करने वाली ज्यादातर छोटी बच्चियां होती हैं. इन जीविका दीदियों ने कभी न आसपास हो रही दहेज वाली शादियों को रोकने की कोशिश की, न बाल विवाह को. इन्हें कभी इस दिशा में जागरूक भी नहीं किया गया. तभी तो समाधान यात्रा में मुख्यमंत्री को अपील करनी पड़ी कि जीविका दीदियां शराबबंदी और बाल विवाह को रोकने में आगे आएं.''

बिहार सरकार का मानना है कि देश भर में जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत हुई, वह बिहार की जीविका से ही प्रभावित थी. महिलाओं के जुड़ाव के मामले में भी बिहार सबसे आगे है. पूरे देश में आजीविका मिशन के तहत अब तक सिर्फ 8.8 करोड़ महिलाओं को ही जोड़ा जा सका है जबकि बिहार में अकेले 1.3 करोड़ जीविका दीदियां हैं. पर उपलब्धियों के मामले में बिहार दूसरे राज्यों के मुकाबले सबसे आगे नहीं दिखता. अक्तूबर, 2020 की असेसमेंट रिपोर्ट में भी कहा गया है कि एक समय में बने स्वयं सहायता समूहों में दूसरे राज्यों के मुकाबले बिहार की स्थित कमजोर नजर आती है.

शुरुआती दिनों में जीविका ने बेहतरीन मॉडल खड़ा किया था. तब छह जिलों के 102 प्रखंडों में इसका काम हो रहा था. मगर जब 2012-13 इसका विस्तार पूरे राज्य के सभी 534 प्रखंडों में हुआ तो इसकी गुणवत्ता कमजोर होने लगी और प्रभाव घटने लगा. नीतीश मिश्र कहते हैं, ''दरअसल हुआ यह कि जीविका की शुरुआती सफलता से प्रभावित होकर बिहार सरकार ने अपनी हर असफल परियोजना का जिम्मा जीविका को देना शुरू कर दिया. पीडीएस भी वही चलाएंगी, अस्पतालों के किचन और साफ-सफाई का जिम्मा भी उन्हीं का होगा, स्कूलों की देखरेख भी वही करेंगी. कोरोना में मास्क भी वही तैयार करेंगी. एक तरह से सरकार अपनी फेल हो रही संस्थाओं की जिम्मेदारी उन्हें सौंपती चली गई. अब उनकी ताकत अपने उत्थान के बदले सरकार की नाकामियों को ठीक करने में लग रही है. सरकार लगातार उनपर निर्भर हो रही है. यह अपने आप में बहुत पवित्र अभियान है. मगर इसका खुद का विकास ठहर-सा गया है.''

पूर्णिया की किरण देवी जैसी महिलाओं के हावभाव से मिश्र के दावे की पुष्टि हो जाती है. सवाल है कि एक कंपनी की डायरेक्टर होने के बावजूद उनकी स्थिति क्यों नहीं सुधरती? इसका जवाब जीविका दीदियों की मासिक आय से जुड़े उन आंकड़ों में दिखता है, जिसके मुताबिक राज्य की 65 फीसद जीविका दीदियां आज भी महीने के छह हजार रुपए कमाने के लिए संघर्ष कर रही हैं. सभाओं में उन्हें शोकेस की तरह पेश तो किया जा रहा है, पर उनका अपना संघर्ष आज भी जारी है. ■

हुआ मैं दीदि रखना''

ग्राफिकः चंद्रमोहन ज्योति

आत्मनिर्भर समूह

33 में से सिर्फ 7 कृषि उत्पाद कंपनियां आत्मनिर्भर हैं
सिर्फ **192** मॉडल क्लस्टर आत्मनिर्भर

राजनीतिक उपलब्धियां

मुखियाः **483**
पंचायत प्रतिनिधिः **21,549**

जीविका संस्थान का कार्यबल

आफिस स्टाफ की संख्याः **8,000**
कॉडरः **90,000**

जीविका पर विश्व बैंक का कुल लोनः
4,530 लाख डॉलर

जीविका दीदियों की आजीविका और आय

(प्रतिशत में)

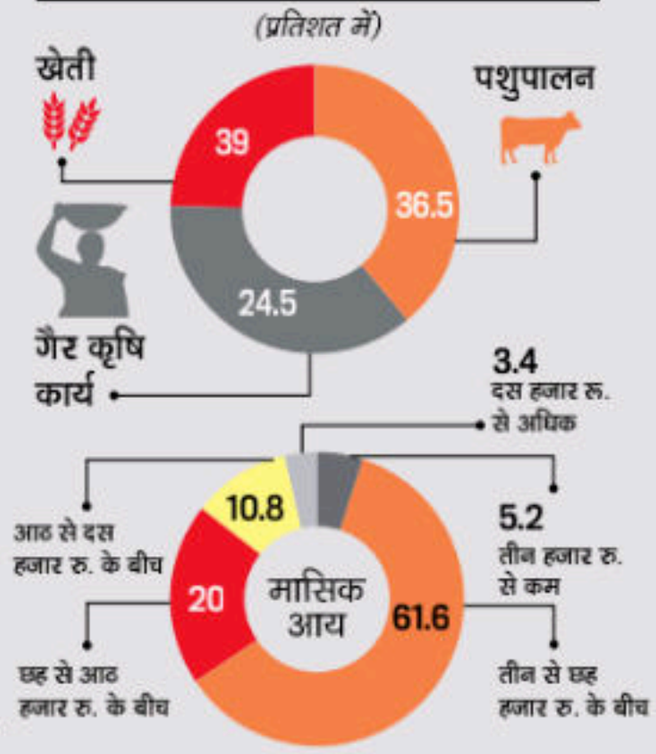

जीवन बदलने का ओड़िया मॉडल

ओडिशा सरकार की मिशन शक्ति योजना दूरदराज के इलाकों में लाखों महिलाओं को लैंगिक बाधाएं पार कर आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में मदद करके उनके जीवन को चुपचाप बदल रही है

रोमिता दत्ता, भुवनेश्वर और जगतसिंहपुर में

एक बहुत तंग कमरा जिसमें नाममात्र की रोशनी है, नारियल की जटाओं और रस्सियों से अटा पड़ा है. मशीन की आवाज में दूसरी सारी आवाजें दब रही हैं. फिर, जैसे-जैसे हमारी आंख खुद को इस अंधेरे के साथ समायोजित करती जाती है, हमें अपने काम में मशगूल 12 महिलाएं साफ-साफ नजर आने लगती हैं. कुछ रस्सियां बना रही हैं तो कुछ दूसरी चीजें तैयार कर रही हैं. उनकी फुर्तीली उंगलियां जटिल हस्तशिल्प को आकार दे रही हैं. 2006 में मुट्ठी भर सदस्यों के साथ इस उद्यम को शुरू करने वाली 45 वर्षीया कविता साहू आज एक सफल उद्यमी हैं. कभी निपट गरीबी में जीवन काटने वाली साहू आज कर्मचारियों को अच्छा वेतन देते हुए अपने लिए 40,000 रुपए प्रति महीने की कमाई कर रही हैं. कविता ओडिशा सरकार की मिशन शक्ति योजना की लाभार्थी हैं.

मिशन शक्ति महिला सशक्तिकरण की ऐसी पहल है जिसने दो दशकों में लाखों महिलाओं को स्वतंत्र रूप से आय का अवसर देकर उनके जीवन को बदल दिया है. ऐसे दौर में जब बहुत-से राज्य महिलाओं को वोटबैंक के रूप में लुभाने के लिए तरह-तरह की खैरात बांटते हैं, ओडिशा का मिशन शक्ति कार्यक्रम महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के रूप में महिला शक्ति को संगठित करता है जो इस कार्यक्रम की रीढ़ हैं. ये एसएचजी तरह-तरह के सामान बनाते हैं, और कई किस्म की सेवाएं मुहैया करते हैं. इसके लिए महिलाओं को विविध कौशल में प्रशिक्षित किया जाता है, सरकारी कर्ज दिया जाता है, इस कर्ज के भुगतान पर जोर दिया जाता है और भुगतान पर पुरस्कृत किया जाता है तथा व्यवसाय की गारंटी दी जाती है.

खेती-बाड़ी से संबंधित गतिविधियों और मछलीपालन से लेकर बैंकिंग संचालन तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की डीलरशिप तक, इन एसएचजी के संचालन का दायरा व्यापक है. ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के दिल के बहुत करीब इस योजना ने महिलाओं की उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को जगाया है और जमीनी स्तर पर उनकी प्रबंधकीय, विपणन और दूसरी ऐसी कई प्रतिभाओं को उजागर किया है जिनका अब तक इस्तेमाल ही नहीं हुआ था. ओडिशा के दूर-दराज के इलाकों में, महिलाओं ने पितृसत्ता की सबसे मोटी दीवार को भेद दिया है. कुल मिलाकर, इस योजना से 70 लाख महिलाएं (जनसंख्या का 15 प्रतिशत) लाभान्वित हुई हैं, जिससे उन्हें वित्तीय सुरक्षा के साथ जीवनयापन में मदद मिली है. अगर उनके परिवारों को होने वाले फायदों को शामिल कर लें तो मिशन शक्ति योजना ने 2.8 करोड़ लोगों को प्रभावित किया है जो कि ओडिशा की आधी आबादी है.

मिशन शक्ति से जुड़े एक वरिष्ठ सदस्य कहते हैं, ''हमारे मुख्यमंत्री का मानना है कि यदि पैसा महिलाओं के हाथ में जाए तो वे उसका कहीं अधिक उचित उपयोग कर लेती हैं. वे इसका परिवार और समाज के लिए उपयोग करते हुए इसमें से थोड़ा-बहुत भविष्य के लिए भी बचा लेती हैं.''

हालांकि इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी पर 2017 में महिला और बाल विकास विभाग के तहत मिशन शक्ति का विशेष निदेशालय बनाया गया. 2021 में एक समर्पित बजट के साथ मिशन शक्ति को एक स्वतंत्र विभाग बनाने का निर्णय लिया गया. 2,100 करोड़ रुपए के बजट और बढ़ी हुई शक्तियों के साथ, मिशन शक्ति महकमें को अब धन को संभालने और स्वतंत्र नीतियां बनाने की ताकत दी गई है. दूसरा कारण एसएचजी के दायरे का विस्तार करना था और उन्हें धीरे-धीरे एसएमई (लघु और मध्यम आकार के उद्यम) श्रेणी में शामिल करना था, ताकि उन्हें अपने संचालन का विस्तार करने में मदद मिल सके. इसके लिए स्वयं सहायता समूहों को ब्लॉक स्तरीय महासंघ बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जो बड़ी संस्थाओं के रूप में उनके लक्ष्य की ओर बढ़ा एक प्रमुख और सधा हुआ कदम है.

नया अवसर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भुवनेश्वर में एसएचजी सदस्यों के साथ

महिलाओं को शक्ति

- 2001 में शुरू हुए मिशन शक्ति को 2017 में महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के तहत एक निदेशालय बनाया गया
- 2021 में यह एक पूर्ण विभाग बन गया
- इसका बजट 2,000 करोड़ रुपए है
- 7 लाख एसएचजी, 70 लाख सदस्य
- मिशन शक्ति के तहत ब्लॉक फेडरेशन में औसतन 1,200 से 2,500 एसएचजी शामिल हैं
- मिशन शक्ति के तहत ऋण घटक–3 लाख रुपए से 61 लाख रुपए
- एसएचजी गतिविधियों में विविधता लाने के लिए यंत्रीकृत और तकनीकी कार्य को प्रोत्साहित किया जा रहा है. मोटे अनाज को भूनने, मिक्स करने और घरों में जाने वाले राशन की पैकेजिंग के लिए महिलाएं अब मशीनों का इस्तेमाल कर रही हैं
- नए क्षेत्र– फैशन डिजाइनिंग, परिधान बनाना और गैजेट्स की मरम्मत
- एसएचजी द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने के प्रयास हो रहे हैं

उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने के लिए 2.04 लाख रुपए के एकमुश्त अनुदान के साथ 50 सदस्यों के निर्माता समूह बनाए गए हैं. अच्छा प्रदर्शन करने वाले निर्माता समूह संगठित होकर और बड़ा प्लेटफॉर्म—निर्माता कंपनियां—बना सकते हैं, जिनकी बाजार क्षमता बहुत बड़ी हो सकती है. ओडिशा सरकार ऐसी हरेक कंपनी को अंततः छोटी या मध्यम इकाई के रूप में विकसित करने के लिए कई चरणों में 61.5 लाख रुपए दे रही है.

अर्थशास्त्री असित मोहंती कहते हैं, ''मिशन शक्ति महिलाओं को आपूर्तिकर्ता (उत्पादन बिंदु) से उपयोगकर्ता (उपभोग बिंदु) तक सभी आर्थिक गतिविधियों के संचालन में सक्षम बनाता है. इससे आपूर्ति श्रृंखला में सुधार होता है, और एसएचजी की भागीदारी से लेन-देन की लागत कम हो जाती है. ओडिशा में बैंकों से उधार की पैठ बहुत कम है. एसएचजी को मिलने वाले छोटे कर्ज इसमें सुधार करेंगे. इसलिए, ओडिशा में सक्रिय बैंकों को मिशन शक्ति को एक अवसर के रूप में लेना चाहिए.''

मिशन शक्ति समूहों की एक प्रमुख विशेषता उनके ऋण व्यवहार का अच्छा होना है. कर्ज के समय पर पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ब्याज अनुदान (ब्याज दरों में रियायत) देती है. वास्तव में, 3,00,000 रुपये तक के कर्ज के पुनर्भुगतान को सरकार शून्य ब्याज का पुरस्कार देती है. पिछले वित्त वर्ष में इस पर 162 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे; इस वर्ष एसएचजी के ब्याज अनुदान के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है. 6,22,000 एसएचजी में से अधिकांश नियमित रूप से और समय पर पुनर्भुगतान कर रहे हैं. देलंग ब्लॉक फेडरेशन की बसंती साहू कहती हैं, ''हमें अपने समूह को जीवित रखना है और इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने कर्ज का भुगतान करें. समूह हमारे लिए सब कुछ है क्योंकि इसने हमें अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत दी है, और हमारे लिए संभावनाओं की दुनिया के द्वार खोलता है.'' 10 गरीब महिलाओं की उनकी मूल टीम ने किसानों से धान और दूसरी कृषि उपज एकत्र की और शोषक बिचौलियों को दरकिनार करते हुए उसे खुद बाजार में बेचा. 2002 में, महिलाओं ने प्रति माह 2,500 रुपए कमाए. आज, बसंती महासंघ में काम करने वाली 80 महिलाओं में से हरेक को 7,000 से 12,000 रुपये के बीच मासिक वेतन मिलता है.

कृषि क्षेत्र में, मिशन शक्ति के तहत नकदी फसलें, सब्जियां, लेमनग्रास और मोटे अनाज उगाकर साल भर की आय सुनिश्चित की जा रही है. सब्जी के मौसम में एक आदिवासी परिवार की औसत आय 20,000-30,000 रुपए बढ़ी है. खेती के लिए अनुपयुक्त क्षेत्रों का उपयोग मत्स्य पालन के लिए किया जा रहा है. मिशन शक्ति की सचिव सुजाता कार्तिकेयन कहती हैं, ''हम महिलाओं को ऐसे कामों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं जिनका संचालन प्रौद्योगिकी से होता है. जब ये महिलाएं हमें बताती हैं कि लोग जब उन्हें 'मैडम' के रूप में संबोधित करते हैं तो वे खुद को कितना सम्मानित महसूस करती हैं, हमें बड़ी खुशी महसूस होती है.''

हालांकि, हर कोई मिशन शक्ति का प्रशंसक नहीं है. भाजपा के पूर्व प्रवक्ता सज्जन शर्मा कहते हैं, ''ये आंकड़े कागजों पर ही बहुत बड़े और आकर्षक नजर आते हैं. महिलाओं को कर्ज देकर वे उन्हें कर्ज के दलदल में धकेल रहे हैं. सरकार कर्ज के रूप में दी गई रकम को हर हाल में वसूलना सुनिश्चित करती है. अगर मिशन शक्ति जीवन बदलने वाली योजना है तो ओडिशा के 3.3 करोड़ लोग सब्सिडी के राशन पर निर्भर क्यों हैं?'' आलोचना के बावजूद, मिशन शक्ति योजना महिलाओं के बीच समर्थन और जुड़ाव के लिए एक उर्वर जमीन बनी हुई है. जब 33 वर्षीया ममता स्वैन ने एक सड़क दुर्घटना में अपने पति को खो दिया, तो वे मदद की आस में मिशन शक्ति के स्वयं सहायता समूहों के पास पहुंचीं. ममता कहती हैं, ''अगर मेरे मिशन शक्ति के दोस्त नहीं होते तो मैं सदमे से कभी उबर ही नहीं पाती.'' परिवार की एकमात्र कमाऊ सदस्य ममता आज बिजली की मीटर रीडिंग लेने का काम करते हुए हर महीने 9,000 रुपए कमाती हैं.

ममता ने जो काम चुना है उसे एक बड़ी सफलता माना जा रहा है. महिलाओं को बिजली की रीडिंग लेने, बिजली के बिल जमा करने और बिजली चोरी के मामले दर्ज करने के लिए प्रशिक्षित किए जाने के बाद बिजली विभाग ने इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और शुल्क संग्रह में वृद्धि पाई है.

कार्तिकेयन बताती हैं, ''जब एक मिशन शक्ति कार्यक्रम में सीएम ने दर्शकों में महिलाओं से पूछा कि क्या उन्हें नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है, तो 50 साल से ऊपर आयु की एक महिला ने उन्हें बताया कि इससे उन्हें एक पहचान मिली है. मिशन शक्ति नए ओडिशा की कहानी है, जो आकांक्षी, समावेशी और आधुनिक है.'' एक अन्य शीर्ष नौकरशाह उनसे सहमत हैं. उनका कहना है कि ओडिशा के उद्धार का मॉडल वास्तव में मुक्तिदायक है. यह घरों की दहलीज के भीतर तक सीमित रही महिलाओं को बंदिशों से आजाद कराता है और उन्हें उनके हुनर के आधार पर अपनी एक अलग पहचान देता है. लाखों लोगों के लिए यह किसी सामाजिक क्रांति से कम नहीं है.■

दुआ में याद रखना

"दुआ में याद रखना"

सब मिल गाएं सा रे गा

सारे गाएं' नाम से की गई पहल के जरिए शुभेंद्र और सस्किया राव चाहते हैं कि 'वंचित नौनिहालों और दूसरे तमाम बच्चों का शास्त्रीय संगीत से तआरुफ कराया जाए ताकि वे बड़े होकर संवेदनशील नागरिक बनें

रोमिता दत्ता

तमाम कलाओं की तरह संगीत का रियाज मन को तरोताजा करता है और पूरी तरह निखार देता है, तो उसके साज-बाजे जुनूनी शिष्यों में बांटने से कम आनंद नहीं मिलता. सितारवादक पंडित शुभेंद्र राव और उनकी चेलोवादक पत्नी मैस्ट्रो सस्किया राव-डे हास—ने इसी घोषित लक्ष्य या 'मिशन' से एक अनोखा काम हाथ में लिया. लेकिन उनका यह काम इससे भी कहीं आगे जाता है. उनकी यह असामान्य किस्म की आकांक्षा सचमुच चौंकाने वाली है—आज के जमाने में कौन भला यह सोचेगा कि संगीत और वह भी शास्त्रीय संगीत ''बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार'' है? या बच्चों के लिए संगीत की ऐसी सहज-सरल किताबों की परिकल्पना करेगा जो उन्हें सचित्र कहानियों के जरिए ताल, स्वर और बाद में राग सरीखी बुनियादी बातें सिखाएं? शुभेंद्र और सस्किया राव फाउंडेशन की पहल 'सारे गाएं' संगीत को एक स्वस्थ खुराक मानती है, एक ऐसी खुराक जो ''सुकून के साथ आपस में गुफ्तगूं करने, बौद्धिक स्तर बढ़ाने और बच्चों में छिपी संभावनाएं सामने लाने में'' मदद करे.

शुभेंद्र-सस्किया दंपती ने सचित्र कहानियों की किताबों के जरिए संगीत के सबक सिखाने की बात सोची, ताकि एक कोने में बैठकर उन पर नजरें दौड़ाते हुए कोई बच्चा मन ही मन गुनगुनाते हुए संगीत की समझ हासिल करे. फाउंडेशन का मकसद ऐसे बच्चों

साथ-साथ स्वर ओडिशा के कलिंगनगर में 2014 में सारे गाएं प्रोजेक्ट की शुरुआत के दौरान सस्किया और शुभेंद्र राव (बाएं से छठे और सातवें) दूसरे कलाकारों के साथ

सारे गाएं
स्थापना: 2014
ओडिशा

और लोगों के बीच भारतीय शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देना है जिन्हें वह आसानी से सुलभ नहीं है, और इस तरह लोगों को उसकी लय, ताल और संगति के बारे में सचेत और जागरूक बनाना है. नाम सारे गाएं के पहले तीन अक्षरों—सा रे गा—का अर्थ क्रमश: 'संग चले', 'रिश्ता जोड़ें' और 'गीत गाएं सुर में' भी है.

राव दंपती ने 2014 में संगीत शिक्षा का कार्यक्रम म्यूजिक फॉर ऑल शुरू किया था. यह संगीत को पाठ्यक्रम के अलग एक विषय के तौर पर नहीं बल्कि बेहतर ढंग से स्कूल के सामान्य पाठ्यक्रम के हिस्से के तौर पर शुरू करने की पहल थी. उसी साल उन्होंने सारे गाएं की भी शुरुआत की. इस पहल ने ग्रामीण और आदिवासी इलाकों के साधनहीन बच्चों को उन्हें विरासत में मिली संगीत की समृद्ध परंपराओं से जोड़ने की कोशिश की. टाटा स्टील फाउंडेशन और एस्पायर एनजीओ भी देशज समूहों के भीतर ही सीमित लोक संगीत को जिंदा करने की इस कोशिश से जुड़ गए.

राव दंपती ने हाल ही 23 जनवरी को ओडिशा के आदिवासी केंद्र स्थल कलिंगनगर में 500 बच्चों के साथ बातचीत की. उन बच्चों को संगीत के पाठ सिखाने के अलावा उन्होंने यहां खुद भी स्थानीय कलाओं के बारे में सीखा. इससे पहले जाजपुर जिले में हो आदिवासियों के गांव मिरिगिचरा की यात्रा के दौरान वे थाप के साथ बजाए जाने वाले मांदर और नगाड़े जैसे साजों के इस्तेमाल और गांववालों की अनूठी गायन शैली की गहरी छाप लेकर लौटे. राव कहते हैं, ''लोक संगीत रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है. यह मौसम, फसल कटाई से जुड़े त्यौहारों और शादियों में गाया जाता है. हमारा उद्देश्य इसे मुख्यधारा में लाना है. राजस्थान के मांगणियार और लंगा समुदायों के लोकगीत इसीलिए लोकप्रिय हैं क्योंकि वे मुख्यधारा में ले आए गए.''

खुशी के सूत्र

''जब मैं बच्चों की आंखें खुशी से चमकते देखता हूं तो मुझे लगता है, ये अमूल्य हैं. इनकी कोई कीमत नहीं''

पंडित शुभेंद्र राव
सितारवादक

'दुआ में याद रखना'

राव दंपती इन दिनों टाटा स्टील की 1,000 स्कूल परियोजना से जुड़े हैं, जिसका मकसद ओडिशा के सरकारी स्कूलों की पढ़ाई-लिखाई में सुधार लाना है. इसके जरिए राव दंपती साधनहीन आदिवासी बच्चों को संगीत के अपने पाठ्यक्रमों में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. राव कहते हैं, ''यह उन्हें समझने के लिए है और उनके भीतर छिपी उस सांस्कृतिक संपदा के बारे में उन्हें समझाने के लिए है जिसका इस्तेमाल समुदाय के निर्माण में किया जा सकता है.'' उनके शब्दों में, ''हम समझते हैं कि बच्चा जितनी जल्दी संगीत की पढ़ाई शुरू कर दे, उतना अच्छा. संगीत मस्तिष्क के विकास में भी मदद करता है. कहते हैं कि 'संगीत वहां से शुरू होता है जहां शब्द खत्म हो जाते हैं', हम लोगों को इसी का अहसास करवाने में जुटे हैं.'' राव कहते हैं कि इस शुरुआती दीक्षा में मदद के लिए संगीत की किताबें तभी उनके हाथों में देनी होती हैं जब बच्चे पांच-छह साल के होते हैं, जब उन्होंने पढ़ना-लिखना सीखा ही होता है.

सस्किया संगीत पर छह किताबें लिख चुकी हैं. इन्हें बच्चे कहानियों की किताबों की तरह पढ़ सकते हैं. ये शिक्षकों के लिए लेसन प्लान का काम भी करती हैं. जरा सोचिए, बच्चे के लिए उस नन्हीं तारा की कहानी के जरिए राग और ताल के बारे में पढ़ना कितना दिलचस्प होगा, जो अपने दोस्तों गट्टू घटम, तबला ट्विंस और सुरी बांसुरी के साथ रहती है. एक और किताब बच्चों को तस्वीरों से भरे कुल 100 पन्नों में ईसा पूर्व 5000 से 2022 तक के भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास से मिलवाती है.

टाटा स्टील फाउंडेशन और सारे गाएं के रेसिडेंशियल ब्रिज कोर्स में उनकी योजना ओडिशा के छह आदिवासी प्रखंडों के 2,700 बच्चों के लिए तीन महीनों की एक पायलट परियोजना शुरू करना भी है. बच्चों के अलावा उनके माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी और गांव के दूसरे वयस्क भी संगीत की कक्षाओं में आ रहे हैं. इरादा उन्हें सभाओं और उत्सवों में प्रार्थना गाने से जोड़ना है क्योंकि संगीत आपस में रिश्ते जोड़ने और समुदाय के निर्माण में मदद करता है.

सारे गाएं का मकसद संगीत के जरिए लोगों को ताकतवर बनाना है. राव दंपती ने कई महिलाओं को इस तरह सिखाया कि वे अब दूसरों को सिखा सकती हैं. सस्किया महिलाओं को दिल्ली के निजामुद्दीन में सिखाएंगी. दोनों कहते हैं, ''हम संगीत की पृष्ठभूमि वाली ऐसी महिलाओं को चुनते हैं जिन्हें करियर बनाने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिला. उनकी छिपी हुई प्रतिभा को सामने लाने में मदद करते हैं ताकि वे धीरे-धीरे इस शिक्षा का पेशेवर ढंग से इस्तेमाल कर सकें. उनको ताकतवर बनाने का यही हमारा मॉडल है.''

शुभेंद्र और सस्किया को लगता है कि अपनी दिनचर्या में संगीत को शामिल करना इस कानफाड़ू दुनिया को दूर रखने में मदद कर सकता है. बेहतर और अधिक खुश भारतीयों की पीढ़ी तैयार करने की उनकी कोशिश सचमुच अनुकरणीय है. उनके कार्यक्रमों में हजारों बच्चे विनम्र और संवेदनशील नागरिक के रूप में विकसित हो रहे हैं, जिसके लिए वे राव दंपती के शुक्रगुजार होंगे.■

सवाल+जवाब

'दबंग' से सीखने की सलाह मिली

डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर और ऐक्टर अनुराग कश्यप से उनके करियर, आने वाली फिल्मों और शाहरुख खान के बारे में

● आपकी फिल्मों पर पिता की राय

पिताजी को पहले मेरी फिल्में समझ नहीं आती थीं. *गुलाल* उन्हें थोड़ी समझ आई, बाद में *मुक्काबाज* अच्छे से समझे. *गैंग्स ऑफ वासेपुर* देखकर कहा बेटा, गाली-गलौच ज्यादा था. मेरे भाई ने *दबंग* बनाई थी, तब पिताजी ने कहा, ये होती है फिल्म, कुछ सीखो.

● आने वाली फिल्में

अभी तो 'ऑलमोस्ट प्यार विथ डीजे मोहब्बत' आई है. एक और आने वाली है. उसका नाम अभी गुप्त रख रहा हूं. मैं चाहता हूं कि वह फिल्म आए, तब लोग हैरान हों. एक फिल्म सुकेतु मेहता के उपन्यास 'मैक्सिमम सिटी' पर बनेगी, जिसे लिख लिया है.

● वह फिल्म जिसने फिल्मों की ओर मोड़ा

मैंने 1992 में एक जापानी फिल्म देखी थी *ए फ्यूजिटिव फ्रॉम द पास्ट*. इस फिल्म ने मुझ पर गहरा असर छोड़ा. मैंने कहा, यार ये करना है. इसके बाद ही मैंने जन नाट्य मंच जॉइन किया. तब कल्चरल सेंटर में जो भी फिल्में आती थीं, हम देखने जाते थे.

● नाना पाटेकर के बारे में

मैं नाना पाटेकर और एन चंद्रा का बहुत बड़ा फैन था. *अंकुश*, *प्रतिघात* और *तेज़ाब*, इन तीन फिल्मों ने मुझे बहुत प्रभावित किया. और बाद में *परिंदा* ने भी. मैं नाना पाटेकर से मिलने दो-तीन बार गया भी हूं. वो मुझे प्यार से हज्जाम बुलाते हैं.

● शाहरुख खान के साथ फिल्म करने के बारे में

शाहरुख के लिए मेरे पास पचास स्क्रिप्ट होंगी लेकिन उनका मन होना चाहिए करने का. और उनके साथ जो जिम्मेदारी आती है, वो मैं नहीं उठा सकता. उनके फैन बेस को केटर करना बड़ी जिम्मेदारी है.

— सौरभ द्विवेदी

गेट्टी इमेजिस

दुआ में याद रखना

BHARATBENZ

THE BEST JUST GOT BETTER.

INTRODUCING

THE NEW 320HP TRUCKS

Engineered for maximum performance and endurance.

DRIVER STATE MONITORING | Lower Maintenance Cost | Higher Uptime | Higher Productivity | Higher Fuel Efficiency | TRUCKONNECT

BHARATBENZ1 BHARATBENZ1 BHARATBENZTRUCKS1

www.bharatbenz.com
Email: sales_dicv@daimler.com

IndiaContent

SEARCH FOR EDITORIAL IMAGES ENDS HERE
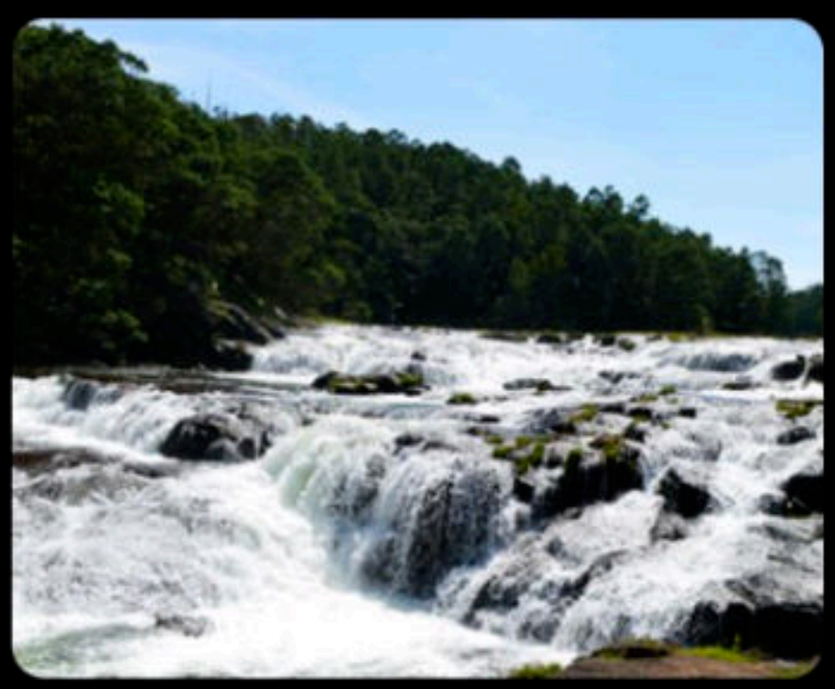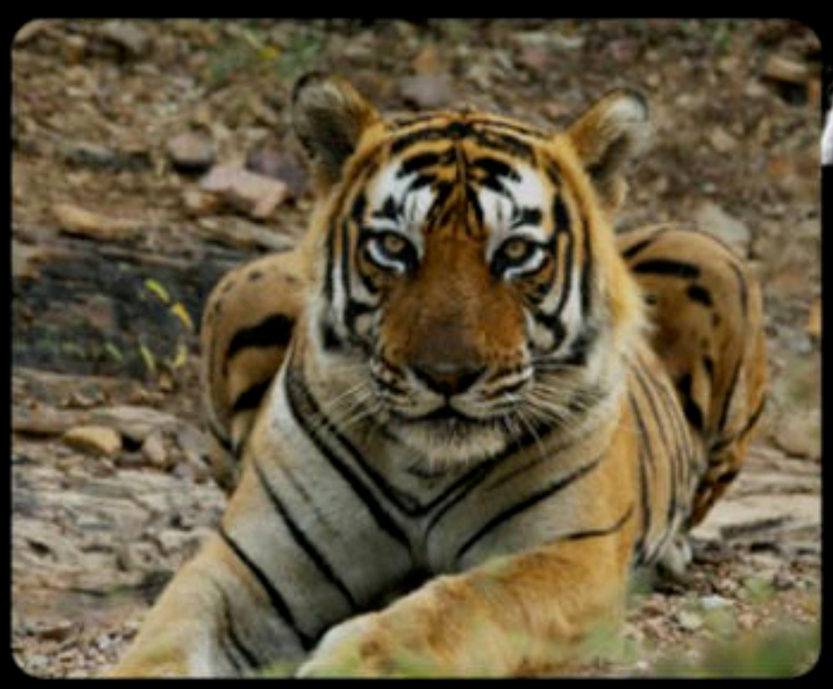
"दुआ संवाद रखना"